सम्पादकीय

सलाखों पर सवाल, सिसोदिया के सत्रह महीनों का हिसाब कौन देगा, कोर्ट ने माना है जमानत नियम है और जेल अपवाद

आखिरकार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं, पर अदालतों को एक बार फिर नसीहत दी है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। किसी की जमानत सजा के तौर पर नहीं टाली जानी चाहिए। हालांकि यह बात सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कई बार कह चुका है, मगर निचली अदालतें इसे गंभीरता से लेती नजर नहीं आतीं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में पहले प्रवर्तन निदेशालय और फिर सीबीआइ ने जेल में बंद कराया था। सिसोदिया निचली अदालत से उच्च न्यायालय के बीच अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते और जमानत की अपील करते रहे, मगर किन्हीं तकनीकी कारणों से उन्हें सलाखों के पीछे ही रहने पर मजबूर होना पड़ा। करीब सत्रह महीने उन्होंने जेल में बिताए। जाहिर है, उनकी जमानत से आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल है। मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि जब एक निर्वाचित सरकार के जिम्मेदार पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति को इतने लंबे समय तक जेल में रहने पर मजबूर होना पड़ता है, तो सामान्य नागरिक के बारे में क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सवाल बेवजह नहीं उठ रहे हैं कि आखिर सिसोदिया के सत्रह महीनों का हिसाब कौन देगा। सिसोदिया अकेले ऐसे नेता नहीं हैं, जिन्हें इस तरह सीखचों के पीछे लंबा वक्त गुजारना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में रह चुके हैं। सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक जमानत की आस लगाए हुए हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों के कामकाज पर गहरे सवाल उठे हैं। दिल्ली आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सेना की जमीन खरीद घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन की जांच एजेंसियों ने बिना पुख्ता आधार और दोषसिद्धि के लंबे समय तक जेल में डाले रखा। इसमें निचली अदालतों ने भी गंभीरता से विचार नहीं किया कि इस तरह जिम्मेदार पदों का निर्वाह करने वालों को जेलों में डालने से आखिरकार सार्वजनिक महत्व के कामकाज बाधित होते हैं।

किसी को जमानत देने का यह अर्थ कतई नहीं होता कि उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच तो चलती रह सकती है और दोषसिद्धि पर उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इस तरह केवल आरोप और आशंका के आधार पर लोगों को लंबे समय तक जेलों में बंद रखना एक तरह से नाहक सजा देने के बराबर ही माना जाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की नसीहत पर गंभीरता से पालन के अपेक्षा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसने के नाम पर जिस तरह अंधाधुंध छापे मारे और गिरफ्तारियां की, उसे लेकर उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे सत्तापक्ष के इशारे पर, उसकी राजनीतिक मंशा के अनुरूप काम करती हैं। वे जानबूझ कर तकनीकी अड़चनें पैदा कर अदालत को जमानत देने से रोकने का प्रयास करती देखी जाती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष

युवा क्रांति के साथ शांति के नये छंद रचें

स्वामी विवेकानन्द ने भारत के नवनिर्माण के लिये मात्र सौ युवकों की अपेक्षा की थी। क्योंकि वे जानते थे कि युवा 'विजनरी' होते हैं और उनका विजन दूरगामी एवं बुनियादी होता है। उनमें नव निर्माण करने की क्षमता होती है। नया भारत निर्मित करते हुए नरेन्द्र मोदी को भी युवाशक्ति को आगे लाना होगा। युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य हैं। वो देश की नींव हैं, जिस पर देश की प्रगति और विकास निर्भर करता है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, जहाँ नौजवान ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है तो कहीं प्रछन्न बेरोजगारी जैसे हालात हैं। युवा अनेक विसंगतियों एवं बुराइयों से घिरे हैं।

ललित गर्ग

युवा क्रांति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, इस क्रांति एवं ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक हो, इसी ध्येय से सारी दुनिया प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाती है। सन् 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आरम्भ किया गया था। यह दिवस मनाने का मतलब है कि युवाशक्ति का उपयोग विध्वंस में न होकर निर्माण में हो। युवा, शांति और सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2250 (9 दिसंबर 2015) शांति को बढ़ावा देने और उग्रवाद का मुकाबला करने में युवा शांति निर्माताओं को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता की अभूतपूर्व स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है, और स्पष्ट रूप से युवाओं को वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थान देता है। पूरी दुनिया की सरकारें युवा के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। न केवल सरकारें बल्कि आम-जनजीवन में भी युवकों की स्थिति, उनके सपने, उनका जीवन लक्ष्य आदि पर चर्चाएं हो। युवाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं मूलभूत बातों को लेकर यह दिवस मनाया जाता है।

विश्व की गम्भीर समस्याओं में प्रमुख है नशीले पदार्थों का उत्पादन, तस्करी और सेवन की निरंतर हो रही वृद्धि। युवापीढ़ी इस जाल में बुरी तरह कैद हो चुकी है। आज हर तीसरा युवक किसी न किसी नशे का आदी हो चुका है। अगर यही प्रवृत्ति रही तो सरकार, सेना और समाज के ऊंचे पदों के लिए शरीर और दिमाग से स्वस्थ युवा नहीं मिलेंगे। एक नशेड़ी पीढ़ी का देश कैसे अपना पूर्व गौरव प्राप्त कर सकेगा? इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत एवं आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। युवा सपनों को आकार देने का अर्थ है सम्पूर्ण मानव जाति के उन्नत भविष्य का निर्माण। यह सच है कि हर दिन के साथ जीवन का एक नया लिफाफा खुलता है, नए अस्तित्व के साथ, नए अर्थ की शुरुआत के साथ, नयी जीवन दिशाओं के साथ। हर नई आंख देखती है इस संसार को अपनी ताजगी भरी नजरों से। इनमें जो सपने उगते हैं इन्हीं में नये समाज की, नयी आदमी की नींव रखी जाती है। यौवन को प्राप्त करना जीवन का सौभाग्य है। जीने की तीन अवस्थाएं बचपन, यौवन एवं बुढ़ापा हैं, सभी युवावस्था के दौर से गुजरते हैं, लेकिन जिनमें युवकत्व नहीं होता, उनका यौवन व्यर्थ है। उनके निस्तेज चेहरे, चेतना-शून्य उच्छ्वास एवं निराश सोच मात्र ही उस यौवन की साक्षी बनते हैं, जिसके कारण न तो वे अपने लिये कुछ कर पाते हैं और न समाज एवं राष्ट्र को ही कुछ दे पाते हैं। वे इतना सतही जीवन जीते हैं कि व्यक्तिगत स्पर्द्धाओं एवं महत्वाकांक्षाओं में उलझकर अपने ध्येय को विस्मृत कर देते हैं। उनका यौवन कार्यकारी तो होता ही नहीं, खतरनाक प्रमाणित हो जाता है। युवाशक्ति जितनी विराट् और उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी है। इस परिप्रेक्ष्य में युवाशक्ति का रचनात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग करने की जरूरत है। गांधीजी से एक बार पूछा गया कि उनके मन की आश्वस्ति और निराशा का आधार क्या है? गांधीजी बोले- 'इस देश की मिट्टी में अध्यात्म के कण हैं, यह मेरे लिये सबसे बड़ा आश्वासन है। पर इस देश की युवापीढ़ी के मन में करुणा का स्रोत सूख रहा है, यह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है।' गांधीजी की यह चिन्ता सार्थक थी। मूल प्रश्न है कि क्या हमारे आज के नौजवान भारत को एक सक्षम देश बनाने का स्वप्न देखते हैं? या कि हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी केवल उपभोक्तावादी संस्कृति से जन्मी आत्मकेन्द्रित पीढ़ी है? दोनों में से सच क्या है? दरअसल हमारी युवा पीढ़ी महज स्वप्नजीवी पीढ़ी नहीं है, वह रोज यथार्थ से जूझती है, उसके सामने भ्रष्टाचार, आरक्षण का बिगड़ता स्वरूप, महंगी होती जाती शिक्षा, कैरियर की चुनौती और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को कुचलने की राजनीति विसंगतियां जैसी तमाम विषमताओं और अवरोधों की ढेरों समस्याएं भी हैं। उनके पास कोरे स्वप्न ही नहीं, बल्कि आंखों में किरकिराता सच भी है। इन जटिल स्थितियों से लौहा लेने की ताकत युवक में ही हैं। क्योंकि युवक शब्द क्रांति का प्रतीक है। विचारों के नभ पर कल्पना के इन्द्रधनुष टांगने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, बेहतर जिंदगी जीने के लिए मनुष्य को संघर्ष आमंत्रित करना होगा। वह संघर्ष होगा विश्व के सार्वभौम मूल्यों और मानदंडों को बदलने के लिए। सत्ता, संपदा, धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य का जो मूल्यांकन हो रहा है मानव जाति के हित में नहीं है। दूसरा भी तो कोई पैमाना होगा, मनुष्य के अंकन का, पर उसे काम में नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि उसमें अहं को पोषण देने की सुविधा नहीं है। क्योंकि वह रास्ता जोखिम भरा है। क्योंकि उस रास्ते में व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यामोह की सुरक्षा नहीं है। युवापीढ़ी पर यह दायित्व है कि संघर्ष को आमंत्रित करे, मूल्यांकन का पैमाना बदले, अहं को तोड़े, जोखिम का स्वागत करे, स्वार्थ और व्यामोह से ऊपर उठे। युवा दिवस मनाने का मतलब है-एक दिन युवकों के नाम। इस दिन पूरे विश्व में युवापीढ़ी के संदर्भ में चर्चा होगी, उसके ह्रास और विकास पर चिंतन होगा, उसकी समस्याओं पर विचार होगा और ऐसे रास्ते खोजे जायेंगे, जो इस पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य दे सकें। इसका सबसे पहला लाभ तो यही है कि संसार भर में एक वातावरण बन रहा है युवापीढ़ी को अधिक सक्षम और तेजस्वी बनाने के लिए। युवकों से संबंधित संस्थाओं को सचेत और सावधान करना होगा और कोई ऐसा सकारात्मक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहे। विशेषतः राजनीति में युवकों की सकारात्मक एवं सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। अनील टायनबी ने अपनी पुस्तक 'सरवाइविंग द फ्यूचर' में नवजवानों को सलाह देते हुए लिखा है 'मरते दम तक जवानी के जोश को कायम रखना।' उनको यह इसलिये कहना पड़ा क्योंकि जो जोश उनमें भरा जाता है, यौवन के परिपक्व होते ही उन चीजों को भावुकता या जवानी का जोश कहकर भूलने लगते हैं। वे नीति विरोधी काम करने लगते है, गलत और विध्वंसकारी दिशाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिये युवकों के लिये जरूरी है कि वे जोश के साथ होश कायम रखे। इसीलिये सुकरात को भी नवयुवकों का दिमाग पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि नवयुवकों का दिमाग उपजाऊ जमीन की तरह होता है। उन्नत विचारों का जो बीज बो दें तो वही उग आता है। एथेंस के शासकों को सुकरात का इसलिए भय था कि वह नवयुवकों के दिमाग में अच्छे विचारों के बीज बोने की क्षमता रखता था। आज की युवापीढ़ी में उर्वर दिमागों की कमी नहीं है मगर उनके दिलो दिमाग में विचारों के बीज पल्लवित कराने वाले स्वामी विवेकानन्द और सुकरात जैसे लोग दिनोंदिन घटते जा रहे हैं। कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे कितने लोग हैं, जो नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं? हेनरी मिलर ने एक बार कहा था- ''मैं जमीन से उगने वाले हर तिनके को नमन करता हूं। इसी प्रकार मुझे हर नवयुवक में वट वृक्ष बनने की क्षमता नजर आती है।''

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कोई विशेष लाभ वो पूरा करेगे जब आप यह समझ पाते है कि आपके लक्ष्य के लिये कौनसे क्षेत्र है, जब आपके सितारे बुलंद होंगे और दुनियाँ तरक्की, आपकी दिल बाली से लाजवाब लगा दहेगा। हम ने सिर्फ हमारे पाठक में और महीन सूत्रों को सुलझाने तथा लाजवाब उन्नति की समझ होगी, धीमा पहलुसिद्ध संभोग में हो, जब हम लाजवाबता हमें लाइ और कामीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है। परिजनों तथा मित्रों के साथ अच्छे पलों को गुजारेंगे। किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है।

वृष
परिजनों के साथ कोई विवाद हो सकता है। आपका आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। दिन की शुरुआत में स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। आपकी रचनात्मकता से आप कठिन काम भी आसानी से बना पाएंगे।

मिथुन
आपको काम पूरा होने का उत्साह बना रहेगा। परिवार का वातावरण भी परिवर्तित होगा। आर्थिक लाभ भी भी संभावना है। आज का दिन पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ का अवसर लाया है। किसी प्रिय पात्र से मुलाकात होगी।

कर्क
परिजनों के साथ सम्बंध मधुर होंगे। हेल्थ आज अच्छी रहेगी। हालांकि बाहर खाने-पीने से बचें। दोपहर के बाद अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। अव्यस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ होगा। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना है। साथी कर्मचारी आपका सहयोग देंगे।

सिंह
किसी प्रिय मित्र या रिश्तेदार से बातचीत करके मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। सुबह के समय आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मन से खुश रहेंगे। परिजनों और मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

कन्या
आज नए काम का आरंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अधिक कार्य से आलस्य और मानसिक चिंता का अनुभव करेंगे। यात्रा आज लाभदायी नहीं है, परंतु दोपहर के बाद आपको कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। धार्मिक काम होंगे। मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे।

तुला
संतान की ओर से भी अच्छे समाचार मिलेंगे। किसी मीटिंग के लिए छोटी यात्रा हो सकती है। नए काम शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा।

वृश्चिक
गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। किसी छोटी यात्रा का आयोजन कर पाएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेंगे। परिश्रम की अपेक्षा फल कम मिलेगा।

धनु
विदेश जाने के इच्छुक लोग आज सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। दोपहर के बाद नया काम या टारगेट मिल सकता है। कोई अधूरा काम आज पूरा हो सकेगा। व्यापार में बढ़ोत्तरी की संभावना हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी।

मकर
दिन की शुरुआत में आप थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे। आज आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दें। वाणी मधुर बनाए रखें, इससे कोई भी काम आसानी से बना पाएंगे, हालांकि किसी तरह के नए काम आज शुरू ना करें।

कुंभ
कार्यालय या व्यवसाय में काम अधूरा रहने से मन निराश रहेगा। यात्रा में विघ्न आ सकता है। आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि आप के काम योजनानुसार पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। धन लाभ की संभावना हैं।

मीन
आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी है। आज आप चिंता से घिरे रहेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में भी किसी से मतभेद रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद आप सभी कामों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। काम का उत्साह बना रहेगा।

शख्सियत

जीते जी हम किसी के काम आ सके तभी कंधों की अहमीयत है,वरना मरने के बाद कंधे लगाने हम परम्परा है उसका पुण्य से कोई लेना देना नहीं.....

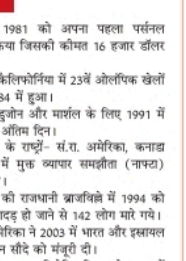

जुगनू
(युवा समाजसेवी)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं एक ऐसे युवा जब कोई कूँए में गिर जाता है तो उसी को याद किया जाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना जुगनू कुँए में उतर कर जानवर या मनुष्य सभी को बचाने में अपनी जान झौंक देते हैं। जी हां मैं बात कर रहा हू वाल्मिकी समाज के इस होनहार युवा की तो आज राजगढ़ क्षेत्र में हीरो बन चुका है। जुगनू तमोली का जन्म 19 दिसम्बर सन 1980 को मुंबई में हुआ उनका बचपन वही मुंबई में रहा। बेटा जब 5वीं कक्षा में था तो यहां राजगढ़ अपने माता-पिता के पास आ गए। यहां राजगढ़ में रह कर समाजसेवा की उसके बाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। जुगनू तमोली का जीवों के प्रति विशेष सेवा भाव है उनकी सेवा करना और जख्मी हो जाने पे उनकी मरहम पट्टी करना, उन्हें कूँए नालो में से निकालकर बचाना इनके बेहतरीन इंसानियत और व्यक्तिव का एक हिस्सा हैं। सैकड़ों जानवरों गायों व बैलों सहित छोटे जानवरों को कूँए से निकाले जाने का जोखिम पूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया है। अनेक गले सड़े शवों को भी कुएँ से निकाल के अपनी सेवा भावना का परिचय दिया। जुगनू ने आज तक 100 से ऊपर के लोगो को अपनी जान की परवाह न करते हुए कूँए से रेस्क्यू किया है। जिनसे कुछ तो जिंदा भी निकल आए हैं। राजगढ़ क्या आस-पास के इलाको में जब भी कोई कुंए में गिर जाता है तो सभी को एक ही नाम याद आता है जुगनू भाई को बुलाओ। जुगनू को कलेक्टर के द्वारा और डीआइजी के द्वारे उनके सेवा भाव और बहादुरी के लिए सम्मान दिया जा चुका है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जय हिन्द

आज का इतिहास

12 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- बादशाह अकबर के मंत्री अबुल फजल की 1602 में हत्या हुई।
- मुगल शासक ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। इसे राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
- नीदरलैंड और बेल्जियम ने 1831 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना 1833 में हुई।
- हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने 1908 में पहला कार मॉडल बनाया।
- फ्रांस और ब्रिटेन ने 1914 में ऑस्ट्रिया-हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- पोलैंड और रूस के बीच वारसॉ की लड़ाई 1920 को शुरू हुई।
- एम्सटर्डम में नौवें ओलम्पिक खेल 1928 को समाप्त हुये।
- क्यूबा का तानाशाह मचाडो वाई मोरालेस सैन्य तख्तापलट के बाद 1933 में भागा।
- गोताखोर माजोरी गेस्ट्रींग सबसे कम उम्र (13 वर्ष 268 दिन) के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 1936 में बने।
- फ्रेंच मार्शल हेनरी पीटेन ने 1941 में नाजी जर्मनी को पूर्ण समर्थन दिया।
- यूनान के लोनियन द्वीप में 1953 को भूकंप से 435 लोगों की जानें गई।
- नासा ने 1960 में अपना पहला सफल संचार उपग्रह ईको-ए प्रक्षेपित किया।
- पहली बार 1962 में एक साथ दो लोग अंतरिक्ष में गए।
- सीरिया ने 1971 में जॉर्डन से राजनयिक संबंध तोड़ा।
- इयान और ग्रेग चैपल ने 1972 में क्रिकेट टेस्ट मैच की एक ही पारी में शतक बनाया।
- आईबीएम ने 1981 को अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया जिसकी कीमत 16 हजार डॉलर रखी गई थी।
- लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में 23वें ओलंपिक खेलों का समापन 1984 में हुआ।
- विव रिचर्ड्स, डुजोन और मार्शल के लिए 1991 में टेस्ट क्रिकेट में अंतिम दिन।
- उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों- सं.रा. अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको में मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) 1992 में सम्पन्न।
- कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजविले में 1994 को एक चर्च में भगदड़ हो जाने से 142 लोग मारे गये।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में भारत और इस्रायल के बीच फाल्कन सौदे को मंजूरी दी।
- फ्रांस के मशहूर स्ट्राइकर जिनेदिन जिदान ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल से सन्यास लिया। इराकी शहर नजफ पर अमेरिकी हमले में 165 मारे गये।
- यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन-5 ने 2006 में जापान के संचार उपग्रह और फ्रांस के एक सैन्य उपकरण को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान एण्डेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचे यात्रियों ने 2007 को स्टेशन पर नई बीम लगाई।
- आमिर खान को उनकी फिल्म 'तारे ज़मीं पर' के लिए गोलापुड़ी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड 2008 में प्रदान किया गया।
- भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी.रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष 2009 को नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर अपनी नियुक्ति के उपरान्त राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

विशेष आलेख

बांग्लादेश में तख्तापलट इससे राहुल गांधी का क्या संबंध

रामस्वरूप रावतसरे

भारत की प्रमुख विपक्ष दल कॉन्ग्रेस के नेता राहुल गाँधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गाँधी और तारिक रहमान पर यह आरोप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। बांग्लादेशी समाचार पत्र 'ब्लिट्ज़' के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने 10 अगस्त 2024 को रिपब्लिक टीवी के एक शो में यह दावा किया। चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा कि लंदन में हुई यह गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।

सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ हुई उस बैठक में राहुल गाँधी ने इस बात के लिए अपनी सहमति दी, जो आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। यानी शेख हसीना को हटाने के लिए दोनों के बीच सहमति बनी। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने आगे कहा, बांग्लादेश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है।बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे पर भाजपा ने कॉन्ग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, यह गंभीर मामला है। बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। भाजपा नेता सरदार आरपी सिंह ने भी राहुल गाँधी से सवाल किया है। सरदार आरपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, राहुल गाँधी को लंदन में बीएनपी के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्तापलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? यह जानकारी बांग्लादेश में बैठे ब्लिट्ज के संपादक सलाउद्दीन चौधरी ने साझा की है। तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1967 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका हुआ है। वह बांग्लादेश की पहली महिला पीएम रहीं खालिदा जिया और बांग्लादेश के 7वें राष्ट्रपति रहे ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं। उनकी माँ खालिदा जिया इसके पहले वाली सरकार में एक राजनीतिक कैदी थीं। हाल ही में बांग्लादेशी सेना द्वारा देश तख्तापलट करने के बाद वह जेल से रिहा हुई हैं। रहमान ने अपना राजनीतिक जीवन 1988 में बीएनपी के प्राथमिक सदस्य के रूप में शुरू किया। उन्होंने 1991 में राष्ट्रीय चुनावों के दौरान अपनी माँ के लिए प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1996-2001 के दौरान जब अवामी लीग सत्ता में थी, रहमान ने हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय की आड़ में सरकार के खिलाफ सक्रिय रूप से आंदोलन चलाया। यूनाइटेड किंगडम में निर्वासित जीवन बिताने वाले तारिक रहमान 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड फेंकने के मास्टरमाइंड है। इसमें शेख हसीना को निशाना बनाने के लिए सैन्य-ग्रेड आर्गेस ग्रेनेड से हमला किया गया था। हमले में महिला अवामी लीग की अध्यक्ष और दिवंगत राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की पत्नी इवी रहमान सहित 24 नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। इस हमले के लिए तारिक रहमान को अदालत ने 10 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 11 सितंबर 2008 को रहमान इलाज का बहाना बनाकर लंदन भाग गए। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक लिखित बॉन्ड दिया था कि वह भविष्य में राजनीति में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद उन्हें लंदन जाने की अनुमति दी गई थी। खालिदा जिया ने दावा किया कि बांग्लादेश लौटने के बाद उनका बेटा सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेगा। हालांकि, लंदन से ही तारिक शेख हसीना सरकार के खिलाफ काम करने लगे। इसके बाद तारिक को सजा होने के बाद शेख हसीना सरकार ब्रिटेन की सरकार पर तारिक के प्रत्यर्पण के लिए लगातार दबाव डाल रही थी। हालाँकि, वह इसमें सफल नहीं हुई।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीपुरा रोड़ खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा चंदना"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन न.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन न.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार"

कल्पमेधा

अहंभाव से दिया गया दान दीनता और विषमता पोसने और बढ़ाने वाला है। धर्म की अकिंचन भावना से दिया गया दान प्रीति और सद्भाव बढ़ाएगा।

- जैनेंद्रकुमार

बचत की बुनियाद

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता इस बात से भी चलता है कि उसके बैंकों का कारोबार कैसा है। बैंकों का कारोबार मुख्य रूप से लोगों से जमा आकर्षित करने और उसे कर्ज के रूप में देकर उससे ब्याज कमाने से चलता है। मगर इस समय भारतीय बैंकों में जमा और कर्ज का अंतर काफी बढ़ गया है। इसे लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है। पिछले दिनों मौद्रिक समीक्षा के वक्त आरबीआइ के गवर्नर ने बैंकों से इस अंतर को पाटने के लिए विशेष योजनाएं चलाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि बैंक ब्याज दरें निर्धारित करने को स्वतंत्र हैं। यही बात केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआइ गवर्नर के साथ बैठक में कही। वित्तमंत्री ने कहा कि बैंक अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान दें। लोगों से जमा आकर्षित करने के लिए वे आकर्षक योजनाएं चला सकते हैं। दरअसल, सार्वजनिक बैंक निवेश की कमी के चलते गंभीर परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। कायदे से बैंक अपनी ब्याज दरें रेपो दरों से आधा से लेकर एक फीसद तक ऊपर रख सकते हैं। मगर इस मामले में भी उन्हें कुछ राहत दी गई है, फिर भी उनके पास अपेक्षित जमा नहीं आ पा रहा।

इसकी वजहें साफ हैं। पिछले कुछ वर्षों से लोगों की आमदनी लगातार कम हुई है। पहले जीएसटी की वजह से छोटे कारोबारियों पर बुरा असर पड़ा, फिर कोरोनाकाल में पूर्णबंदी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। जिन लोगों के पास नौकरियां हैं भी, उनके वेतन में तुलनात्मक रूप से काफी कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि महंगाई काफी बढ़ गई है। इस तरह बहुत सारे लोगों के पास बचत के लिए पैसे हैं ही नहीं कि उन्हें वे बैंकों में रखें। बल्कि इसका उलट यह हुआ है कि छोटे-छोटे काम के लिए भी लोगों को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कर्ज पर ब्याज की भरपाई करना भी बहुत सारे लोगों के लिए कठिन बना हुआ है। बचत के बारे में लोग तब सोचते हैं, जब उनके पास जरूरी खर्चों से अधिक आमदनी होती है। मगर सरकार लगातार इस हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही है कि रोजगार और आमदनी के स्रोत लगातार घटे हैं। कुछ दिनों पहले आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने खुद दोहराया था कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, गरीबी लगातार कम हो रही है। अगर सचमुच ऐसा होता, तो सरकार को इस तरह बचत बढ़ाने को लेकर चिंतित न होना पड़ता।

बैंकों में लोगों द्वारा जमा बचत से राष्ट्रीय बचत बनती है। जिस देश के पास राष्ट्रीय बचत जितनी अधिक होती है, उसे अपनी विकास परियोजनाएं चलाने में उतनी ही आसानी होती है। मगर इस वक्त जब चालू खाते में जमा की दर चिंताजनक देखी जा रही है, तो लंबे समय के लिए चलाई जाने वाली बचत योजनाओं में निवेश को लेकर क्या ही दावा किया जा सकता है। अगर बैंक आकर्षक योजनाएं लेकर आएंगे और उन पर अधिक ब्याज की पेशकश भी करेंगे, तो कितने लोग आकर्षित हो पाएंगे, कहना कठिन है। सरकारी योजनाओं के तहत कर्ज देने की बाध्यता और उनके वापस न लौट पाने, फिर बड़े पैमाने पर कर्जमाफी के चलते भी सार्वजनिक बैंकों के जमा और कर्ज में अंतर आया है। ऐसे में, सरकार बुनियादी पहलुओं पर काम करने के बजाय बैंकों पर दबाव बना कर शायद ही इस समस्या से पार पा सकेगी।

सुरक्षा पर सवाल

अस्पतालों में महिला चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अनेक बार सवाल उठते रहे हैं। खासकर रात के वक्त उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध की जरूरत रेखांकित की जाती है। मगर इस तकाजे पर गंभीरता से ध्यान कम ही दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि सेवा के समय अक्सर महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ जाती हैं। कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कालेज में प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या इसकी एक कड़ी है। प्राथमिक जांच से पता चला है कि उस चिकित्सक का बलात्कार किया गया और फिर उसे मार डाला गया। उसका शव अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में पाया गया। शव परीक्षा में उसके शरीर पर जगह-जगह गंभीर चोटें पाई गई हैं। हालांकि अस्पताल के कैमरों से मिली तस्वीरों के आधार पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर खासा सख्त रुख जाहिर किया है, मगर इस घटना को लेकर अस्पताल कर्मियों और चिकित्सा छात्रों का रोष कम नहीं हो रहा।

घटना की जांच के लिए सरकार ने सात सदस्यों का विशेष जांच दल नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर पीड़िता के परिजन चाहें तो वे इसकी सीबीआइ जांच के आदेश भी देने को तैयार हैं। मगर सवाल है कि आखिर इस तरह का साहस किसी में आया कैसे, कि उसमें कानून का जरा भी भय पैदा क्यों नहीं हुआ। अगर कानून-व्यवस्था का खौफ होता और अस्पताल प्रशासन मुस्तैद रहता, वहां सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होते, तो ऐसी वारदात होने ही न पाती। अच्छी बात है कि सरकार इस मामले पर किसी तरह की लीपापोती करने का प्रयास नहीं कर रही है, मगर सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहां इतनी लचर व्यवस्था क्यों है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। यह केवल किसी अस्पताल तक सीमित समस्या नहीं है। सामान्य रूप से भी घर से बाहर निकलते वक्त महिलाएं सशंकित रहती हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी न घट जाए। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सचमुच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए।

आर्थिक विकास पर अनुत्तरित प्रश्न

हमने तरक्की के पायदान तो कई चढ़ लिए। पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से दो-तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा भरोसा निजी क्षेत्र के योगदान पर ही क्यों किया जा रहा है?

सुरेश सेठ

देश 2047 में आजादी की सौवीं वर्षगांठ मनाने की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों जब नए माहौल में एक नई आर्थिक विकास यात्रा शुरू करने के वादों के साथ निर्माण यात्रा शुरू हुई, तो उसकी घोषणाओं में बहुत-सी ऐसी अधूरी बातें रह गईं, जिनका समाधान इतने दशक में भी नहीं मिल पाया है। सरकार की नई पारी की शुरुआत करते हुए घोषणा की गई कि देश में एक अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कतार के हर आखिरी आदमी को भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा। बेशक, सहकारिता की बातें बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इसके नाम पर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों से लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक भी बने हैं, लेकिन नतीजा उल्लेखनीय नहीं रहा। अब भी जब उम्मीद की जा रही थी कि सहकारिता का एक नया माहौल होगा, तो फिर भ्रष्टाचार और सहकारी योजनाओं के अधूरेपन के सत्य सामने आने लगे।

पंजाब के विभिन्न इलाकों में सहकारी 'मिल्क प्लांट' खूब कोलाहल के साथ शुरू किए गए थे, वे अब करोड़ों रुपए के घाटे में क्यों चल रहे हैं। देश भर में नए आंदोलन के नाम पर सहकारी बैंकों की जो इकाइयां सामने आईं, पिछले दिनों वहां लेनदेन बंद हो गया, क्योंकि उपकरण सही नहीं थे। सर्वर काम नहीं कर रहा था और हिसाब-किताब पूरा नहीं था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा के साथ हमने अपने संविधान में आर्थिक प्रगति की सौगंध खाई थी। वादा था कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र जहां आर्थिक तरक्की की ओर देखेगा, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र जनकल्याण की परवाह करेगा, क्योंकि उसके सामने हर निवेश में लाभ कमाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। हमने तरक्की के पायदान तो कई चढ़ लिए। पांचवीं आर्थिक महाशक्ति से दो-तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा भरोसा निजी क्षेत्र के योगदान पर ही क्यों किया जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र उपेक्षित हो रहा है, क्योंकि उसमें नौकरशाही और लालफीताशाही के बोलबाले पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर लाने की बात छोड़िए, यहां सब चलता है, की संस्कृति हावी होने लगी। इधर संसद में नए आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष से ठोस विचार-विमर्श की उम्मीद की जा रही थी, ताकि नई शासन पारी का नया वर्ष एक सार्थक शुरुआत बन सके। मगर इस पर राजनीति हावी होने लगी। आर्थिक समस्याओं पर चिंतन की जगह जातिवाद पर टीका-टिप्पणियों ने पूरे संवाद का मिजाज बिगाड़ दिया। कुछ सवाल थे, जो पूछे जाने चाहिए थे। देश के कर्णधारों से लेकर देश के विचारवान आर्थिक चिंतकों तक इन प्रश्नों के जवाब तलाश करने चाहिए। पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि हम 'जय जवान, जय किसान' के साथ 'जय अनुसंधान' का नारा लगाते हैं, लेकिन इस अनुसंधान पर पर्याप्त खर्च का प्रावधान कहां है। हमारे कृषिप्रधान देश में आज भी आधे से थोड़ी कम जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी हुई है, लेकिन उसका योगदान सकल घरेलू आय में केवल पंद्रह फीसद क्यों है?

भारत के वित्तीय कर्णधारों ने भी कहा है कि भारत का विकास करना है तो कृषि में उत्पादकता और वक्त के मुताबिक बदलाव की अनुकूलता बढ़नी चाहिए। आज भी खेतीबाड़ी होती है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में उनके

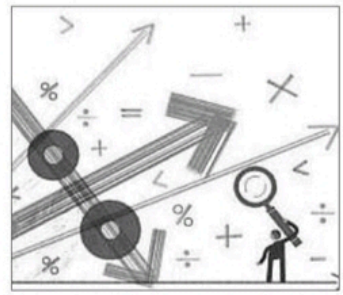

अंतिम उत्पाद बनाने के छोटे कारखाने क्यों नहीं उभर सके? ये उभर आते तो लोगों को रोजगार मिलता। इस युवा देश की आधी जनसंख्या तो काम तलाशते युवाओं की है, जिन्हें अपनी ग्रामीण जड़ों के माहौल में काम नहीं मिलता और वे समुद्र पार अपने लिए रोजगार तलाशने पर मजबूर होते, या

> **न**या आम बजट आया, लेकिन कृषि शोध की राशि बढ़ी नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि विकास दर पिछले वर्ष 4.7 फीसद थी, इस वर्ष घटकर 1.4 फीसद रह गई। यहां शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2008-09 में जो अनुपात 0.75 फीसद था, वह 2022-23 में घटकर 0.43 फीसद रह गया। कृषि अर्थशास्त्री तो समझाते रहे कि शोध बढ़ाओ, एक रुपए से दस रुपए प्राप्त होंगे। पर्यावरण अनुकूलित बीज लाओ, नई सिंचाई और विगाई तकनीकों पर काम करो, लेकिन वह नहीं हुआ। पचास फीसद आबादी अब भी खेतीबाड़ी में लगी है और उत्पादकता दुनिया में औसत से काफी कम है।

फिर सरकारी अनुकंपा यानी रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं का इंतजार करते हैं। क्यों बड़े पैमाने पर ग्रामीण समाज में शोध कार्य शुरू नहीं किए गए?

नया आम बजट आया, लेकिन कृषि शोध की राशि बढ़ी नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कृषि विकास दर पिछले वर्ष 4.7 फीसद थी, इस वर्ष घटकर 1.4 फीसद रह गई। यहां शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2008-09 में जो अनुपात 0.75 फीसद था, वह 2022-23 में घटकर 0.43 फीसद रह गया। कृषि अर्थशास्त्री तो समझाते रहे कि शोध बढ़ाओ, एक रुपए से दस रुपए प्राप्त होंगे। पर्यावरण अनुकूलित बीज लाओ, नई सिंचाई और काम करो, लेकिन वह नहीं हुआ। पचास फीसद आबादी अब भी खेतीबाड़ी में लगी है और उत्पादकता दुनिया में औसत से काफी कम है। क्या इसकी चर्चा संसद या नीति आयोग के मंच पर नहीं होनी चाहिए थी?

दुर्भाग्य से नीति आयोग की बैठक राज्यों को धनराशि के आबंटन के नाम पर राजनीति का शिकार हो गई। संसद में तो इस सवाल को सही ढंग से उठाया ही नहीं गया, सिवाय इस बात के कि दो चहेते राज्यों को धन आबंटन कर दिया, शेष रीते हाथ रह गए। सत्तापक्ष की ओर से इस बाबले को बार-बार रद्द किया गया। क्या कारण है कि संसद में जो बहस बहुत ठोस और सार्थक होनी चाहिए थी, उनमें महंगाई पर नियंत्रण और नौकरी के लिए एक नई रोजगार नीति की घोषणा नहीं हुई? जहां तक महंगाई पर नियंत्रण का संबंध है, इस समय देश की मौद्रिक नीति इस दोराहे पर ठिठकी हुई है कि क्या उसे कीमत नियंत्रण उपायों का सहारा लेते हुए अपनी मौजूदा नीति पर ही ठहरे रहना चाहिए या कि देश विकास की नीति का विकल्प अपनाकर अपनी साख नीति को उदार बनाकर देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाया देना चाहिए।

बार-बार कहा जाता है कि विश्व महामंदी का सामना कर रहा है। भारत ने बाहुबली, आर्थिक रूप से संपन्न देशों की विकास दर को पछाड़ दिया है, लेकिन हम कुछ बातों का पूरी तरह से ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे? महंगाई पर नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे और हमने महंगाई के सूचकांकों की परिभाषा को अपनी सुविधानुसार बदल दिया है। महंगाई के सूचकांकों की नई रपटें अब खाद्य वस्तुओं की कीमतों को उपेक्षित करके घोषित हो रही हैं, क्योंकि लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार कीमत की खुदरा दर को सुरक्षित चार फीसद तक लाया जाए। मगर एक बड़े सत्य की चर्चा क्यों नहीं हुई कि पिछले दिनों में थोक कीमत की दर, जो शून्य से नीचे चली गई थी, वह अचानक शून्य को पार करके ऊपर आ गई?

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मौसम के तेवर के बदलने से कुलांचे भरकर आम आदमी की जिंदगी को दुभर क्यों करती हैं? उससे भी बड़ी बात कि जब थोक कीमतों के सूचकांक गिरावट दिखा रहे हैं, तो परचून कीमत सूचकांक उनका अनुसरण क्यों नहीं करते? उनका विरोधी तेवर क्यों बना रहता है? क्या इसका कारण खुदरा व्यापारियों पर कमी के मनोविज्ञान का सहारा लेकर चोरबाजारी करना है? अगर चोरबाजारी है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इनकी चिंता तो होनी चाहिए?

इसके अलावा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर रियायतों और छूटों की घोषणा हो जाती है, लेकिन घरेलू बचत और मध्यवर्गीय बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नजर आने वाले कदम क्यों नहीं उठाए जाते? क्यों ऐसी बचतों पर कर बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे वह मामूली रूप से ही हो। यह आधा-अधूरा चिंतन देश के आर्थिक विकास की एक उदीयमान और संपूर्ण तस्वीर पेश नहीं करता। इसकी चिंता देश के विचारवान लोगों को करनी ही चाहिए।

खुशी और आजादी

मेघा राठी

विद्वान और दार्शनिक कहते हैं कि सच्ची खुशी पाने के लिए व्यक्ति का खुद के साथ होना जरूरी है। किसी भी बाह्य आलंबन द्वारा प्राप्त प्रसन्नता अस्थायी होती है, क्योंकि जैसे ही ये कारण दूर होने लगते हैं, प्रसन्नता उदासी या अवसाद में बदलने लगती है। यह सत्य भी है, लेकिन अपने आप में प्रसन्न रहने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है 'स्वतंत्रता', जो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक, तीनों रूपों में प्राप्त हो। खुद को खुश रखने के प्रयास में अगर किसी को इन तीनों रूपों में स्वतंत्रता न प्राप्त हो तो व्यक्ति के भरितष्क पर कहीं न कहीं दबाव बना रहता है, जो उसके खुश रहने में बाधक बनता है। फिर वास्तव में खुश होने की प्रक्रिया में बाधा आती है। यानी खुशी बाधित होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज के अपने पारंपरिक मापदंड और अपेक्षाएं होती हैं, जो व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों और कार्यों पर दबाव डालती हैं।

आमतौर पर लोगों की सोच एक तरह से पहले से निश्चित परिपाटी के अनुकूल तय होती है और चलती है। अगर व्यक्ति के कार्य और विचार उसके विपरीत हो रहे हों, भले ही उनके जरिए समाज का कोई अहित नहीं हो रहा हो, तब भी उनका परंपरा के अनुरूप न होना ही लोगों को खटकने लगता है और वे उसका विरोध करने लगते हैं या फिर व्यक्ति पर परिपाटी और परंपरा के अनुरूप होने के लिए वक्त-बेवक्त समझाइश, दबाव डाला जाने लगता है। अलग-अलग प्रकार से ताने दिए जाने लगते हैं, जिससे व्यक्ति पर मानसिक दबाव बनता है। इस तरह के हालात में भी मनुष्य को अपनी आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखने में कठिनाई होती है। अगर दबाव बनाने वाले लोग परिवार के सदस्य हों, तब स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को उनकी खुशी और उम्मीदों का भी सम्मान करना पड़ता है, ताकि उनके संबंध मधुर बने रहें। संबंधों में मधुरता कायम रखने के लिए न जाने कितने लोगों को क्या-क्या छोड़ना पड़ता है। हालांकि अपनी आंतरिक प्रसन्नता के लिए व्यक्ति का अपने प्रियजनों की उपेक्षा कर देना उसका स्वार्थ कहलाएगा, स्वतंत्रता नहीं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये कारण बाधा तो बनते ही हैं।

साथ ही व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से परनिर्भर है, तब भी वह इसे प्रसन्नता की राह में बाधक पाएगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने किसी भी निर्णय के लिए निवेश करने वाली वित्तीय आवश्यकता खुद से ही पूर्ण कर सकता है। जब व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं की चिंता नहीं होती, तो वह मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुष्ट रहता है, जिससे उसका संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।

वास्तव में स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जिससे उसका तनाव कम होता है, लेकिन उसे इन तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तो उसके मन में आत्म-संदेह की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। जब व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रह पाता, तो वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करने लगता है और यह नकारात्मक सोच और विचारधारा भी आत्म प्रसन्नता को अवरुद्ध करने लगती है। अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना निरंतर प्रयासों द्वारा ही संभव है, जिसे व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनने के लिए आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद न होने दिया जाए। व्यक्ति सदा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए और नकारात्मक विचारों से दूर रहे और साथ ही साथ चिंतन के माध्यम से समय-समय पर आत्म-साक्षात्कार करते हुए आत्म-सुधार पर ध्यान दे। सिर्फ अपने नहीं, बल्कि दूसरों के भी अधिकार हैं। इस सच को समझते हुए दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करने की जरूरत है। सामाजिक रूप से विभिन्न समुदायों और समूहों के साथ जुड़कर और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेने से व्यक्ति की सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के अलग-अलग आयामों के बारे में अपनी समझ स्पष्ट होती है। अपनी स्वतंत्रता के समांतर दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने की परिपक्वता हासिल होती है।

परिवार समाज की इकाई है और आपसी मेलजोल के साथ जब व्यक्ति के खुले और ईमानदार संवाद होंगे, विचार-विमर्श होंगे, एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान होगा तो निश्चित ही आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ेगा। व्यक्ति का अपने समय का सही प्रबंधन भी परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना कर आंतरिक प्रसन्नता को बनाए रखने में सहायता करेगा। ध्यान और योग करना भी मानसिक शांति और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

स्वतंत्रता के दायरे बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि अपनी प्राथमिकताओं को समझा जाए और अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उनको पूर्ण करने के लिए नियमित प्रयास किए जाएं।

दूसरे व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के विषय में समझाने से बेहतर है कि खुद ही इस दिशा में प्रयास करते रहा जाए, ताकि उनके द्वारा अपने आप ही स्वतंत्रता की स्थितियां निर्मित हो जाएं और हम आत्मिक रूप से प्रसन्न रहकर अपने आसपास के परिवेश को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकें।

दुनिया मेरे आगे

> **ज**ब व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रख पाता, तो वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करने लगता है और यह नकारात्मक सोच और विचारधारा भी आत्म प्रसन्नता को अवरुद्ध करने लगती है। अपनी प्रसन्नता बनाए रखने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना निरंतर प्रयासों द्वारा ही संभव है, जिसे व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तरों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

सबक और संदेश

बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता और समझदारी की सराहना करनी चाहिए। सरकार ने संसद में कोई बयान देने से पहले बांग्लादेश के विषय पर जिस तरह सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, वह सराहनीय है। किसी भी विवादित विषय पर कोई निर्णय लेने से पहले सर्वसम्मति बनाने की चेष्टा सजीव लोकतंत्र का गुण है, जिसका अभाव बांग्लादेश में अक्सर उभरता रहा है। बेशक, भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने में मदद की है, पर विदेश मंत्री ने यह भी बता दिया है कि भारत ने शेख हसीना को संयम बरतने की सलाह बार-बार दी थी और आग्रह किया था कि हालात को बातचीत से सुलझा लें। शेख हसीना का पतन वास्तव में उन सभी नेताओं के लिए सबक है, जो विपक्ष या विरोधियों के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं और जो लोकतंत्र और चुनाव की इज्जत नहीं करते हैं। आज के समय में सत्ता में बने रहने से ज्यादा जरूरी है- प्रतिकूल परिवेश न बनने देना। इसके बावजूद अगर हालात खिलाफ हो जाएं, तो समय रहते सत्ता से अलग हो जाना ही बेहतर है। इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है और अराजकता पर अंकुश रहता है।

- शाहिद हाशमी, जाकिर नगर, नई दिल्ली

बेलगाम हिंसा

मणिपुर में अभी तक साठ हजार से अधिक लोग बेघर, ढाई सौ से अधिक मौतें, सैनिक और सैन्य बलों की भी हत्या, सामूहिक बलात्कार और महिलाओं को नग्न घुमाने जैसी घटनाएं हुईं। हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला हुआ। इसे मुख्यमंत्री की बेबसी, नाकामी या भेदभाव का प्रतिवाद कहें, अन्यथा एक वर्ष में कुछ तो सुधार हुआ होता। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी नस्लीय हिंसा जारी रहने और न्याय न मिलने पर आरएसएस प्रमुख भागवत और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नाकाम बताया। उल्लेखनीय है कि मैतेई और कुकी में संवाद की गुंजाइश लगभग नहीं बची है और हमार और मैतेई के बीच हुआ समझौता भी चौबीस घंटे में टूट गया, क्योंकि सरकार में दूरदर्शिता का अभाव है। नस्लीय हिंसा के सामने असहाय बनने के बजाय राहुल गांधी की तर्ज पर मणिपुर के लोगों से सतत चर्चा जारी रखनी होगी।

- बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

आभासी दुनिया के खतरे

इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोग इसी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हमारा युवा इस सोशल मीडिया से अधिक समय और कहीं नहीं बिता रहा है। किसी एक ही और आभासी समाज से हमेशा घिरे रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आज इसमें बच्चे और बुजुर्ग, सभी लीन दिखते हैं। इससे हमारा मरितष्क विकृत हो रहा है जो भविष्य में घातक साबित होगा। इसलिए अब सरकार और हमारे समाज को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा समाज विनाश की ओर बढ़ता चला जाएगा। सोशल मीडिया के अनेक ऐसे मंच हैं, जो हमारे बच्चों और युवाओं को एक तरह से मादक पदार्थों में डुबोते जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की जिसे आदत लग गई है, वह उसे छोड़ नहीं पा रहा है और यह हमारे मरितष्क को कमजोर करता जा रहा है। इससे दूरी बनाना बेहद जरूरी है।

- अंकित यादव, दिल्ली

अब आगे

चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को पता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार की दोस्ती नई दिल्ली से गहरी थी। अब शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंध बाधित हो सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अहम सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच अच्छा-खासा व्यापार होता रहा है। अब दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती मिल सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीस्ता सिंचाई परियोजना पर चीन अपनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन भारत के इसमें सहयोग के प्रस्ताव से शेख हसीना ने अपनी नीतियां भी बदली थीं। अब वहां जिन लोगों ने सत्ता का सूत्र थामा है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये बांग्लादेश में शांति-व्यवस्था कायम करें।

- युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। रविवार, 12 अगस्त 2024

बेहतर हुए रिश्ते

विदेश मंत्री एस जयशंकर की पिछले सप्ताह हुई मालदीव यात्रा के दौरान वहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का जैसा दोस्ताना रवैया दिखा, उसे भावनात्मक राजनीति के तकाजों पर कूटनीति की ठोस हकीकतों की जीत के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। पिछले करीब एक साल की अवधि में दोनों देशों के रिश्तों ने तो हिचकोले खाए ही, एक ऐसे दौर के रूप में भी मालदीव कई कड़वे अनुभवों से गुजरा।

चुनाव प्रचार में भारत विरोध | इस प्रकरण की शुरुआत पिछले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से मानी जा सकती है जिसमें एक प्रत्याशी के तौर पर मुइज़ू ने भारत विरोधी भावनाओं पर दांव लगाया था। वह बार-बार सार्वजनिक तौर पर यह संकल्प करते देखे गए कि सत्ता में पहुंचते ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से विदा कर देंगे। हालांकि सबको पता था कि भारतीय सैनिकों की वहां मौजूदगी सांकेतिक ही थी।

जयशंकर की यात्रा दोस्ताना माहौल में

चीन से करीबी | चुनावों के दौरान ही यह साफ हो गया था कि मुइज़ू भारत के साथ रिश्तों में आ रही संभावित दूरी की भरपाई चीन से करीबी रिश्तों के रूप में करना चाहते हैं। हालांकि एकसपर्ट्स तब भी इस बात की ओर ध्यान खींच रहे थे कि भू-राजनीति की वास्तविकताओं के मद्देनजर यह संभव नहीं है कि मालदीव में जो भूमिका भारत निभा सकता है, वह चीन निभाने लगे।

मंत्रियों की टिप्पणी | राष्ट्रपति पद संभाल करने के बाद मुइज़ू के बयानों में हलकी सी नरमी जरूर दिखी, लेकिन नीतियों की दिशा बदलने का प्रयास भी जारी रहा। चुनावों के दौरान बने माहौल का असर ही कहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के एकाधिक मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में धीरे-धीरे बनता तनाव अचानक बेकाबू हो गया। सोशल मीडिया पर 'बॉयकॉट मालदीव' का हैशटैग ट्रेंड करने लगा।

वेट एंड वॉच की पॉलिसी | मालदीव की नई सरकार के रुख को देखते हुए भारत ने भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार कर ली। नतीजा यह हुआ कि भारत से छुट्टियां बिताने मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या कम होने लगी। इस साल के शुरुआती चार महीनों की अवधि में वहां भारतीय टूरिस्टों की संख्या में 42% की कटौती दर्ज की गई। ध्यान रहे, मालदीव की GDP में टूरिज्म का योगदान 30% है।

रुख बदलने के संकेत | इतना ही नहीं, भारत के सहयोग से चलने वाले इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स और हेल्थ, एजुकेशन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का भविष्य भी अधर में लटका दिखाई देने लगा। मुइज़ू सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। किसी अन्य देश का सहयोग भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता था। ऐसे में मुइज़ू सरकार ने पिछले कुछ समय से अपने रुख में बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया था। भारत ने भी इन संकेतों का सम्मान किया। नतीजा यह कि दो पड़ोसी देशों के पुराने रिश्ते फिर पटरी पर लौटते दिख रहे हैं।

चक्र-व्यू

जादू आलू का

राहुल पाण्डेय

जरूरी नहीं कि नाम का वही अर्थ निकले, जिसके लिए वह बोला जा रहा हो। जरूरी नहीं कि गाजर हमेशा गाजर हो, टमाटर हमेशा टमाटर हो या आलू हमेशा आलू हो। शुरुआती क्राइम रिपोर्टिंग के दिनों में एक बार मेरी ड्यूटी मेरठ की एक चुंगी पर लगा दी गई। काम था कि चुपचाप बैठे रहो और देखो कि पुलिस वाले 'चढ़ावे' के लिए कैसे-कैसे कोड बोलते हैं। एक-दो दिन कुछ समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। पुलिस वाले हमेशा अपने टिन शेड में ही बैठे रहते, बमुश्किल ही बाहर निकलते। और वैसे भी हिंदुस्तानी ट्रैफिक को पुलिस की न तो पहले जरूरत रही, और न ही आज है। हिंदुस्तानी ट्रैफिक रास्ता देखकर निकलता है, पुलिस देखकर नहीं। और जब नहीं निकल पाता है तो पुलिस को जेब से निकालकर एक जादू दिखाता है, और सर्र से निकल जाता है। अब जादू का तो हिसाब-किताब यही है कि जितना दिखाओ, लोग उतना ही और देखना चाहते हैं। फिर पुलिस भी तो इंसान ही है। वह बार-बार जादू देखना चाहती है। लोग बार-बार जेब से निकालकर कभी नीला, कभी हरा और बंद होने से पहले गुलाबी जादू दिखाते रहे हैं। शायद ऐसा कोई नहीं, जिसने पुलिस को यह जादू न दिखाया हो और जादू देखकर पुलिस का खिलता-खिलखिलाता चेहरा न देखा हो। हर इंसान में एक बच्चा होता है तो आखिर पुलिस में क्यों न हो? तो चुंगी पर मैं कई दिन पुलिस को बच्चों के जैसे खिलखिलाते देखता रहा। फरी, चुटकी, बैरियर जैसे कुछ कोडवर्ड हाथ लगे तो आकर खबर लिख दी।

जादू पर तो खबर क्या, किसी का असर नहीं हो सकता। लेकिन जादू के मंत्रों पर कुछ असर हुआ और कोडवर्ड बदल गए। साथी रिपोर्टर ने खबर दी कि इन दिनों प्याज, टमाटर चल रहा है, और महंगा होगा तो आलू भी चलेगा। पिछले हफ्ते एक दरोगा जी पांच किलो आलू मांगते पकड़े गए। अब यहां आलू यो वाला आलू नहीं है जो नाना पाटेकर साहब कोट पैंट पहनकर ठेले पर लादकर हांक लगाते हुए बेच रहे थे। ये वाला आलू बिकता नहीं, खरीदता है। हमारे एक गुरुवर बताते हैं कि दरोगा का तो मालूम नहीं, पर दस्तूर के हिसाब से एक किलो आलू का मतलब है 10 हजार नकद। उन्हें यह बात एक परिचित ने बताई थी, जिनसे पेशकार ने पांच किलो आलू मंगाए थे। हालांकि ट्रैफिक में एक किलो आलू का दाम कम होता है। ट्रैफिक की चौकी से तीन सितारे वाले थाने तक पहुंचते-पहुंचते इसका दाम बढ़ जाता है। बढ़ना भी चाहिए। दाम अगर ना बढ़े तो यह पुलिस की नहीं, आलू की बेइज्जती है। और दुनिया में किसी की इज्जत रहे या ना रहे, आलू की इज्जत बनी रहनी चाहिए। आलू है तो जादू है। आलू है तो चमक है।

एकदा

सैनिकों के लिए भोजन

अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। कुछ समय बाद अमेरिकी सेना को गेहूं के अभाव का संकट झेलना पड़ा। सैनिकों के भूखे मरने की नौबत आ गई। आखिर अन्न की कमी को कैसे पूरा किया जाए? पता चला कि Tuskegee School की प्रयोगशाला में शकरकंद के प्रयोग से डबल रोटी बनाई जाती है। यह भूख तो मिटाती ही है, पोषणयुक्त भोजन भी है। अधिक जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि जॉर्ज वॉशिंगटन कॉर्वर नाम के एक नीग्रो वैज्ञानिक ने मूंगफली और शकरकंद से कितने ही व्यंजन बनाए हैं। इनसे एक गरीब व्यक्ति और सैनिक बदहाल परिस्थिति में भी अपना गुजारा कर सकता है। यह जानकर उन्हें सैनिकों की मदद के लिए बुलाया गया। वहां आकर जॉर्ज कॉर्वर ने लोगों को शकरकंद से डबलरोटी, बिस्कुट, आटा बनाना सिखाया। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि शकरकंद की एक बहुत बड़ी खासियत है, यदि इसका निर्जलीकरण कर दिया जाए तो 100 पौंड शकरकंद का आटा एक छोटे-से डिब्बे में रखा जा सकता है। इससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखकर विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शकरकंद की यह खासियत वाकई युद्ध में सैनिकों के लिए बहुत अनमोल थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों और वहां की जनता को भूख से मुक्ति मिली। वह जीवनभर गरीब किसानों की मदद के लिए ही प्रयोग करते रहे।

Subrata Char

संकलन : रेनू सैनी

भारत को ओलिंपिक्स की मेज़बानी के बजाय पदकों की संख्या बढ़ाने पर देना चाहिए ध्यान

पैरिस ने जो सिखाया, याद रखना होगा

बोरिया मजूमदार

पैरिस ओलिंपिक्स में भारत से दहाई अंकों में मेडल जीतने की उम्मीद थी। हमारे पास 117 खिलाड़ी थे, जिनमें से कई दुनिया के टॉप ऐथलीट थे। इसलिए ये उम्मीदें जायज थीं। लेकिन, परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा, जितना सोचा गया था। सबसे बड़ी निराशा यह रही कि भारत पैरिस ओलिंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया।

खाब टूटा | विनेश फोगाट वाले मामले ने इस तकलीफ को और बढ़ा दिया है। युई सुसाकी जैसी महान खिलाड़ी को हराने के बाद विनेश गोल्ड के लिए सबसे मजबूत दावेदार थीं, लेकिन आखिरी मैच से पहले जब उनका वजन हुआ तो वह 100 ग्राम अधिक निकला। इसलिए उन्हें मैच की खातिर अयोग्य घोषित कर दिया गया और गोल्ड का ख्वाब टूट गया।

6 खिलाड़ी चौथे नंबर पर | सरसरी तौर पर देखें तो पैरिस ओलिंपिक्स भारत के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन गहराई से देखें तो कुछ उम्मीदें भी नजर आती हैं। नीरज चोपड़ा का कहना है कि 'छह चौथे स्थान आसानी से नहीं मिलते। इसका मतलब है कि हमारे खिलाड़ी लगभग-लगभग वहां तक पहुंच रहे हैं। हम उनका समर्थन करते रहें तो हम इन चौथे स्थानों को पदकों में बदल सकते हैं।'

रोमानिया से जीते | निशांत देव, विनेश फोगाट और सात्विक और चिराग की जोड़ी का प्रदर्शन देखते हुए दहाई अंकों में मेडल जीतना संभव लग रहा था। महिला टेबल टेनिस में भी भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दो भारतीय लड़कियों का प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना थी और टीम इवेंट में रोमानिया को हराना भी। रोमानिया के खिलाफ भारत ने शानदार जीत दर्ज की।

बड़े मौके पर गलतियां | धीरज और अंकित भगत मिक्स्ड आर्चरी में मेडल के बहुत करीब पहुंच गए थे। लक्ष्य सेन ने एक गेम का फायदा और 8-3 की बढ़त गंवा दी। सात्विक और चिराग भी एक गेम से आगे थे और फाइनल सेट में 14-10 से आगे थे, लेकिन फिर हार गए।

ओलिंपिक्स के सबक

- 6 ऐथलीट चौथे स्थान पर रहे
- मैनेजमेंट से कुछ गलतियां भी हुईं
- 2028 में अधिक फंक्स पर हो ध्यान

आत्मनिरीक्षण की जरूरत | कुछ खेलों में, जैसे ऐथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और महिला बैडमिंटन में आत्मनिरीक्षण करने की बहुत गुंजाइश है। चोपड़ा और अविनाश साबले (3000 मीटर स्टीपलचेज) और कुछ हद तक पारुल चौधरी (3000 मीटर स्टीपलचेज) को छोड़कर, ब 1 क ी सभी ट्रैक एंड फील्ड ऐथलीटों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया।

शूटिंग में वापसी | निशानेबाजों ने तीन मेडल जीते। रियो 2016 और तोक्यो 2020 की निराशाओं के बाद पैरिस ओलिंपिक्स में इस प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि भारतीय खिलाड़ी फिर से पुरानी चमक हासिल कर रहे हैं और आगे भी उनका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। हॉकी में कांस्य पदक मिला। यह भी बेहद खुशी का विषय है। तोक्यो के बाद पैरिस ओलिंपिक्स में भारत ने लगातार दूसरी बार यह मेडल हासिल किया है।

कहां हुई गलती | भारत कहां गलती कर रहा था? ऐथलीटों के प्रबंधन में। सहायक कर्मचारियों, जिनमें पोषण विशेषज्ञ और खेल वैज्ञानिक शामिल हैं, उन्हें अंतिम पंघाल की नाकामी के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि उसके पास वाउट के दौरान कोई अजों न बची हो? जब आप सुनते हैं कि उसने वजन कम करने के लिए 48 घंटे तक भूखे रहकर प्रतियोगिता की, तो यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। मुक्केबाज अमित पंघाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। और विनेश के मामले में गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। हालांकि इस मामले में सजिश की जो थिअरी चल रही है, उसमें कोई दम नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं किसी ने गलती की, जिसकी वजह से भारत को पदक गंवाना पड़ा।

खिलाड़ियों की संख्या बढ़े | आगे चलकर, भारत को एक सरल बात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वह है, 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक्स में ऐथलीटों की संख्या तिगुनी करने का प्रयास करना। पैरिस में, अमेरिका के 600 से अधिक ऐथलीट थे, जबकि जापान के 400 से अधिक। भारत ने केवल 117 ऐथलीट पैरिस ओलिंपिक्स में भेजे थे। अगर भारत इस संख्या को तीन गुना बढ़ाने में सक्षम होता है तो स्वाभाविक है कि पदकों की संख्या भी बढ़ेगी।

पहले पदक बढ़ें | 2036 में खेलों की मेजबानी करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, ध्यान पूरी तरह से 2028 ओलिंपिक्स और उसके बाद के आयोजनों में पदकों की संख्या बढ़ाने पर होना चाहिए। तभी हम ओलिंपिक्स नेशन बन सकते हैं और तभी दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी का कोई मतलब होगा।

परछाइयों में छिपी खुशियों को कभी तलाशा क्या

प्रह्लाद आचार्य कोई जादूगर नहीं हैं, फिर भी उन्हें जादू आता है। कभी वह हाथों से कोई जानवर निकालते हैं, तो कभी इंसान। कभी कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ उनकी हथेलियों के बीच प्रकट हो जाता है, तो कभी कोई बूढ़ा पेड़ कहानी सुनाने लगता है अपनी। प्रह्लाद यह सब कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोशनी का इस्तेमाल कैसे करना है।

वह एक शैडो आर्टिस्ट हैं। शैडो आर्टिस्ट मतलब परछाइयों से खेलने और उससे खेल दिखाने वाला कलाकार। वह कभी सामने नहीं आता। उसकी कला खिलती ही पर्दे के पीछे रहकर है। सामने आता है बस उसका काम, जिसे देखकर सामने बैठे दर्शक खिलखिला उठते हैं। परछाई होती है काले रंग की, लेकिन जब वह पर्दे पर उतरती है, तो उसमें कल्पनाओं के रंग अपने आप भरते चले जाते हैं। कलाकार की अंगुलियों से पैदा हुई समंदर की लहर या उगते सूरज से जगमगा रहे आसमान के बारे में दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं कि उसका रंग क्या होगा। वह बात अनकही, लेकिन समझी-बूझी है। ऐसा ही खेल तो परछाइयां हमारे साथ हर दिन खेलती हैं। बिना कहे वे हमें तरह-तरह की चीजें दिखाती हैं, और इसमें भी वही आनंद है जो शैडो प्ले में।

परछाई हवा की तरह है, जो हथेलियों पर आकर बैठ जाती है, लेकिन मुट्ठी में कैद नहीं होती। यह बादलों की तरह है, जो आपको बिल्कुल वही दिखा सकती है जो उस समय आप देखना चाहते हैं। परछाइयों से खेलना पजल गेम में उलझने जैसा है। आप बस सोचिए कि दिखना क्या है और रोशनी से मिलकर परछाई वह चीज पेश कर देगी।

AI Image

जीवन आनंद

गौर कीजिए कि पेड़ों की परछाई क्या बना रही है, कमरे में पड़ा बेड, मेज पर रखा सामान, कुर्सियां और डोरी पर उड़ते कपड़े किस तरह का करतब रच रहे हैं।

कहा जाता है कि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, और जब छोड़ती है तो वक्त वाकई बुरा होता है। लेकिन, क्या परछाई सही में साथ छोड़ देती है या शायद वह हमारे साथ ही रहती है, पर दिखती नहीं। अंधेरा कभी भी घिर सकता है, बिल्कुल मुश्किलों की तरह। तब ऐसा लग सकता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन, दरअसल अंधेरे के कारण हम ही नहीं देख पाते। परछाई तो वहीं रहती है।

हमारे साथ चलते हुए परछाई कभी पीछे रह जाती है, कभी आगे निकल जाती है, लेकिन वह कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होती। उसके आसपास कई रंग हैं। लेकिन कभी किसी परछाई को नहीं देखा होगा आपने कि वह रंगों के पीछे भागे। जो है जैसा है, वह संतुष्ट है उसमें। लेकिन, इसके स्वभ ही वह यह भी बताती है कि आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। अगर रोशनी के साथ तालमेल सही बन जाए, तो एक छोटी-सी परछाई भी बड़ी होकर किसी को भी आगोश में ले सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें छिपक नहीं है और आत्मविश्वास तो कूट-कूटकर भरा है। देखिए, कितनी गंदगी है सड़क पर, आजकल तो हर जगह कीचड़ ही कीचड़, ऊपर से नकारात्मक बातें। लेकिन, बढ़ती हुई परछाई जब इनके बीच से गुजरती है, तो भी इनके असर में नहीं आती। कितनी भी खराब स्थिति हो, वह उसमें से निकलती बिल्कुल साफ है। उसे किसी बात का डर नहीं है, न किसी की आलोचना का, न किसी की डांट-फटकार या मार का। वह तो उस अंधेरे से भी नहीं डरती, जो उसे खत्म करने पर तुला है। उसे पता है कि अंधेरा हुआ है, पर हमेशा तो नहीं रह पाएगा। उसे हटना ही पड़ेगा और तब वह फिर सामने आ जाएगी। तब तक वह हम में समा जाती है। उसे हम पर भरोसा है, तो हमें अपनी परछाई पर भरोसा क्यों नहीं।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें लिखें nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें 'जीवन आनंद'

चीन के कितने चेहरे, जानते हैं आप?

मृत्युंजय राय

चीन के आर्थिक मॉडल और उसकी कामयाबी की अक्सर चर्चा होती है। किस तरह से चीन ने 'मिरैकल इकॉनमी' का दर्जा हासिल किया और कैसे वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने पूंजीवाद का एक अलग ही रास्ता दुनिया को दिखाया। कई देशों ने इसकी नकल करने की भी कोशिश की, लेकिन चीन जैसी तरक्की कोई हासिल नहीं कर पाया। हमारे यहां भी यह चर्चा होती आई है कि क्या भारत इस मॉडल को अपनाकर मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ताकत नहीं बन सकता ताकि कृषि क्षेत्र से अधिक कामगारों की खपत वाले उद्योग धंधों की ओर लोगों को शिफ्ट किया जा सके और बेरोजगारी में कमी लाई जाए। इस बारे में जानकार दो धड़ों में बंटे हुए हैं। कुछ इसके पक्ष में तो कुछ विरोध में।

AI Image

विचार विंडो

चीन फिलहाल आर्थिक दुश्वारियों से गुजर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास, भूगोल और विरासत के जरिये भी इस देश को समझा जा सकता है। इस नजरिये से देखने पर चीन की कैसी तस्वीर सामने आती है? **At the Edge of Empire: A Family's Reckoning with China** में एडवर्ड वोंग (Edward Wong) ने यही कोशिश की है। यह किताब संस्मरण है, जिसके जरिये लेखक ने चीन के अंदर निहित विरोधाभासों को सामने लाने का प्रयास किया है। एडवर्ड इसमें अपने पिता और चाचा के बारे में लिखते हैं। दोनों का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हॉन्गकॉन्ग में हुआ था। 1948 में एडवर्ड के चाचा अमेरिका पढ़ाई के लिए चले गए और पिता 1950 में पेइचिंग। उनके पिता क्रांति के सिपाही बनने गए थे। उन्हें पार्टी ने शिंगच्यांग में तैनात किया।

क्रांति के इस सिपाही का क्यों माओवाद से मोहभंग हुआ, इस बारे में एडवर्ड लिखते हैं कि जब उनके पिता ने बाद के वर्षों में देखा कि क्रांति के कई नायकों की हत्या कर दी गई और माओ की 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' पॉलिसी की वजह से चीन को कैसे भुखमरी से गुजरना पड़ा तो उन्हें इसके खोखलेपन का अहसास हुआ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत माओवादी चीन ने औद्योगिक ब्रिटेन की बराबरी करने का लक्ष्य तय किया था। एडवर्ड के पिता ने चीन से भागने का फैसला किया। वह पहले हॉन्गकॉन्ग गए, जहां ब्रिटेन की हुकूमत थी और लोकतंत्र था। अफीम युद्ध में हार के बाद हुए समझौते की वजह से हॉन्गकॉन्ग को 100 वर्षों के लिए चीन ने ब्रिटेन को लीज पर दिया था। खैर, एडवर्ड के पिता हॉन्गकॉन्ग में भी ज्यादा वक्त नहीं रुके और 1962 में अमेरिका पहुंच गए। कोई एक दशक बाद यहीं एडवर्ड का जन्म हुआ।

एडवर्ड की वापसी चीन में 2008 में हुई। वह एक अमेरिकी अखबार के संवाददाता के रूप में चीन पहुंचे। वह अपने पिता के गांव गए। यहां उन्होंने देखा, किस तरह से कम्युनिशयस के पारिवारिक रिश्तों के बारे में विचार आज तक समाज पर प्रभाव रखते हैं। उन्होंने इसकी कमियां भी देखीं। ये विचार चीन में Individualism में बाधा बनते हैं, जबकि अमेरिका में एडवर्ड के परिवार ने इसी Individualism की बदौलत तरक्की हासिल की थी। वह शिनच्यांग, तिब्बत और हॉन्गकॉन्ग भी गए, जहां उनके पिता रह चुके थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और औपनिवेशिक इतिहास के कारण लोगों में कम्युनिस्ट सत्ता को लेकर नाराजगी है और सरकार कैसे इसे दबाने की कोशिश करती रहती है। अपने परिवार के किस्सों के जरिये एडवर्ड चीन की तस्वीर रखने में कामयाब रहे हैं और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने चीन के अंतर्विरोधों को भी सामने रखा है।

रिश्तों में बराबरी

प्रणव प्रियदर्शी

स्त्री-पुरुष संबंधों को अक्सर तर्कों से परे कहा जाता है। किस तरह के लड़के और किस तरह की लड़की में बनेगी और कौन किसे पसंद करेगा, यह तय करने का कोई फॉर्म्यूला नहीं है। हालांकि फॉर्म्यूले खोजने की कोशिशें कम नहीं हुईं। रूप-गुण से लेकर कुंडली मिलाने तक की तमाम कवायदें इसी का नतीजा हैं। बहरहाल, बात पसंद की उतनी नहीं, जितनी पसंद के बाद शुरू होने वाली साझा जिंदगी की है। अक्सर बड़े साहित्यकार, मानव मन के जानकार भी इस तरह का निष्कर्ष देते हैं कि प्यार में लड़का और लड़की के बीच बराबरी नहीं हो सकती क्योंकि रोमांस के विचार में ही पुरुष प्रधानता का तत्व गुंथा होता है। इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए अपेक्षाकृत उदार विचारों वाले कुछ लोग कहते हैं कि मैन-वुमन रिलेशनशिप में बराबरी की तलाश मृगतृष्णा है क्योंकि यह व्यवहार में संभव नहीं। उनका कहना है कि कौन कब डॉमिनेट करेगा यह तय नहीं है। कुछ खास स्थितियों में एक पक्ष ऊपर होता है तो दूसरे हालात में दूसरा पक्ष। मगर गैर-बराबरी की कीमत होती है। फ्रांस की फेमिनिस्ट राइटर और पत्रकार ने अपनी पुस्तक **Reinventing Love : How the Patriarchy Sabotages Hetrosexual Relations** में इस पहलू पर रोशनी डाली है। सवाल कई हो सकते हैं। मसलन, एक स्त्री और एक पुरुष के साथ रहने के आधार पर ही क्या यह माना जा सकता है कि कोई रिश्ता प्यार से निर्देशित हो रहा है? और, अगर रिश्ते में पजेसिवनेस या स्वामित्व का भाव, पालन-पोषण करने और खर्चा चलाने का भाव हावी हो जाए तो भी क्या इसे प्यार से निर्देशित माना जाएगा? आखिरी बात, प्यार में समर्पण के भाव के चलते इंगो की खास भूमिका नहीं रह जाती। लिहाजा हिसाब-किताब भी नहीं होता कि कितनी मैंने पार्टनर की सुनी और कितनी पार्टनर ने मेरी। लेकिन अपनी न सही तो पार्टनर की ही सोचकर रिश्तों में बराबरी सुनिश्चित करने की कोशिश तो हो ही सकती है, बल्कि होनी चाहिए।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ जीवन की खुशियां

5 अगस्त को 'जीवन आनंद' कॉलम में 'एक ट्रिक आजमाइए, काम से प्यार हो जाएगा' लेख पढ़ा। लेखक ने यह बताया है कि किस तरह हम अपने काम में मजा ढूंढ सकते हैं। अक्सर हम काम को बोझ समझते हैं और बॉस की बातें सुनकर तनाव और थकावट महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने काम को केवल एक नौकरी के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा मानें। हर बड़ा काम छोटे-छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम काम को प्यार से करते हैं तो उसमें आनंद महसूस होता है। काम से जुड़ी चुनौतियां और समस्याएं हमें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।

सुधांशु शेखर मिश्र, इंमेल से

■ सुखी जीवन के फॉर्म्यूले

ट्विस्ट जीवन को सरल और सुखमय बनाने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते हम समय और हालात के बीच तालमेल बैठा लें। योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या को व्यवस्थित करने से जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। 5 अगस्त के लेख 'एक ट्रिक आजमाइए, काम से प्यार हो जाएगा' में इस बात को बेहतर अंदाज में समझाया गया है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क है। इन ट्रिक्स को अपनाएं तो ये गणित और फिजिक्स के फॉर्म्यूले की तरह हर समस्या को सॉल्यूशन तक पहुंचा देते हैं।

गरिमा रावत, इंमेल से

■ आगे की उम्मीद

जीत चाहे बड़ी हो या छोटी, वह जीत हो होती है। हाल ही में ओलिंपिक्स खेलों में भारत ने केवल 6 मेडल जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह छोटी उपलब्धि नहीं है। भले ही यह संख्या कुछ अन्य देशों की तुलना में कम हो, लेकिन हर एक मेडल और हर एक खिलाड़ी ने अपने प्रयासों से हमें गौरवान्वित किया है। आगे की उम्मीद रखकर अपनी खुशियों को इन सफलताओं से जोड़ना चाहिए।

उज्ज्वल कुमार, पीतमपुरा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ लिखें।

जीवन आनंद

अंतिम पत्र

यूक्रेन को 12.5 करोड़ डॉलर देगा अमेरिका - एक खबर

- यह युद्ध की आग में घी डालने का तो काम नहीं है।

प्रमोद यादव

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

जब आनंद अपने भीतर है, दुनिया के भरोसे क्यों रहना

प्रेम रावल जी

इस संसार में आपके लिए सबसे मूल्यवान चीज कौन-सी है? वह जो सबसे सरल हो, आसान हो, मुफ्त हो और जिसके लिए किसी प्रयास की जरूरत न हो, पर जिसे सारी दुनिया के धन से भी नहीं खरीदा जा सकता हो? इतनी सस्ती और इतनी महंगी चीज क्या है?

एक सांस है! यह सरल है। इसको लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह अपने आप आती है, अपने आप जाती है। कभी सोचा कि यह सांस कितनी अनमोल है? एक-एक करके आती है और जब तक आती रहती है, तुम्हारे लिए सब कुछ है। सारे रिश्ते-नाते इसीलिए हैं, क्योंकि ये सांस आ रही है। जिस दिन सांस आनी बंद हुई, लोग इकट्ठा होंगे और फूंक-फांक देंगे। यह सांस का ही तो चक्कर है।

बनाने वाला तुमको ये मुफ्त में दे रहा है। अगर मनुष्य ने इसकी क़दर नहीं जानी तो यह आई और चली गई। उसके पास दुनिया की सबसे महंगी चीज आई, उसके पास धनों का धन आया, परंतु वह उस चीज को नहीं पहचान सका। यह इस जीवन को पहचानने की बात है। इस प्यास को पहचानने की बात है। मैं आपको प्यास देने की कोशिश नहीं कर रहा। जो प्यास पहले से ही आपके अंदर है, उस प्यास से आपका परिचय होना चाहिए। यह आपकी अपनी चीज है। अगर इस प्यास से आपका परिचय नहीं हुआ तो समय निकल जाएगा! बनाने वाले ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है, अपने जीवन में इस कृपा को पहचानो।

हमारे अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है और वह है परमानंद। उस परमानंद का स्वयं अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव का आनंद उठाया जा सकता है। उसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। ढूंढने से वह नहीं मिलेगा। वह पहले से ही वहीं है, जहां है। जो चीज तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे पास ही मिलेगी। लोग समझते हैं कि अगर सारी लड़ाइयां बंद हो जाएं तो शांति हो जाएगी।

इस जीवन के अंदर आनंद की अभिलाषा हर एक व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो। सबको आनंद चाहिए, सुख-शांति चाहिए। आनंद मिल रहा है तो सब कुछ ठीक है। कोई मंदिर में नहीं जाता है यह कहने के लिए कि, 'हे भगवान! बहुत ज्यादा आनंद दे दिया, अब थोड़ा-सा कम कर दो।' कोई नहीं जाता है, क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति है कि तुम्हारे लिए सुख सहने की कोई सीमा नहीं है और दुःख जरा भी नहीं झेल सकते।

यह सारा संसार हमसे वायदा करता है कि आनंद तरफ चलो। जैसा हम कहें, वैसे चलो और तुमको सुख मिलेगा। परंतु यह दुनिया सिर्फ दुःख देती है। यही होता है। तो कैसे मिलेगा सुख? कहां है असली सुख? ऐसा सुख कहां है, जो जिंदगी भर बना रहे?

लोग बड़े-बड़े प्लान बनाते हैं। पर क्या तुमने इस जीवन का भी कोई प्लान बनाया है? तुम्हारे अंदर भी एक जगह है, वह है असली स्वर्ग। वहां कौन बैठा है वह 'हंस' बैठा है तुम्हारे अंदर, जो सबको आनंद विभोर कर देता है। उसको जानो, ढूंढो! जहां मिले वही ठीक है, नहीं मिले तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं।

प्रस्तुति : आर.डी.अग्रवाल 'प्रेमी'

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, रविवार, 12 अगस्त 2024

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, रविवार, 12 अगस्त 2024

अगर आपने हवाई किले बना रखे हैं, तो आपका काम बेकार नहीं जाना चाहिए; वे वहीं होने चाहिए. बस अब उसके नीचे नींव डाल दीजिए. : हेनरी डेविड थोरो

हिंदुओं की आवाज उठाने में क्यों डर रहा है विपक्ष?

गजब है कि भारत की सेकुलर बिरादरी को हजारों किलोमीटर दूर गाजा में मारे जा रहे मुस्लिमों के प्रति सहानुभूत उमड़ आती है लेकिन पड़ोसी देश में इस्लामिक हिंसा का शिकार हो रहे हिन्दू दिखाई नहीं पड़ते हैं। गाजा के मामले में कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा से लेकर अन्य कई विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आते हैं लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में अभीतक कांग्रेस के मुख्य नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का कोई बयान नहीं आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवश्य ही तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस से अपील की है कि उनकी सरकार हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों की चिंता करे। हिंदू समाज को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उनके हित की बात करने वाली केवल एक ही पार्टी और उसके नेता हैं। हिंदू समाज के मन में प्रश्न यह भी है कि आखिर क्या कारण है कि गाजा में मुसलमानों की चिंता करने वाले कांग्रेसी नेता बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज नहीं उठा पा रहे? अपितु कई छुटभैये कांग्रेसी नेता तो यह स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में दो-चार गलत फोटो/वीडियो को आधार बनाकर हिंदुओं पर हो रहे भयानक हमलों की नकारने की शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं। इतनी ही नहीं, एक-दो फोटो/वीडियो के आधार पर यह स्थापित करने के भी प्रयास हो रहे हैं कि मिस्लिम समुदाय तो हिंदुओं के घरों और मंदिरों की रक्षा कर रहा है? सच पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे 'झूठों के समूह' से जब यह पूछा जाता है कि यदि मुस्लिम हिंदुओं के घरों और मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं तो वे कौन लोग हैं जो उनके घरों और मकानों को जला रहे हैं? झूठे लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं।

हिंदू समाज के मन में प्रश्न यह भी है कि आखिर क्या कारण है कि गाजा में मुसलमानों की चिंता करने वाले कांग्रेसी नेता बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज नहीं उठा पा रहे? अपितु कई छुटभैये कांग्रेसी नेता तो यह स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है।

ये लोग हिंदुओं की संवेदना बनाने की जगह उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। हिंदुओं के जलते घरों के सामने सेकुलरिज्म की ढपली बजाने वालों को क्या ही कहा जा सकता है। यह सुखद बात है कि बांग्लादेश के हिन्दू एकजुट होकर सड़कों पर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में एकत्र आकर बांग्लादेश के हिन्दू समाज ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के अनुसार, देश के 64 जिलों में से 52 में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। परिषद ने कहा है कि देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की आबादी इस स्थिति से बुरी तरह से आशंकित, बेचैन और भविष्य की अनिश्चितता को लेकर डरी हुई है। परिषद ने सरकार प्रमुख मुहम्मद यूनुस से सुरक्षा और संरक्षण की मांग की है। एकजुटता का प्रभाव यह है कि अमेरिका में भी अब यह बात उठ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को यथाशीघ्र रोका जाना सुनिश्चित किया जाए। स्मरण रखें कि अपनी माटी, घर, दुकान और मंदिर छोड़कर भागना कोई उपाय नहीं हो सकता। मुसीबत का सामना करना ही उचित निर्णय है। बांग्लादेश ही नहीं अपितु दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हिंदुओं को यह समझना पड़ेगा कि संगठित रहने में ही शक्ति है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबाकर तूफान से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस्लामिक कट्टरता के सच को स्वीकार करके संगठित शक्ति के रूप में रहना ही श्रेष्ठ निर्णय होगा। अगर हिन्दू पहले से संगठित होता तो बांग्लादेश में भी इस प्रकार के हमले करना आसान बात न होती। बहरहाल, भारत सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस और रणनीतिक कदम शीघ्र उठाने चाहिए। विश्वास है कि भारत सरकार इस दिशा में कुछ कार्य कर भी रही होगी, जिनको सामान्य लोगों के सामने रखना कूटनीतिक रूप से उचित न हो। बांग्लादेश में हो रही उठापटक को लेकर भारत सरकार बहुत सक्रिय दिख रही है। यह सक्रियता निरंतरता के साथ बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि हिन्दू समाज को जो कुछ उम्मीद है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से ही है।

हिन्दवी स्वराज्य स्थापना का 350 वां वर्ष

महाराज का राज्याभिषेक

स्वर्य गागाभट्ट जैसे वेदोनारायण ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का महत्व व आवश्यकता का प्रतिपादन किया। राज्याभिषेक होना ही चाहिए यह आग्रह पूर्वक बताया। 'सिंहासन पर बैठिये!' यह गागाभट्ट के रूप में धर्म की ही आज्ञा थी। महाराज क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे, संस्कार लुप्त हुए थे, सिंहासन लुप्त हुआ था। इनकी फिर से संस्थापना शिवाजी जैसे प्रतापी पुण्यश्लोक राजा के हाथों होना यह मराठों का, मराठों की मिट्टी का, महाराष्ट्र प्रान्त का अहोभाग्य था! राज्याभिषेक की हृदयंगम कल्पना से रायगढ़ पर नवचैतन्य निर्माण हुआ। खबर चारों ओर फैली, शूर सैनिक आनंदमुग्ध हुए। जीजाबाईसाहेब-मांसाहेब को लगा मानों मेरे व्रत का उद्यापन होगा।

राज्याभिषेक होना तय हुआ व सर्वप्रथम विचार हुआ राजधानी कौनसी? अर्थात राजधानी के लिए रायगढ़ तय हुआ। कारण? क्योंकि गढ़ मजबूत था, चारों दिशाओं में पत्थर के सीधे कड़े थे, ऊंचाई भरपूर थी। पूर्व में ही बारह महल, अट्ठारह कारखानों से गढ़ सुसज्जित था। अब राज्याभिषेक के लिए राजसभा, श्री जगदीश्वर मंदिर निर्माण के लिए महाराज ने भवन निर्माण विधान के प्रमुख हिराजी इंदुलकर को याद किया। इंदुलकरजी ने गढ़ की सजावट प्रारम्भ की। राजसभा के द्वार पर नगाड़खाना बना। इस प्रवेशद्वार की ऊंचाई इतनी थी कि हाथी की पीठ पर झंडा बंधा हुआ हो तो भी हाथी आसानी से अंदर प्रवेश कर पाएगा।

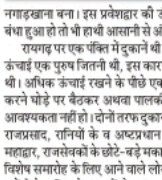

रायगढ़ पर एक पंक्ति में दुकानें थी जिससे बाजार सज गया था। इन दुकानों की ऊंचाई एक पुरुष जितनी थी, इस कारण दुकानें अधिक शोभायमान प्रतीत हो रही थी। अधिक ऊंचाई रखने के पीछे एक उद्देश्य था, अगर कोई व्यक्ति खरीददारी करने घोड़े पर बैठकर अथवा पालकी में बैठकर आया तो उसे नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं हो। दोनों तरफ दुकानें व उसके मध्य लम्बा-चौड़ा राजरस्ता था। राजप्रसाद, रानियों के व अष्टप्रधान मंडल के महल, राजसभा, नगाड़खाना, महाद्वार, राजसेवकों के छोटे-बड़े मकान, कोठियां-हवेलियां थी। इसके अतिरिक्त विशेष समारोह के लिए आने वाले लोगों की व्यवस्था के लिए 20,000 लोग बैठ सके ऐसे शामियाने, मण्डपों से गढ़ सुसज्जित हुआ था।

हिराजी ने जगदीश्वर मंदिर की सीढ़ी पर लिखवाया था, 'सेवा के लिए सतत तत्पर, हिराजी इंदुलकर'! इसके साथ राज्याभिषेक का उल्लेख तिथि सहित भी दीवार पर लिखवाया गया। ' श्रीगणपतये नमः'

प्रासादो जगदीश्वरस्य जगतामानन्दो नुज्ञया, श्रीमच्छत्रपतेः शिवस्य नृपतेः सिंहासने तिष्ठतः, शाके षण्णव बाणभूमिगणनादानन्द संवत्सरे, ज्येष्ठि राजमुहूर्त कीर्तिसहित शुक्लेथ सार्पे तिथऔ ।

नगाडखाना व महाद्वार की दीवारों पर अपने पैरों तले सिंह हाथी को रौन्द रहा है ऐसे शिल्प उकेरे गये थे।

गढ़ पर टकमक टोक (फांसी देने का स्थान), पूर्व में भवानी व पश्चिम में हिरकणी बुर्ज, उसके पास श्रीगोंदे टोक था व कैलाश पर्वत जैसा रायगढ़ का शिखर था। पानी की व्यवस्था के लिए गढ़ पर गंगासागर व कुशावर्त तालाब थे। हाथियों के स्नान के लिए अलग तालाब बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त गढ़ पर अन्यान्य स्थानों पर पानी की टंकियां व छोटे तालाबों का निर्माण करवाया गया था।

विपक्ष मुस्लिम मुद्दे को उठाकर अपने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश कर रहा है

राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का संकट और भूमिका महत्वपूर्ण

आलोक मेहता
आई टी वी नेटवर्क इंडिया न्यूज और आज समाज के सम्पादकीय निदेशक

लोकसभा चुनाव के दौरान और बाद में राहुल गाँधी की कांग्रेस, लालू यादव की आर जे डी, ममता की तृणमूल कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के संकट, समुदाय के अपने शरीयत कानून, वक्फ बोर्ड के अधिकार, बांग्ला देश की घटनाओं के साथ मुस्लिम विस्थापतों आदि मुद्दे उठाकर अपने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान और बाद में राहुल गाँधी की कांग्रेस, लालू यादव की आर जे डी, ममता की तृणमूल कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के संकट, समुदाय के अपने शरीयत कानून, वक्फ बोर्ड के अधिकार, बांग्ला देश की घटनाओं के साथ मुस्लिम विस्थापतों आदि मुद्दे उठाकर अपने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम अस्मिता के साथ राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के आदर्शों के आधार पर यही दावा करते हैं कि सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट से सभी क्षेत्रों , वर्गों , समुदायों की जनता को लाभ मिल रहा है। कहीं अल्प संख्यकों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। यही कारण है कि कई प्रदेशों के मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिए हैं। सबसे बड़ा प्रमाण गुजरात का है, जहाँ सीएसडीएस के सर्वे से प्रमाणित है कि 29 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा को वोट दिए। हिंदूत्व के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शीर्ष नेता लगातार यही स्पष्ट करते रहे हैं कि वे भारत में उत्पन्न 98 प्रतिशत मुस्लिमों को हिन्दू और भारतीय ही मानते हैं, फिर उनकी उपासना पद्धति अलग हो। इसी दृष्टि से मोदी सरकार भी समान नागरिक संहिता के लिए अभियान चला रही है। उत्तराखंड में तो इसके प्रारुप को विधान सभा में पारित कर दिया गया।

तब सवाल उठता है कि मुस्लिम अधिकारों, आरक्षण और हितों के नाम पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता सामाजिक भेदभाव और कटुता क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें असली राष्ट्रवादी नेता कौन है? इस संदर्भ में आजादी से पहले बीसवीं शताब्दी में स्वयं मुस्लिम नेताओं द्वारा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध उठाई गई बातों को याद दिलाना उचित लगता है। अलीगढ़ के प्रसिद्ध विद्वान नेता सर सैय्यद अहमद खान ने 27 जनवरी 1883 को पटना में हिन्दू मुस्लिम एकता पर ऐतिहासिक व्याख्यान देते हुए कहा था - 'हम भारत की हवा में सांस लेते हैं, गंगा यमुना सहित नदियों का जल पीते हैं, भारत की जमीन पर उपजा अनाज खाते हैं। भारत में रहने से शरीर के रंग एक हैं। यदि हम जीवन में धर्म-ईश्वर की बात को अपनी मान्यता के अनुसार रहने दें, तो मानना पड़ेगा कि हमारा देश एक, कौम एक है और देश की तरक्की भलाई, एकता, परस्पर सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है । अनबन , झगड़े और फूट हमें

समाप्त कर देगी। 'यही नहीं पंजाब में हिन्दुओं की एक सभा में उन्होने कहा - ' हिंदुस्तान का हर निवासी अपने को हिन्दू कह सकता है। मुझे इस बात का दुःख है कि आप मुझे हिन्दू नहीं समझते, जबकि मैं भी हिंदुस्तान का वासी हूँ।'

इसी तरह 1896 में लोकमान्य तिलक द्वारा शोलापुर में प्रारम्भ किए गए गणपति उतसव में हिन्दू मुस्लिम सिख पारसी सभी धर्मावलबी शामिल होते थे। उस समय के एक साप्ताहिक अखबार 'रफत गोफतार' ने लिखा था- 'गणपति उत्सव में स्थानीय मुसलमान गणपतिजी का सम्मान करते जुलूसों में शामिल हुए। नासिक में तो गणपति विसर्जन जुलुस का नेतृत्व एक मुस्लिम सज्जन कर रहे थे।' इस समय बिहार बंगाल और वहां के मुस्लिमों को लेकर सर्वाधिक राजनीति हो रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि लार्ड कर्जन ने 1903 में हिन्दू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए ही बंगाल के विभाजन कि योजना पर अमल शुरू किया था। इसके विरुद्ध समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। स्वदेशी रैली हुई और राखी अपील जारी की गई। 1905 में लियाकत हुसैन ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को पत्र लिखकर बंग विभाजन से निपटने के लिए बहिष्कार को एकमात्र उपाय बताया था। बिहार में 1908 और 1909 में हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए सम्मेलनों के आयोजन हुए। उस समय हिन्दू मुस्लिम नेताओं का प्रभाव जनता पर था। बहरहाल अंग्रेजो के कारण बंगाल ही नहीं देश का भी विभाजन हुआ। लेकिन क्या आज उस तरह का कोई बड़ा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता है? कांग्रेस पार्टी में दशकों से प्रमुख स्थानों पर रहे सलमान खुर्शीद या बंगाल में अधीर रंजन चौधरी अपने मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में न तो स्वयं चुनाव जीत पाते हैं, न किसीको जितवा पाते हैं। आर जे डी और समाजवादी या शरद पवार की विभाजित एन सी पी में जो नेता मुस्लिम नेता बढ़ाए गए, उनकी आपराधिक गतिविधियों से देश के किसी राज्य में उनकी विश्वसनीयता मुस्लिम समाज में नहीं बन पाई। ओवैसी भी हैदराबाद और दो चार चुनाव क्षेत्रों को प्रभावित कर पाते हैं। ये सब अपने प्रचार और देशी विदेशी समर्थन से सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय के हितों की ठेकेदारी का दावा करते रहते हैं।

देश में सबसे अधिक मुस्लिम जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। आबादी में इनकी हिस्सेदारी 68.31% है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री थे। वे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे। वे भारत के गृह मंत्री भी रहे। यह भी कांग्रेस से निकले वी पी सिंह के अल्प सत्ता काल में। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देश की कुल आबादी का 16.51 फीसदी यहीं बसता है। इस सूबे में चुनावों में हुई हार-जीत का गणित देश की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साल 2011 की जनगणना पर नजर डाले तो यूपी की कुल आबादी 19.98 करोड़ रही और इसमें 3.84 करोड़ मुस्लिम रहे। इस हिसाब से देखा जाए तो इस सूबे की कुल आबादी में 20.26 फीसदी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की हार-जीत का दारोमदार मुस्लिम नेताओं पर रहता है। ऐसे कुछ असरदार और रौबदार नेताओं में आजम खान, मुख्तार अंसारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं तो इमरान मसूद शफीकुर्रहमान बर्क, नाहिद हसन, हाजी फजलुर्रहमान, एसटी हसन जैसे नेताओं के नाम गिनाए जाते रहे हैं। लेकिन इनके विवादों की चर्चा काम नहीं होती और किसी अन्य राज्य में तो उनका कोई असर नहीं होता। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। जबकि 2019 में 115 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इस बार संसद में 24 मुस्लिम सांसद चुनकर आए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 7, समाजवादी पार्टी के 4, टीएमसी के 5, आईयूएमएल के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो और 2 निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे हैं। इसमें यूसुफ पठान, असदुद्दीन ओवैसी, और इकरा चौधरी जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। फिर भी करीब बीस करोड़ मुस्लिम आबादी में व्यापक प्रभाव रखने वाला क्या कोई एक मुस्लिम नेता है?

यह लेखक के निजी विचार हैं

बांग्लादेश में हुंकार भरते हिंदू

प्रमोद भार्गव
साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार

बांग्लादेश में संक्रमण के इस दौर में पिटते हुए नहीं, बल्कि हुंकार भरते हिंदू दिखाई दे रहे हैं। हिंदुओं का यह बदला रुख न केवल उनके लिए, उनके राष्ट्र का नागरिक बने रहने का अभिमान है, बल्कि शरणार्थी या घुसपैठिए की लाचारी से मुक्त बने रहने का स्वाभिमान भी है। उनकी इस भावना को समान देते हुए मुहम्मद यूनुस को कहना पड़ा है कि हिंदू देश के नागरिक हैं, अतएव उनके प्रति हर प्रकार की हिंसा तत्काल बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी कि हम ऐसी सरकार का गठन करेंगे, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए यह भी कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है यह तय करना होगा कि देशभर में कहीं भी किसी पर कोई हमला नहीं किया जाए। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो यहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कथन इस बात का संकेत है कि यूनुस अब देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव एवं अन्याय नहीं देखेंगे। दरअसल यूनुस बुद्धिजीवी होते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए उन्हें तत्काल शेख हसीना या खालिदा जिया की तरह वोट-बैंक के लिए बहुसंख्यक हित साधने की जरूरत नहीं रह गई है।

बांग्लादेश में एकाएक तख्तापलट के बाद हालात बद से बदतर होते दिखाई दिए हैं। नतीजतन पुलिस बलों ने हड़ताल करके 650 थानों में तलाबंदी कर दी थी। इस कारण अराजकतावादी तत्वों को खुली छूट मिल गई और वे बांग्लादेश में रहने वाली लगभग 1 करोड़ 30 लाख की हिंदू आबादी वाली क्षेत्रों में आक्रमक होते दिखाई दिए। अतएव हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना पड़ा। एक हिंदू महिला के हाथ में हसिया भी दिखा। यह हसिया इस बात का प्रतीक रहा कि यदि किसी महिला से दुराचार की कोशिश अतातांइयों ने की तो हिंदू स्त्री देवी दुर्गा की प्रतीक बनकर प्रतिहिंसक के अवतार में आ जाएगी। अपनी संगठन क्षमता दिखाने की दृष्टि से बांग्लादेश में हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय राजधानी ढाका के शाहबाग में एकत्रित हुए और आगजनी, लूटपाट व हमलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केवल हिंदू ही नहीं थे, बल्कि ईसाई और बौद्ध भी थे। इन लोगों ने हुंकार भरी की 'हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। हम अपना देश (जन्मभूमि) छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और अपने पर हो रहे जुल्मों व बर्बर हिंसा का साहस के साथ प्रतिकार करेंगे। 'बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं। कई हिंदुओं के गांव जला दिए गए। नतीजतन लोगों को पलायन करना पड़ा। इस घटना को लेकर बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद् ने अंतरिम सरकार के नेता मुहम्मद यूनुस को खुला पत्र लिखकर कहा है कि 'अल्पसंख्यकों में गहरी चिंता और अनिश्चितता है। सरकार को तत्काल ऐसे हालातों को संज्ञान में ले। 'संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि 'हम बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ हैं। हम यह तय करना चाहते हैं कि तुरंत बांग्लादेश में चल रही हिंसा को नियंत्रित किया जाए। हम किसी भी नस्ल आधारित हमले या हिंसा भड़काने के उपायों के विरुद्ध खड़े हैं। हालांकि बांग्लादेश में विद्रोही इतने उग्र हैं कि वहां की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को प्रदर्शनकारियों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है। लोग अदालत में घुसते चले गए थे।

इस बीच देखने में आया है कि संयुक्त राष्ट्र और मुहम्मद यूनुस तो हिंदुओं की सुरक्षा की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस और विपक्षी दलों के ओंठ सिले हुए हैं। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की न तो कोई बात की और न ही उनका कहीं कोई उल्लेख किया। कांग्रेस की इस मनस्थिति पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'कांग्रेस राजा और फिलिस्तीन को लेकर बड़ी-बड़ी बाते करती है, वहां के हालात पर समय-समय पर चिंता जताती है। मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलती है। आखिर कांग्रेस को ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को गाजा की तो चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। 'याद रहे कांग्रेस व विपक्ष की इस वोट-बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर में आतंक और अलगाववाद बढ़ा, नतीजतन वहां से पांच लाख से भी ज्यादा हिंदू, सिख और बौद्धों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। क्या कांग्रेस बांग्लादेश में भी हिंदुओं की यही दुर्दशा देखने की इच्छुक है?

हिंदुओं पर हमले, मंदिरों और दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हृदयविदारक घटनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में आम बात रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज की आवाज को मुखर ढंग से उठाया नहीं जा सका है। इसका बड़ा कारण है कि पिछले चार दशकों के दौरान वहां से हिंदुओं की आबादी पांच फीसदी घटकर 13.5 से मात्र 8.5 फीसदी रह गई है। बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन भारत में होता रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाना। परंपरागत रूप से हिंदू वोटर बांग्लादेश में सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद को धर्मनिरपेक्ष बता कर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा तो करती रही हैं, लेकिन हमले की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश अपने कार्यकाल में कभी नहीं लगा पाईं। हिंदू बांग्लादेश में इसलिए कमजोर हुए, क्योंकि पलायन करके भारत का रुख करते गए। यह पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां की सरकार को देश का नागरिक होने के अधिकार को जताया।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस

युवा क्रांति के साथ शांति के नये छंद रचें

ललित गर्ग
वरिष्ठ पत्रकार

युवा क्रांति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, इस क्रांति एवं ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक हो, इसी ध्येय से सारी दुनिया प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाती है। सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आरम्भ किया गया था। यह दिवस मनाने का मतलब है कि युवाशक्ति का उपयोग विध्वंस में न होकर निर्माण में हो। युवा, शांति और सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2250 (9 दिसंबर 2015) शांति को बढ़ावा देने और उग्रवाद का मुकाबला करने में युवा शांति निर्माताओं को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता की अभूतपूर्व स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है, और स्पष्ट रूप से युवाओं को वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थान देता है। पूरी दुनिया की सरकारें युवा के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करें। न केवल सरकारें बल्कि आम-जनजीवन में भी युवकों की स्थिति, उनके सपने, उनका जीवन लक्ष्य आदि पर चर्चाएं हो। युवाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं मूलभूत बातों को लेकर यह दिवस मनाया जाता है।

स्वामी विवेकानन्द ने भारत के नवनिर्माण के लिये मात्र सौ युवकों की अपेक्षा की थी। क्योंकि वे जानते थे कि युवा 'विजनरी' होते हैं और उनका विजन दूरगामी एवं बुनियादी होता है। उनमें नव निर्माण करने की क्षमता होती है। नया भारत निर्मित करते हुए नरेन्द्र मोदी को भी युवाशक्ति को आगे लाना होगा। युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य हैं। वो देश की नींव हैं, जिस पर देश की प्रगति और विकास निर्भर करता है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, जहां नौजवान ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है तो कहीं भ्रष्टाचार बेरोजगारी जैसे हालात हैं। युवा अनेक विसंगतियों एवं बुराइयों से घिरे हैं। विशेषतः युवा अपनी वृद्ध पीढ़ी की उपेक्षा के कारण भी निशाने पर हैं। विश्व की गम्भीर समस्याओं में प्रमुख है नशीले पदार्थों का उत्पादन, तस्करी और सेवन की निरंतर हो रही वृद्धि। युवा पीढ़ी इस जाल में बुरी तरह कैद हो चुकी है। आज हर तीसरा युवक किसी न किसी नशे का आदी हो चुका है। अगर यही प्रवृत्ति रही तो सरकार, सेना और समाज के ऊंचे पदों के लिए शरीर और दिमाग से स्वस्थ युवा नहीं मिलेंगे। एक नशेड़ी पीढ़ी का देश कैसे अपना पूर्व गौरव प्राप्त कर सकेगा? इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत एवं आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। युवा सपनों को आकार देने का अर्थ है सम्पूर्ण मानव जाति के उन्नत भविष्य का निर्माण। यह सच है कि हर दिन के साथ जीवन का एक नया लिफाफा खुलता है, नए अस्तित्व के साथ, नए अर्थ की शुरूआत के साथ, नयी जीवन दिशाओं के साथ। हर नई आंख देखती है इस संसार को अपनी तालगी भरी नजरों से। इनमें जो सपने उगते हैं इन्हीं में नये समाज की, नयी आदमी की नींव रखी जाती है।

यौवन को प्राप्त करना जीवन का सौभाग्य है। जीने की तीन अवस्थाएं बचपन, यौवन एवं बुढ़ापा हैं, सभी युवावस्था के दौर से गुजरते हैं, लेकिन जिनमें युवकत्व नहीं होता, उनका यौवन व्यर्थ है। उनके निस्तेज चेहरे, चेतना-शून्य उच्छ्वस एवं निराश सोच मात्र ही उस यौवन की साक्षी बनते हैं, जिसके कारण न तो वे अपने लिये कुछ कर पाते हैं और न समाज एवं राष्ट्र को ही कुछ दे पाते हैं। वे इतना सतही जीवन जीते हैं कि व्यक्तिगत स्पर्द्धाओं एवं महत्वाकांक्षाओं में उलझकर अपने ध्येय को विस्मृत कर देते हैं। उनका यौवन कार्यकारी तो होता ही नहीं, खतरनाक प्रमाणित हो जाता है। युवाशक्ति जितनी विराट और उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी है। इस परिप्रेक्ष्य में युवाशक्ति का रचनात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग करने की जरूरत है। युवकों से संबंधित संस्थाओं को सचेत और सावधान करना होगा और कोई ऐसा सकारात्मक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहे।

जिंदगी कैसी है पहेली

कोलकाता हमसे बहुत अलग नहीं

पिछले दिनों एक पारिवारिक कार्यक्रम के सिलसिले में कोलकाता जाना हुआ। उत्तर भारत में पले-बढ़े लोगों के लिए बंगाल बिल्कुल परदेसी संस्कृति है। बंगाल आज भी अपनी संस्कृति को महत्व देता है और उत्तर भारत में एक सार्वभौमिक संस्कृति है।

जाने से पहले डर था कि भाषायी समस्या सकती है। यूँ भी पूरे परिवार के साथ कहीं जाने पर आशंका ग्रस्त होना स्वाभाविक है।

हालांकि शहर मेरी आशंकाओं से बिल्कुल विपरीत था। लगभग सभी हिंदी समझ रहे थे वहां। और अंग्रेजी थी ही सहायता के लिए। तो पहली समस्या तो यहीं ख़त्म हो गई।

फिर था शाकाहारी भोजन का मसला क्योंकि यहाँ लगभग सभी सी फूड के शौक़ीन होते हैं. लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ. कोलकाता में भी शाकाहारी भोजन

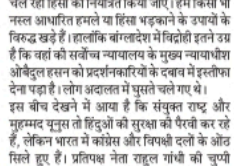

ठीक-ठाक मिल गया।

यहाँ खाना उत्तर प्रदेश के खाने की तरह मसालेदार नहीं होता। एक सादगी होती है जरा सी मिठास के साथ। कच्चे सरसों तेल की खुशबू काफ़ी पसंद की जाती है इधर।

हालांकि, घूमना कोई बहुत ज़्यादा न हो सका. हमारे लखनऊ की तरह कोलकाता भी ओल्ड टाउन और न्यू टाउन में बंटा है। पुराने शहर में जाना नहीं हुआ। पर न्यू टाउन बेहद पसंद आया। जो भी यात्रा गंतव्य हैं वो बहुत ज्ञानवर्धक हैं। एक रिकॉर्ड बुक के साथ ही जाना चाहिए वहां।

सबसे अधिक आकर्षित यहाँ के लोगों के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण ने किया। यहाँ पढ़ने-ल

यूनुस को जिम्मेदारी

मोदी की मुबारकवाद

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को उनके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने पर मुबारकवाद दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक्स' पर मुबारकवाद देते हुए बांग्लादेश में वर्तमान राजनीतिक उथलपुथल के बीच हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों की दयनीय दशा पर चिन्ता प्रकट की है। मोहम्मद यूनुस ने अपनी ओर से कानून-व्यवस्था बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस बीच भारत सरकार ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में अपनी चिन्ताओं पर जोर दिया है। सीमा पार कर भारत में आने का प्रयास करने वाले सैकड़ों लोगों को सीमा सुरक्षा बल ने वापस भेजा है। बांग्लादेश में स्थिति अस्थिर बनी हुई है क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले छात्रों पर 'दुष्ट तत्व' हावी हो गए हैं जो स्थिति का लाभ उठा कर लूट और आगजनी में लिप्त हैं तथा वे जनता का व्यापक समर्थन जुटाने के लिए अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं। धीरे-धीरे पर निश्चित रूप से बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव ने सांप्रदायिक तनावों को भी भड़का दिया है। जनसंख्या का 8-10 प्रतिशत हिस्सा हिंदू अल्पसंख्यक अत्याचारों का बुरी तरह शिकार बने हैं। हालिया खबरों से संकेत मिलता है कि हिंदू मंदिरों, बिजनेसों और घरों पर हमले बढ़ रहे हैं जिससे इस समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल गंभीर रूप ले रहा है।

मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी का संपर्क बांग्लादेश के एक सम्मानित व्यक्ति से संबंध स्थापित करने का सुनियोजित तरीका है जिनकी अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता और प्रभाव है। मोहम्मद यूनुस से संपर्क कर मोदी बांग्लादेश में मानवाधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत के समर्थन का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही वे हिंदू समुदाय की सुरक्षा और बेहतरी के प्रति अपनी चिन्ता भी प्रकट कर रहे हैं। भारत इस समय दुविधा की स्थिति में है। उसने लगातार शेख हसीना का समर्थन किया है और स्थितियों में आमूल परिवर्तन के बावजूद ऐसा कर रहा है। शेख हसीना अब अपने देश में अलोकप्रिय हो गई हैं, जबकि उनके विरोधी बहुत शक्तिशाली हैं। हसीना को अपने खिलाफ जांच में शामिल होने को कहा जा सकता है जिससे भारत द्वंद्व का शिकार हो सकता है। अच्छी बात है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। वे सत्ता के गलियारों में 'बाहरी' व्यक्ति होने के बावजूद एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका ट्रैक रिकार्ड बेदाग है। कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान ने हसीना के तख्तापलट में सहयोग किया है और वे भारत-बांग्लादेश संबंध खराब करना चाहते हैं, ऐसे में मोहम्मद यूनुस भारत के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उनको तटस्थ रहने के लिए मनाया जा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता तथा सांप्रदायिक हिंसा की संभावना शरणार्थी संकट को जन्म दे सकती है। इससे अनेक हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक भारत में शरण मांग सकते हैं। इससे भारत का घरेलू राजनीतिक परिदृश्य खासकर पश्चिम बंगाल और असम के सीमान्त प्रदेशों में जटिल हो जाएगा। बांग्लादेश से व्यापार में गिरावट आई है और शरणार्थी संकट बढ़ रहा है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बनाने में प्रमुख साझीदार है। यह समय गंभीर राजनय का है। प्रधानमंत्री मोदी को शीघ्रातिशीघ्र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करनी चाहिए। हालांकि, ट्विटर राजनय अच्छी शुरुआत है, पर इसके बाद सीधा संपर्क जरूरी हो जाता है। बांग्लादेश में विकास की भावी दिशा भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

बांग्लादेश : अनिश्चितता व अराजकता

बांग्लादेश अतिवादी इस्लामवाद की लहर व बढ़ती हिंसा का शिकार है। ऐसे में वहां लोकतंत्र के भविष्य तथा क्षेत्रीय स्थायित्व पर सवाल उठ रहे हैं।

हिरण्यमय कालेंकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

बांग्लादेश में उथलपुथल के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे कर भारत में पलायन करना पड़ा। इससे दो सवाल पैदा होते हैं। वे इस स्थिति पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकीं? तथा बांग्लादेश और भारत के लिए भविष्य कैसा होगा?

शेख हसीना छात्रों से संपर्क कर उनको अपने पक्ष में ला सकती थीं क्योंकि उनमें से अधिकांश 'मध्यमार्गी' हैं। इस प्रकार छात्रों के भेदभाव-विरोधी आंदोलन-एडीएसएम के जोर पकड़ने के पहले वे इस्लामवादी कट्टरपंथी अतिवादियों को अलग-थलग कर सकती थीं। वे तर्क दे सकती थीं कि उनकी सरकार ने 2018 में ही 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वारिसों को 30 प्रतिशत आरक्षण से वंचित कर चुकी थीं। शुरुआत में छात्रों की यही मांग थी। लेकिन बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने अनेक वारिसों की याचिका पर इसे बहाल कर दिया था। वास्तव में, उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय के अपील विभाग ने 21 जुलाई, 2024 को सरकारी नौकरियों में 93 प्रतिशत भर्ती 'मेरिट' के आधार पर करने का निर्देश दिया था और उसने स्वतंत्रता सेनानियों व उनके वारिसों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया था। इसके साथ ही एक-एक प्रतिशत आरक्षण आदिवासियों तथा दिव्यांगों व यौन अल्पसंख्यकों के लिए किया था। लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी रखने के दो कारण हो सकते हैं।

पहला, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति कठोर व्यवहार जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्रों व अन्य की मौत हुई थी। यह स्थिति इतनी खतरनाक थी कि छात्र आंदोलन वापस नहीं ले सकते थे और अब वे शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। दूसरा, इस्लामवादी आतंकी संगठन उनके आंदोलन के साथ नजदीकी से जुड़ गए थे और वे हसीना और अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटाने के अपने एजेंडे को पूरा करना चाहते थे। इनमें भारतीय उप-महाद्वीप में अलकायदा-एक्यूआईएस से जुड़ा अंसार-अल-इस्लाम, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश-जेएमबी, बांग्लादेश जमातुल इस्लामी-बीजेल व उसकी छात्र शाखा बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर-बीआईसीएस शामिल हैं। उनका इरादा एक कट्टरपंथी इस्लामवादी सरकार बनाना तथा भारत-विरोधी अवस्थापना स्थापित करना था।

शेख हसीना यह सब जानती थीं और उनको कम से कम चार अवसरों पर बांग्लादेश में आक्रामक छात्र आंदोलन के असर का भी पता था। इनमें पहला 'भाषा आंदोलन' था जिसकी मांग केवल उर्दू के बजाय उसके साथ बांग्ला भाषा को लागू कराना था। उर्दू पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बन गई थी और पश्चिम पाकिस्तान की सत्तारूढ़ अवस्थापना इस पर जोर दे रही थी। पुलिस दमन का सामना करते हुए आंदोलन 21 फरवरी, 1952 को अपने शिखर पर पहुंचा जब देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया गया। पुलिस फायरिंग में चार छात्र-रफीक, बरकत, जब्बार और सलाम मारे गए जिनको बांग्लादेश के शहीदों में महत्वपूर्ण स्थान मिला। यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया और उसने पाकिस्तान को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू के साथ बांग्ला को स्वीकार करने पर मजबूर किया। 1958 में जनरल अयूब खान के सैनिक विद्रोह और सैनिक तानाशाही के खिलाफ फिर छात्र आंदोलन भड़का। अयूब सरकार का चरित्र 23 मार्च, 1962 को बनी फर्जी प्रतिनिधिक सरकार के पीछे छिप नहीं सका था। पाकिस्तानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मुक्ति संग्राम में भी छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।

पाकिस्तानी सेना ने ढाका व अन्य विश्वविद्यालयों के परिसरों और हास्टलों पर बर्बर हमले किए थे। रात में किए इस कुख्यात हमले का नाम 'आपरेशन सर्चलाइट' था जिसमें सैकड़ों छात्र 25 मार्च, 1971 की रात मारे गए थे। अंततः फरवरी-मई, 2013 में ढाका में व्यापक 'शाहबाग स्क्वायर आंदोलन' हुआ था जिसने 1971 के युद्ध अपराधियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सरकार ने इस पर इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल्स एक्ट, 1973 में किए 2009 के संशोधन के अनुसार इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल गठित करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना और रज़ाकारों, अल बद्र व अल शम्स के लोगों के खिलाफ जांच कर उनके खिलाफ अभियोजन चलाना था जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार में भाग लिया था।

इन सबको देखते हुए हसीना को नवीनतम छात्र आंदोलन शुरुआत में ही समाप्त कराने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन अब सवाल है कि बांग्लादेश में अब क्या होगा? और भारत को अब क्या करना चाहिए? वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और उनको लूटा जा रहा है। इनमें प्रख्यात ढाकेश्वरी मंदिर भी शामिल है जिसके नाम पर ढाका बसा था। हिंदू दुकानों, बिजनेस अवस्थापनाओं और घरों पर हमले हो रहे हैं। अवामी लीग से जुड़े एक हिंदू पार्षद की हत्या हुई है, अनेक लोग घायल हुए हैं तथा महिलायें यौन हिंसा का शिकार बनी हैं।

शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां गिराई गई हैं या उनको नुकसान पहुंचाया गया है। अवामी लीग के मंत्रियों, नेताओं और एक्टिविस्टों पर हमले हुए हैं और उनके घरों व बिजनेसों को नष्ट किया गया है। खुलना में अवामी लीग पदाधिकारी मोहसिन रजा समेत तीन की हत्या हुई। शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर फिल्म बनाने वाले मोहसिन रजा और उके बेटे शांती खान को मार डाला गया। जैसोर में अवामी लीग नेता के एक होटल में आग लगाई गई जिसमें 24 लोग मर गए। अवामी लीग सांसद व पूर्व बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेटर माशरफ मुर्तजा का घर नष्ट कर दिया गया। ये इस्लामवादी कट्टरपंथियों का विरोध करने वाले अल्पसंख्यकों, अवामी लीग समर्थकों तथा सिविल सोसाइटी तत्वों पर हुए हमलों के केवल कुछ उदाहरण हैं। सवाल है कि अब चीजें सुधरेंगी या और खराब होंगी। बहुत कुछ अंतरिम सरकार पर निर्भर करेगा जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। क्या वे व्यवस्था स्थापित करने में सफल होंगे और वर्तमान हिंसा का कारण बने बीजेल, बीआईसीएस और अंसारुल इस्लाम के समर्थकों पर लगाम लगेगी या स्थिति और खराब होने दी जाएगी। इनमें बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी के नेता भी शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस न कट्टरपंथी हैं और न घोषित भारत-विरोधी। लेकिन उनके अनेक साथियों की पृष्ठभूमि सवाल खड़े करती है। सेना की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खबर है कि वहां शेख हसीना-समर्थक तत्वों या ऐसे लोगों का सफाया किया जा रहा है जो शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक व सहिष्णु बांग्लादेश की इच्छा रखते हैं। यह स्थिति अत्यधिक चिन्ताजनक है। अंतरिम सरकार गठन के बावजूद सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि भावी संसदीय चुनाव कितने स्वच्छ व स्वतंत्र होंगे। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया गया है, इसलिए अंतरिम सरकार को जल्द ही देश में संसदीय चुनाव कराने होंगे।

नई दिल्ली ने उचित ही बांग्लादेश की स्थितियों पर गहरी नजर बनाए रखी है। बांग्लादेश में 2001 से 2006 तक शासन करने वाली बीएनपी-जमात नीत गठबंधन सरकार पूरी तरह भारत-विरोधी थी। उसने सक्रिय रूप से भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी समूहों को न केवल अपने देश में शरण दी थी, बल्कि हथियारों से लैस भी किया था। नई दिल्ली यह बिल्कुल नहीं चाहती है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार बने जो पुरानी सरकार की तरह भारत-विरोधी हो।

इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि वे बांग्लादेश की घटनाओं में 'विदेशी हाथ' की संभावनाओं को खारिज नहीं करते हैं। हालांकि, अपने पद को देखते हुए उनको अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहना होता है। लेकिन इसके बावजूद यह पूर्णतः स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आईएसआई तथा संभवतः चीन का भी इन घटनाओं में हाथ है। पाकिस्तान को अपने ही पाले-पोसे तालिबान से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और चीन को भी इस्लामवादियों से परेशानी हो रही है। ऐसे में उनको विलियम एस. बैरिग-गोल्ड की लिमरिक याद करनी चाहिए-'रीगा की एक युवा महिला ने शेर पर सवारी की। यात्रा समाप्त होने पर महिला शेर के पेट में थी और शेर मुस्करा रहा था।' कट्टरपंथी इस्लामवाद रूपी शेर पर सवारी करने वालों को यह सबक याद रखना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण

ईशान शिवानंद
(लेखक मानसिक स्वास्थ्य शोधकर्ता हैं)

इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि मन, शरीर और आत्मा सूक्ष्म स्तर पर आपस में जुड़े हुए हैं। यह संबंध हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए, हमारी भौतिक वास्तविकता और हमारी शारीरिक स्थिति हमारे मानसिक स्वास्थ्य और प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है।

सच्चे स्वास्थ्य का संकेत मन और शरीर के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन से मिलता है। यहां तक कि एक मामूली असंतुलन भी शारीरिक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से लेकर खुद और जीवन के साथ अधूरेपन की भावना तक कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लगभग 80 प्रतिशत मामले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होते हैं। अवसाद और चिंता जैसी स्थितियां दुनिया की लगभग 9 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करती हैं और विकलांगता के साथ जीने वाले 10 प्रतिशत से अधिक वर्षों के लिए जिम्मेदार हैं। फार्मास्युटिकल उपचार लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य सेवा की आधारशिला रहे हैं, जो गंभीर मामलों के प्रबंधन और स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। ये लक्षित उपचार बायोमार्कर के आधार पर विशिष्ट रोग तंत्र को संबोधित करते हैं, जिससे अधिक व्यक्तिगत उपचार होता है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी की प्रगति इन उपचारों की प्रभावकारिता को बढ़ाती है और रोगी के परिणामों में सुधार करती है। हालांकि, अकेले दवा पर निर्भरता अक्सर मानसिक स्वास्थ्य की समग्र प्रकृति को नजरअंदाज कर देती है।

एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोण, विशेष रूप से योगिक तौर-तरीकों जैसे भारतीय ज्ञान प्रणालियों में निहित, पारंपरिक दवा उपचारों के लिए एक आशाजनक पूरक प्रदान करते हैं। श्वास क्रिया और ध्यान संबंधी प्रोटोकॉल का संयोजन व्यक्तियों को गैर-निर्णयात्मक जागरूकता की एक उच्च अवस्था में प्रवेश करने में मदद करता है। ये आराम और पाचन या विश्राम की एक शारीरिक स्थिति को सक्षम करते हैं, जो उड़ान-या-लड़ाई तनाव प्रतिक्रिया के विपरीत है। तनाव प्रतिक्रिया में यह रुकावट मन और शरीर के बीच संतुलन और

एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है। योग अभ्यास भी कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं। मानव शरीर एक समग्र इकाई है जिसमें एक दूसरे से अविभाज्य विभिन्न परस्पर संबंधित आयाम शामिल हैं। किसी एक आयाम का स्वास्थ्य या बीमारी अन्य को प्रभावित करती है। दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतें अद्वितीय होती हैं और उन्हें इस व्यक्तित्व को स्वीकार करने वाले अनुरूप अभ्यासों के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। योगिक तौर-तरीके व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं: उनके उपचारक बनने के लिए, स्वास्थ्य की ओर उनकी यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए, और स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही, किसी व्यक्ति के मन की गुणवत्ता और स्थिति उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मन-स्थिति उपचार को गति प्रदान करती है, जबकि नकारात्मक मन-स्थिति इसे लम्बा खींच सकती है। लगातार योगाभ्यास अवसाद को कम करने में कारगर साबित हुआ है, जिससे सेरोटोनिन के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और मोनोमाइन ऑक्सीडेज में कमी आती है, जो एक एंजाइम है जो न्यूरोट्रांसमीटर और कोर्टिसोल को तोड़ता है। योग-आधारित हस्तक्षेप हाइपोथैलेमस के सहानुभूति क्षेत्र को बाधित करके अवसादग्रस्तता विकारों, तनाव और चिंता को प्रभेधित करने में भी मदद करते हैं। यह अवरोध तनावपूर्ण उत्तेजनाओं के लिए शरीर की प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करता है और तनाव से जुड़े स्वायत्त विनियामक प्रतिवर्त तंत्र को पुनर्स्थापित करता है। इसके अलावा, योगाध्याय भय, आक्रामकता और क्रोध के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को बाधित करते हैं, जबकि मस्तिष्क में आनंद केंद्रों को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आनंद की स्थिति और कम चिंता होती है। योग और ध्यान के नियमित अभ्यास करने वालों को हृदय गति, श्वसन दर, रक्तचाप और हृदय उत्पादन में कमी का अनुभव होता है।

मानसिक स्वास्थ्य से परे, यौगिक प्रोटोकॉल कार्डियोरेस्पिरेटरी प्रदर्शन, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल और प्लाज्मा मेलाटोनिन के स्तर में सुधार करते हैं। यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप, औसत धमनी दबाव और ऑर्थोस्टेटिक सहनशीलता को काफी कम करता है। योग कार्डियोवैस्कुलर दक्षता और होमोस्टैटिक नियंत्रण को भी बढ़ाता है, जिससे बेहतर स्वायत्त संतुलन, श्वसन प्रदर्शन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। अध्ययनों से पता चला है कि योग-आधारित जीवनशैली में बदलाव कोरोनरी धमनी रोग (सीएडी) के रोगियों में मायोकार्डियल परफ्यूजन में सुधार कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों से अंतर्दृष्टि का लाभ उठाता है, जिसमें फार्मास्युटिकल उपचारों को गैर-फार्मास्युटिकल ध्यान प्रथाओं के साथ जोड़ा जाता है। यह तालमेल न केवल तत्काल लक्षणों को संबोधित करता है बल्कि दीर्घकालिक रिकवरी और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। जैसे-जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटते हैं, प्राचीन प्रथाओं के ज्ञान को अपनाना महत्वपूर्ण है।

योग और अन्य गैर-आक्रामक तरीकों को अपने मानसिक स्वास्थ्य टूलकिट में एकीकृत करके, हम एक संतुलित स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहाँ मन और शरीर सामंजस्य में काम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए केवल गोलियों से ही रास्ता नहीं बनाया जा सकता; कभी-कभी, यह हमारी सांस को खोजने और खुद को उन अभ्यासों में स्थापित करने जितना ही सरल होता है जो हमें हमारे मूल से जोड़ते हैं।

आप की बात

हॉकी में सफलता

पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत कर भारतीयों को अपार खुशी प्रदान की है। सभी भारतीयों के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि भारतीय हॉकी ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक अर्जित किया था। पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी यात्रा शानदार रही। भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को हराया था। उसके बाद अर्जेंटीना को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया था और आयरलैंड को भी हराया था। हालांकि, भारत को एक महत्वपूर्ण मैच में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भारतीय हॉकी टीम ने यह करिश्मा 52 वर्ष बाद करके दिखाया था। भारत ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में उसे जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, इसी के साथ ही भारत का गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी टूट गया था, पर इस हार के बाद भी भारत ने मनोबल बनाए रखते हुए स्पेन पर जीत दर्ज की। ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर चुके भारत के गोलकीपर श्रीजेश के लिए भी एक यह शानदार और ऐतिहासिक विदाई थी। भारत को अब गांवों तक खेलों को लोकप्रिय बनाने का काम करना चाहिए।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

सरोज देवी का बयान

खेल का मतलब है प्रेम, सौहार्द और भाईचारा। ओलंपिक प्रतीक का मतलब ही है पांच महाद्वीपों का मिलन। इस बार ओलंपिक में सबसे भावनात्मक क्षण वो था जब नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने अरशद नदीम को लेकर कहा-हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड के ही बराबर है। गोल्ड जीतने वाला भी हमारा ही लड़का है। मेहनत करता है। उनके इस बयान की चर्चा न सिर्फ सरहद के इस पार और उस पार हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में इसे मानवता, सद्भाव एवं जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोग यह अपनत्व की भावना व्यक्त करने के लिए नीरज चोपड़ा की माता जी की खूब तारीफ़कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख़्तर ने लिखा-गोल्ड जिसका है, वो भी हमारा ही लड़का है। ये बात सिर्फ़ एक मां ही कह सकती है। कमाल है। दोनों देशों के मध्य भले ही बंटवारे के बाद आपसी रंजिश, तनाव, युद्ध एवं बैमनस्य वाला माहौल रहा हो, पर इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान के बीच अटूट पैतृक संबंध बने हुए हैं। हमारी तहजीब, बोली, पहनावा, रहन-सहनए, संस्कृति व रीत रिवाजों में सबंध बने हुए हैं। तमाम दूरियों के बावजूद सरोज देवी का बयान प्रकाश की किरण की तरह है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

बांग्लादेश के कट्टरपंथी

बांग्लादेश का जन्म 1971 में भारतीय सेना के शौर्य के गर्भ से हुआ था आज उसी देश के बहुत से लोग मन्दिरों और हिन्दुओं पर हमले कर भारत-विरोधी माहौल बना रहे हैं। खुशी की बात है कि आखिरकार शेख हसीना ने 57 मुस्लिम देशों को छोड़कर भारत को ही अपने लिए सुरक्षित माना। इसका कारण भारत की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक धरोहर पर विश्वास है जिसके चलते भारत ने कभी अपने प्रति विश्वास को आघात नहीं लगने दिया। यह तथ्य भी भुलाया नहीं जाना चाहिए कि 1975 में अपने पिता मुजीबुर रहमान और परिवार के अधिकांश सदस्यों की सैनिक तख्तापलट में हत्या के बाद शेख हसीना को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में शरण देकर उनकी पूरी सुरक्षा की थी। शेख हसीना 6 साल भारत में रहने के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने पर 1981 में बांग्लादेश वापस गई थीं। लेकिन उस देश के मज़हबी कट्टरपंथियों को शेख हसीना के रूप में एक उदारवादी नेता पसन्द नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पिछले 15 साल में बांग्लादेश का उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ और वह सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में शामिल था। लेकिन दुनिया भर में भीख मांगने वाले पाकिस्तान-समर्थकों को यह बात पसंद नहीं आई।

- नरेन्द्र टोक, मेरठ

बेटियों की भूमिका

प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर-एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कभी बेटियों की भागीदारी केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रहती थी, लेकिन आज भारत की बेटियां जल,थल, नभ और अंतरिक्ष में भी अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही है। वर्तमान में बदलते भारत की तस्वीर का यह यथार्थ है। जीवन के सभी क्षेत्रों में बेटियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही इन तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि उनको आज भी पुरुष वर्चस्व वाले समाज में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कार्पोरेट जगत में उनको सर्वोच्च पदों पर समुचित स्थान नहीं मिल रहा है, वहीं अनेक ग्रामीण व करबाई क्षेत्रों के साथ ही नगरों महानगरों में उनको उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी व लव जिहाद, आदि का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का एक समाधान पुलिस, अर्धसैनिक बलों व अभियोजन के साथ न्यायपालिका में नीचे से लेकर ऊपर तक महिलाओं को समुचित स्थान देना है। यदि इनमें महिलाओं को 50 प्रतिशत स्थान मिल जाए तो बेटियों की प्रतिभा और निखरेगी।

-संजय वर्मा, मनावर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 152

निराशाजनक प्रदर्शन

पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक खेलों में भारत के 117 खिलाड़ियों ने 16 खेलों में हिस्सा लिया। माना जा रहा था कि इन खेलों में देश टोक्यो ओलिंपिक के एक स्वर्ण और दो रजत समेत सात पदकों के प्रदर्शन को बेहतर करेगा। परंतु इन खेलों में हमें एक रजत और पांच कांस्य सहित केवल छह पदक मिले जो बताता है कि भारतीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय बनाने के क्षेत्र में अभी काफी काम करने की आवश्यकता है। खासकर उन खेलों में जिनके बारे में हमारा दावा है कि हम विश्वस्तरीय सुविधाएं रखते हैं। मनु भाकर द्वारा एक ही ओलिंपिक में दो पदक (कांस्य) हासिल करने और अमन सहरावत के देश का सबसे युवा ओलिंपिक पदक विजेता (कुश्ती में कांस्य) बनने के अलावा भारत के प्रशंसकों को खुशी से अधिक निराशा का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अयोग्य घोषित कर दी गईं जिनकी अपील पर फैसला आना बाकी है। भारत कई अवसरों पर करीबी मामले में पदक पाने से चूक गया।

उदाहरण के लिए भाकर 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में बहुत मामूली अंतर से तीसरा पदक पाने से चूक गईं। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में दो बार बढ़त गंवा बैठे और कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में हार कर चौथे स्थान पर रहे। यह उस खेल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था जिसके बारे में उसका दावा है कि उसके पास विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो में रजत पदक जीता था, वह महज एक किलोग्राम वजन कम उठाने के कारण कांस्य पदक पाने से चूक गईं। हॉकी में जहां भारत को विश्व में पांचवीं वरीयता हासिल है, टीम ने लगातार दूसरे ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता लेकिन यहां भी टीम स्वर्ण या रजत पदक जीत सकती थी। जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में ढेर सारे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाने में नाकामी की शाश्वत समस्या के कारण टीम को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाजों को हमेशा पदक का दावेदार माना जाता है लेकिन उन्हें भी खाली हाथ लौटन पड़ा। नीरज चोपड़ा भी टोक्यो में स्वर्ण जीतने का कारनामा दोहरा नहीं सके और उन्हें पेरिस में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कुश्ती में भारत को केवल एक कांस्य पदक मिला। फोगाट को दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद एक ऐसे खेल में यह कमजोर प्रदर्शन है जिसमें भारत वैश्विक शक्ति होने का दावा करता है।

इस कमजोर प्रदर्शन की वजह निर्धारित कर पाना मुश्किल है। यकीनन सरकार के समर्थन में निरंतरता की कमी एक वजह है। उदाहरण के लिए शूटिंग में पदक जीतने वालों में से अधिकांश अच्छे परिवारों से आते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वे प्रशिक्षण और कोचिंग का खर्च उठा सकें। या फिर खिलाड़ी सरकारी सेवा में होते हैं, मसलन नीरज चोपड़ा सेना में जबकि शूटिंग का कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्निल कुसाले आदि सरकारी कर्मचारी हैं। देश के अधिकांश खेल संघों के गैर पेशेवर रवैये ने हालात और भी खराब किए हैं। इन संघों में वरिष्ठ पदों पर राजनेता बैठे हैं जो खिलाड़ियों के कल्याण के बजाय अन्य बातों में रुचि रखते हैं। पिछले वर्ष पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के मुखिया और सत्ताधारी दल के ताकतवर राजनेता बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन इसकी बानगी है। फोगाट का अपने वजन को तय सीमा में रखने के लिए संघर्ष आंशिक रूप से उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का भी परिणाम था। जैसा कि इस श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहलवान ने कहा भी कि पिचले भार वर्ग में लड़ने की तैयारी कम से कम दो साल पहले शुरू होनी चाहिए। फोगाट के पास तैयारी के लिए एक वर्ष से भी कम समय था। पेरिस में भारत का प्रदर्शन 1900 के बाद से दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन था। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की क्षमताओं को यह सही ढंग से नहीं दर्शाता।

सत्ताधारी पक्ष बचाव में और विपक्ष आक्रामक

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस के सभी विचारों को कल्पना से परे बताते हुए खारिज करने से दूरी बना ली है। अब वह उनमें से कई विचारों को लागू भी कर रही है।

हम अक्सर क्रिकेट से जुड़े हालात और रूपकों की मदद से राजनीतिक जटिलताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस समय ओलिंपिक खेल और यूरो कप चल रहे हैं इसलिए हॉकी और फुटबॉल का जिक्र अधिक उचित होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हॉकी या फुटबॉल के खेल में आने वाले बदलाव हमारी राष्ट्रीय राजनीति के परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इनके संकेत संसद के मॉनसून या बजट सत्र में मिले हैं।

ओलिंपिक हॉकी के अंतिम आठ के मुकाबले को याद कीजिए जहां भारत को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ करीब 42 मिनट तक केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा था। इसका फायदा उठाते हुए ग्रेट ब्रिटेन ने लगातार हमले किए और भारत सामने आकर खेलने के लिए संघर्ष करता रहा। परंतु जब कभी भारत ने हमला किया तो खेल एकदम नाटकीय रूप से बदला नजर आया। बुरी तरह हाशिये पर धकेले जाने के बाद जवाबी हमले का ऐसा उदाहरण जबरदस्त है। बचाव के पूरे समय गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजनीति में भी इस समय ऐसा ही हो रहा है।

2024 के आम चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति को नए सिरे से संतुलित किया है और यह बात हम 4 जून से जानते हैं। पूरा विपक्ष एकदम हाशिये पर धकेल दिया गया था और नाउम्मीद हो चुका था। तभी उसे जवाबी हमला करने का अवसर मिला। फर्क यह था कि ज्यादातर लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि जवाबी हमला इतना तगड़ा और प्रभावी होगा कि विजेता को अपनी योजनाएं और रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस दौरान राहुल गांधी को एकदम अलग ढंग से देखा जा रहा है। ध्यान रहे यह वही राजनेता है जिसका हमारे इतिहास में सबसे अधिक मखौल उड़ाया गया है।

अब निष्पक्ष होकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहां उन विचारों और प्रचार अभियान के बिंदुओं की सूची प्रस्तुत है जो कांग्रेस के घोषणापत्र से लिए गए हैं:

- युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर रोजगार बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाए और इंटर्नशिप की योजना बनाई जाए।
- गरीब, बेरोजगारों और किसानों को नकद सहायता दी जाए।
- किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हो और उनकी कर्जमाफी की जाए।
- अग्निपथ योजना पर सवाल।
- राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और उसके बाद लाभ और सहायता का हर वर्ग को उसकी संख्या के आधार पर आवंटन करना।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

इनमें से कई को भाजपा ने झूठ बताकर खारिज कर दिया। जाति से जुड़े मुद्दों की अनदेखी कर दी गई और इसके प्रतिवाद में हिंदू विचारों के उभार का सहारा लिया गया। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के जाति जनगणना के बाद वितरण के समाजवादी रुख को सीधे तौर पर 'रेवड़ी' करार देकर खारिज कर दिया गया। आम भाषा में कहें तो कहा गया कि कांग्रेस मुफ्त उपहारों की मदद से वोट खरीदना चाहती है। अब हमें देखना होगा कि आगे चलकर क्या हुआ।

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में उन विचारों से तेजी से दूर हुई है जिनके तहत वह राहुल गांधी और कांग्रेस के विचारों को कल्पना से परे और मजाक मानती थी। अब वह उनमें से कई को लागू कर रही है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं:

- इस बजट में बेरोजगारी को लेकर उल्लेखनीय आवंटन किया गया है और वादे भी किए गए हैं। कंपनियों को अधिक लोगों को काम देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और पांच साल में एक करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दिलाने की योजना बनाई गई।
- भाजपा की राज्य सरकारें, खासकर जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां की सरकारें पहले ही कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर रही हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने पहले की 14 के मुकाबले अब सभी 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
- अगर आप इन दिनों अखबारों में आ रहे पूरे पन्ने के विज्ञापनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा में मुफ्त उपहारों की झड़ी लगी है। 46 लाख परिवारों को केवल 500 रुपये में एलपीजी सिलिंडर दिए जा रहे हैं। स्कूली छात्राओं के लिए निःशुल्क दूध योजना और नहर जल उपकर की माफी।
- एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के सभी सदस्यों को हर माह 1,000 किमी निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। भाजपा दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसी ही योजनाओं का मखौल उड़ा चुकी है।
- हरियाणा ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को भी छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दिया है।

महाराष्ट्र पर ध्यान देना अधिक श्रेयस्कर होगा। वह पहले ही ऐसी रेवड़ियां घोषित कर चुकी है जो सालाना 96,000 करोड़ रुपये का बोझ डालेंगी। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

- एक खास आय वर्ग के नीचे की महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा वरकारी संप्रदाय (करीब 16 लाख जातिविहीन लोगों का पंथ) को नकद हस्तांतरण तथा सब्सिडी दी जाएगी। वरकारियों को अपने सालाना पंढरपुर तीर्थ के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। संभव है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले योगी भी कांवड़ियों को भी ऐसी ही सुविधा दे दें।
- 21 से 65 आयु वर्ग की जिन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हो उनको हर माह 1,500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसकी लागत करीब 46,000 करोड़ रुपये होगी।
- कक्षा 12वीं पास करने वालों को छह माह तक 6,000 रुपये, डिप्लोमाधारियों को 8,000 रुपये और स्नातकों को 10,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी ताकि वे कौशल प्रशिक्षण ले सकें।
- पांच लोगों वाले हर परिवार को साल में तीन एलपीजी सिलिंडर निःशुल्क दिए जाएंगे।

इन सभी उदाहरणों से यही पता चलता है कि एक दशक तक रक्षात्मक रहा विपक्ष ही इस समय एजेंडा तय कर रहा है। भाजपा जो पहले ऐसे वितरण का मखौल उड़ाती थी वह अब खुद वोट जुटाने के लिए रेवड़ी बांटने में लगी है। विपक्ष ने सत्ताधारी दल को अपनी स्थिति बदलने के लिए विवश किया है।

अगर आप मानते हैं कि यह केवल चुनाव की वजह से हो रहा है तो हम और ठोस बात उठा सकते हैं और वह है हमारी राजनीति में वैचारिक मुद्दे। प्रवास करते हैं यह जानने का कि क्या उपरोक्त दलील यहां भी लागू होती है।

सन 1989 से ही दो बातें यह तय करती रही हैं कि भारत पर कौन शासन करेगा: एक यह कि क्या धार्मिक आधार पर एकजुट लोगों को जाति के आधार पर बांटा जा सकता है? या फिर क्या जाति के आधार पर बंटे हुए लोगों को धर्म के आधार पर एक सूत्र में पिरोया जा सकता है? हमने अक्सर कहा है कि बीते 25 सालों से जाति जीत रही है। मोदी के उभार ने जातियों में बंटे हिंदू मतों को एकजुट किया। हिंदुत्व की चर्चा ने तब जोर पकड़ा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के नारे के साथ इसे चुनौती दी। उन्होंने इसे संसद में उठाया और जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी इसी संसद से जाति जनगणना कराएगी। भाजपा के पास इसका जवाब नहीं है।

जाति के मसले पर जवाब नहीं होने के कारण ही भाजपा धर्म पर बहुत अधिक जोर दे रही है। नया वक्फ विधेयक, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की 'भूमि जिहाद' की बातें, योगी द्वारा 'लव जिहाद' के मामलों में कानून में संशोधन करके आजीवन कारावास की सजा देने का प्रस्ताव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा एक समुदाय पर आबादी नियंत्रित नहीं करने का आरोप आदि इसी वजह से उठाए गए रक्षात्मक कदम हैं।

मेरे मुताबिक यह भ्रम की स्थिति है क्योंकि आम चुनाव में यह कारगर नहीं रहा। भाजपा फिर जाति के प्रश्न से जूझ रही है। जाति जनगणना को भूल जाइए, पार्टी तो 2021 में ही होने वाली सामान्य जनगणना तक की बात नहीं कर रही। भाजपा ने खुद पिछड़ी जातियों की उपश्रेणियों की बात की और दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी के अधीन इसके परीक्षण के लिए एक आयोग गठित किया। उसने अब तक रिपोर्ट नहीं दी। अगर उपश्रेणियां बनेंगी तो जाति जनगणना भी करनी होगी। यह राहुल गांधी की जीत होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हिंदू मतों का जातीय विभाजन जोर पकड़ेगा।

विपक्ष आराम से प्रतीक्षा कर सकता है क्योंकि उसका किसी हिंदीभाषी राज्य में शासन नहीं है। भाजपा संविधान संशोधन के बारे में सोच भी नहीं सकती है क्योंकि चुनाव प्रचार में यह बहुत बड़ा मुद्दा था। उसे अभी भी बहुत हासिल है लेकिन वह रक्षात्मक रुख अपनाकर चुनौती देने वालों से निपटने के लिए जूझ रही है।

आईटीआई: रोजगार कौशल फिर से प्रासंगिक

केंद्र के बजट भाषणों में अब तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को बहुत कम जगह मिली है लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कृषि के बाद अपनी नौ बजट प्राथमिकताओं की सूची में 'रोजगार एवं कौशल विकास' को दूसरा स्थान दिया। विभिन्न सहयोगों के माध्यम से आईटीआई को बेहतर बनाने और रोजगार सृजन करने के लिए 'रोजगार और कौशल विकास' विषय मुख्य आधार बना, जिससे यह बजट पिछले कई बजट से काफी अलग साबित हुआ।

यह संयोग ही सकता है कि देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद रोजगार के मौके तैयार करने के लिए शुरू किए गए आईटीआई को आजादी के 100 वर्ष पूरे होने और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की तैयारी के केंद्र में लाया जा रहा है। आईटीआई एक बार फिर से प्रासंगिक हो गया है लेकिन सवाल यह है कि रोजगार सृजन के अपने प्राथमिक उद्देश्य के लिहाज से उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों और स्नातकों की इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग कौशल देने के संदर्भ में आईटीआई किस जगह पर है?

केंद्र सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, आईटीआई और पूरे कौशल नेटवर्क को नियंत्रित करने वाली नीतियां बनाता है लेकिन इनमें से अधिकांश संस्थान, राज्य सरकारों या राज्यों द्वारा अधिकृत निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे में केंद्र की नीति/पाठ्यक्रम और राज्यों की प्रशिक्षण और रोजगार देने की क्षमता के बीच बेमेलपन स्पष्ट है। कुशल प्रशिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी, प्लेसमेंट के अप्रभावी तरीके, पुराना पाठ्यक्रम और प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण न होना वास्तव में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना आईटीआई को विभिन्न राज्यों में करना पड़ता है।

आईटीआई की स्थापना के दशकों बाद भी इन संस्थानों में प्रभावी प्लेसमेंट सेल स्थापित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले अगस्त में श्रम एवं कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने कौशल विकास मंत्रालय से आईटीआई के लिए प्लेसमेंट और उद्यमिता सेल स्थापित करने का आग्रह किया था। साथ ही समिति ने आईटीआई के लिए अपने स्नातकों के रोजगार की स्थिति पर डेटा अपलोड करना अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने ही इन सिफारिशों पर अमल किया है। संसदीय समिति ने पाठ्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जैसे कि डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में अधिकांश की अभी सार्थक शुरुआत नहीं हुई है।

सामयिक सवाल
निवेदिता मुखर्जी

नीति आयोग ने भी पिछले साल आईटीआई तंत्र से जुड़े एक अध्ययन का जिक्र किया जिसमें बदलाव के सुझाव दिए गए थे। अध्ययन में बुनियादी ढांचे, नियमन और पाठ्यक्रम सामग्री के लिहाज से मौजूदा तंत्र की कमजोरियों के बारे में बताया गया था और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता के लिए एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना सहित सात सूत्री रणनीति का प्रस्ताव दिया गया था।

हालांकि, इस निराशाजनक पृष्ठभूमि के बावजूद कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। इस साल की शुरुआत में आई समाचार रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के आईटीआई ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में 72.3 प्रतिशत की प्लेसमेंट दर हासिल की और कई छात्रों को शीर्ष कंपनियों में नौकरी मिली। दिल्ली के कुछ आईटीआई 94 से 97 प्रतिशत तक की प्लेसमेंट दर हासिल करने में कामयाब रहे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में प्लेसमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में प्लेसमेंट दर 80 प्रतिशत से अधिक है।

रोजगार पर केंद्रित केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ दिनों के भीतर ही वाहन क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हुंडै ने कौशल विकास योजना के तहत नौ राज्यों में कई सौ आईटीआई छात्रों के लिए नए रोजगार के मौके देने की घोषणा की। उसी दौरान तेलंगाना सरकार ने 65 सरकारी आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की।

बजट की तैयारी के दौरान भी आईटीआई से संबंधित कुछ उत्साहजनक उदाहरण सामने आए। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में कई आईटीआई छात्रों की भर्ती जर्मनी से लेकर जापान, सऊदी अरब से लेकर इजरायल तक की विदेशी कंपनियों में की गई। यह राज्य, अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट केंद्र भी स्थापित कर रहा है। हाल ही में, जर्मनी ने कथित तौर पर केरल के संस्थानों से लगभग 4,000 पेशेवरों की भर्ती, रेलवे की आधुनिकीकरण परियोजना के लिए की जिनमें आईटीआई जैसे संस्थान भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हाल ही में बने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में से एक, आईटीआई शिकोहाबाद ने इलेक्ट्रिक वाहनों सहित नए पाठ्यक्रम शुरू किए।

आईटीआई की शुरुआत वर्ष 1948 में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में हुई थी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद अरब-की-सराय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देश के सबसे पुराने आईटीआई में से एक है जिसका नाम कई बार बदला गया है।

आईटीआई के कई दशकों के उतार-चढ़ाव भरे सफर को आंकड़ों से समझा जा सकता है। भारत के लगभग 14,993 सरकारी आईटीआई में 2021-22 में लगभग 25 लाख सीट थीं। प्रशिक्षुओं की संख्या 12 लाख थी। नए नामांकन वर्ष 2014 में हुए 9,46,000 नामांकन से बढ़कर वर्ष 2022 में 12,40,000 (12 लाख) हो गए।

आईटीआई प्लेसमेंट पर व्यापक डेटाबेस के अभाव में, दिल्ली के लोकप्रिय पूसा आईटीआई के ताजा आंकड़ों पर गौर किया जा सकता है। वर्ष 2022 में कुल 659 छात्रों में से 409 की नौकरी लगी, वहीं 101 उच्च शिक्षा के लिए गए और 149 छात्रों की नौकरी नहीं लगी।

हालांकि आंकड़े भी कहानी बताते हैं लेकिन कुछ राज्यों और कुछ संस्थानों द्वारा अलग तरह से काम करने की कोशिशें भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। केवल अधिक बजट खर्च से फर्क नहीं पड़ सकता। इसके बजाय केंद्र और राज्यों को सफल रोजगार के मौके की तलाश में एक नए दृष्टिकोण के साथ एक ही स्तर पर आना होगा।

आपका पक्ष

चीन पर निर्भरता का प्रश्न

इस समाचार पत्र में प्रकाशित लेख 'चीन पर निर्भरता' को आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने या चीन के निवेश या दोनों को भारत के हित में स्थापित करता है। व्यावहारिक पक्ष में प्रथम दृष्टया यही विमर्श सही प्रतीत होता है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावी होना और मुख्यतः आत्मनिर्भरता से सेमी कंडक्टर और ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में चीन या अमेरिका पर निर्भरता समाप्त करने के साथ एक प्रमुख निर्यातक के रूप में स्थापित होना बहुत आवश्यक है। भारत का चीन के साथ 85 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा पिछले कई वर्षों के व्यापारिक घाटे को देखते हुए चिंताजनक नहीं है। भारत चीन के बीच आपसी व्यापार का स्वरूप बदल चुका है और अब केवल अपरिहार्य सेमी कंडक्टर और ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तक सीमित रह गया है जिनकी मांग भी बढ़ी है क्योंकि भारत ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में अग्रणी स्थान ले चुका है। सेमी कंडक्टर और ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के उत्पादन में भारत विभिन्न प्रोत्साहन एवं पीएलआई के माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर है। यह भी तो प्रयास करने की जरूरत है कि चीन भारत से अपना आयात बढ़ाए और भारत के साथ सौहार्द्र स्थापित करे। यह चीन का भी प्रयास हो कि भारत चीन सीमा पर शांति रहे और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में अपना नाजायज अधिकार छोड़ दे। चीन के विस्तारवाद की सीमा यह है कि वह दक्षिण कोरिया को भी अपना भाग मानता है और 16 देशों के भूभाग पर उसका आधिपत्य है। भारत को ही चीन से व्यापार करने और अपने देश में चीनी निवेश की सीख बार बार क्यों दी जाती है और चीन को भारत को एक पड़ोसी देश के साथ यही सौहार्द्र और व्यापार की सीख क्यों नहीं दे जाती? इस एक तरफा संवाद की दिशा बदलनी चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

भारत को चीन से आयात निर्भरता कम करने तथा सेमीकंडक्टर का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है

बांग्लादेश पर रहे पैनी नजर

तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ते शांत देश बांग्लादेश में अचानक ये परिस्थितियां नहीं बनीं कि रातोरात तख्तापलट हो गया। एक के बाद एक गलतियां सरकार करती रही और जनमानस की आग ने दावानल का रूप ले लिया। वर्ष 1971 के मुक्तिदाताओं को 30 फीसदी आरक्षण का मामला युवाओं की प्रमुख मांग थी जिसका विरोध हो रहा था। वर्ष 2018 में अवामी लीग ने इसे हटा भी दिया था परंतु जून 2024 के अदालत के निर्णय ने फिर आग भड़का दी। उस पर शेख हसीना ने आंदोलनकारियों को रजाकार के खिताब से नवाजा तो लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। अतः शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। देश में व्याप्त भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ने लोगों की जिंदगी मुश्किल की हुई थी। बेरोजगारी और महंगाई ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया था। लेकिन सरकार इन सबसे बेफिक्र रही। तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अब भारत को बांग्लादेश के माहौल को बहुत चौकन्ना होकर देखना होगा और सावधान रहना होगा क्योंकि चीन पहले से ही घात लगाए बैठा है।

मुनीश कुमार, रेवाड़ी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना ठाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पेरिस के वर्सेल्स के ट्रायोन में रविवार को परीक्षण के लिए एक वोलोसिटी को तैयार करते वोलोकॉप्टर के कर्मचारी। वोलोकॉप्टर विद्युत से उड़ने वाला विमान है जो एडीपी समूह से जुड़े जर्मन निर्माता वोलोकॉप्टर द्वारा निर्मित है। वोलोसिटी एयर टैक्सी का उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे परिवहन केंद्रों तक ले जाना है।

दैनिक जागरण
प्रसन्नता की कुंजी तो मन के पास होती है

ओलिंपिक में भारत

पेरिस ओलिंपिक के समापन के पहले ही भारत का सफर खत्म हो चुका था। इस बार भारत एक रजत पदक समेत कुल छह पदक ही हासिल कर सका। इस प्रदर्शन को उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत तमाम तैयारी के बावजूद पिछले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा सका। इससे यही रेखांकित होता है कि भारत को खेलों में बड़ी शक्ति बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। पदक तालिका में भारत का स्थान पहले 50 देशों में भी नहीं है। सबसे बड़ी आबादी वाले देश का पदक तालिका में इतना पीछे रहना ठीक नहीं। इस बार कुछ ही खेलों में भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इनमें सर्वोपरि रहे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पिछली बार स्वर्ण पदक जीतकर करिश्मा किया था और इस बार उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। इसके बाद भी वह भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। शूटिंग में मनु भाकर ने भी चमत्कृत करने वाला प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा के साथ युगल प्रतिस्पर्धा में भी सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता। शूटिंग में ही ऐसा ही प्रदर्शन स्वप्निल कुसाले ने भी किया। कुश्ती में अमन सहरावत के कांस्य के रूप में एक ही पदक मिला। विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। पदकों की संख्या कम रह जाने का एक कारण यह भी रहा कि लक्ष्य सेन, अर्जुन बबूटा समेत कई खिलाड़ी चौथे स्थान से आगे नहीं जा सके। हाकी टीम की ओर से लगातार दूसरा कांस्य पदक हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि यही बताती है कि भारतीय हाकी अपने स्वर्णिम दिनों की ओर लौट रही है।

ओलिंपिक में समापन के साथ ही हमारे नीति-नियंताओं, खेल संगठनों, खेल प्रशासकों और स्वयं खिलाड़ियों को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि भारत ओलिंपिक में इतना पीछे क्यों है। यह तो साफ है कि अपने देश में वैसी खेल संस्कृति विकसित नहीं हो सकी है, जैसी अब तक हो जानी चाहिए थी। चूंकि खेल संस्कृति का सही तरह विकास नहीं हो सका है इसलिए विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं की तलाश और उनका समुचित प्रशिक्षण नहीं हो पाता। इस काम में सरकारी विद्यालय भी पीछे हैं और निजी स्कूल भी। विभिन्न खेल संगठन भी खेल प्रतिभाओं की तलाशने और उन्हें निखारने का काम नहीं कर पाते। एक समस्या यह भी है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही अपने करियर की भी चिंता करनी पड़ती है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केंद्र सरकार के साथ कुछ ही राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर दिखती हैं। खेलों और खिलाड़ियों का विकास कैसे हो, इसकी सीख चीन समेत अन्य देशों से भी ली जानी चाहिए। अब जब भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आर्थिक विकास खेलों के विकास में सहायक होता है तब फिर भारत को ओलिंपिक की पदक तालिका में पहले बीस स्थानों में तो अपनी जगह बनानी ही चाहिए।

कड़ी कार्रवाई जरूरी

पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह की चेतावनी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है उसे देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल कदम उठाना चाहिए। प्रोजेक्ट के निर्माण में लगे स्टाफ से मारपीट और जान से मारने की धमकी देना गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस को शिकायत करने के बाद भी समुचित कार्रवाई न होना हैरानीजनक है। यह जांच का विषय है कि जालंधर एवं लुधियाना में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो या कानून व्यवस्था का, यदि केंद्र की ओर से प्रोजेक्टों को रद कर दिया जाता है तो इससे नुकसान पंजाब का ही ज्यादा होगा। खास करके दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे तो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने के बाद पंजाब से जम्मू एवं दिल्ली जाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से पंजाब के व्यापार एवं कारोबार में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। निवेश की संभावना भी बढ़ेगी, जिसकी राज्य को बहुत आवश्यकता है। पंजाब पर तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और बीस हजार करोड़ रुपये केवल ब्याज देने पड़ रहा है। निवेश ज्यादा आएगा तो राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश तभी आएगा जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी। हाईवे निर्माण में लगे स्टाफ को जिन लोगों ने भी धमकी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है।

नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगे स्टाफ से मारपीट और जान से मारने की धमकी देना गंभीर मामला है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए

भारतीय कृषि का अमृतकाल

शिवराज सिंह चौहान

मोदी सरकार में किसानों को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया गया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए

कृषि विकास और किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्न के माध्यम से हमारे जीवन संचालन के सूत्रधार अन्नदाता के जीवन में सुख-समृद्धि लाना हमारा संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। किसान की आय बढ़ाने के लिए हमने छह सूत्रीय रणनीति बनाई है। उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा में राहत की उचित राशि दिलाना, कृषि का विविधीकरण तथा प्रीमियम खेती को बढ़ावा देना इसके अहम पहलू हैं। उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सबसे जरूरी हैं अच्छे बीज, जो कम पानी और विपरीत मौसम में भी बेहतर उत्पादन में सक्षम हो सकें। ऐसे बीजों की 109 नई किस्मों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र और किसानों को समर्पित किया है।

बीते 10 वर्षों में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने का है। वर्तमान में विज्ञान से ही किसानों का कल्याण संभव है। मुझे अपने कृषि विज्ञानियों पर गर्व है जो जलवायु अनुकूल किस्में तैयार कर रहे हैं। कृषि में किए जा रहे नवाचारों से कृषि एवं किसान कल्याण सुनिश्चित होगा।

किसान होने के नाते मैं भलीभांति समझता हूं कि बढ़िया उत्पादन के लिए अच्छे बीज कितने आवश्यक हैं। अगर बीज उन्नत और मिट्टी एवं मौसम की प्रकृति के अनुकूल होंगे तो उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मोदी जी ने यह समझा और व्यापक विजन के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन किया। विविधता भारतीय कृषि की विशेषता है। यहां कुछ दूरी के अंतराल पर ही खेती का मिजाज बदल जाता है। जैसे मैदानी खेती अलग है तो पहाड़ों की खेती अलग। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों की 109 नई किस्में जारी की गईं हैं। इनमें खेती की 69 किस्में और बागवानी की 40 किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी गईं हैं। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने और श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है।

हमारा संकल्प है कि किसान के परिश्रम का उचित मूल्यांकन हो और उन्हें फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भारत की चिंता भी रही है कि मानव शरीर और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन हो। आज भारत नई हरित क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता तथा ईंधनदाता भी बन रहे हैं। पराली, मधुमक्खी पालन, औषधीय खेती, फूलों-फलों की खेती सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा रहा है।

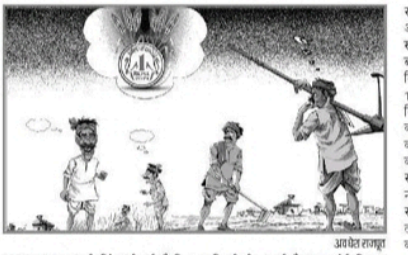

अवधेश राजपूत

पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकता में कृषि और किसान रहे ही नहीं। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27 हजार 663 करोड़ रुपये था जो 2024-25 में बढ़कर 1 लाख 32 हजार 470 करोड़ रुपये हो गया है। यह बजट सिर्फ कृषि विभाग का है। कृषि से संबद्ध क्षेत्रों और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अलग बजट है। मोदी सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है। यूरिया पर सरकार किसानों को करीब 2,100 रुपये सब्सिडी जबकि डीएपी के एक बैग पर 1083 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान स्वावलंबी और सशक्त हुआ है। फसलों के नुकसान पर भी फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है।

मोदी सरकार में किसान को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए। उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। इसी कड़ी में एक लाख करोड़ रुपये की एग्री इन्फ्रा फंड के जरिये कृषि से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पूरे देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसान और विज्ञान को जोड़ रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिये टेक्नोलाजी से दूरदराज की हमारी माताओं-बहनों को भी जोड़ा जा रहा है। कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने के पहले चरण में अब तक 35 हजार कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मोदी जी का विजन है कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में भी रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 निर्यात केंद्रित बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 1500 से अधिक मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही 6,800 करोड़ रुपये की लागत से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने की भी तैयारी है। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल और अन्य उपज के लिए नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार ने यह संकल्प भी लिया है कि दलहन फसलों में तुअर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद एमएसपी पर की जाएगी।

यजुर्वेद में उल्लिखित है 'अन्नान्न पतये नमः क्षेत्राणां पतये नमः' अर्थात अन्न के स्वामी और खेतों के स्वामी अन्नदाताओं को नमन। कृषि पराशर में भी उल्लेख है-अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है एवं अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। किसानों के बिना इस देश का अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी किसानों को प्रणाम किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसका आत्मा। हमारे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा है। आज प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक विजन तथा सर्वांगीण, समावेशी और समग्र विकास वाले सोच के साथ भारत एवं भारतीय कृषि निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई-बहन आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और समृद्ध संपन्न होने के साथ-साथ देश के अन्न भंडार भरते रहेंगे।

(लेखक केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं)

response@jagran.com

जमीन पर उतरती नई शिक्षा नीति

वंदी नारायण

नई शिक्षा नीति तभी साकार रूप ले सकेगी जब उसके अनुरूप पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लागू होने के बाद उसके क्रियान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है कि इस नई शिक्षा नीति के आत्मा को कैसे ज्ञान सृजन एवं शिक्षण में उतारा जाए? हमें समझना होगा कि नई शिक्षा नीति मात्र एक ढांचागत परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के नवनिर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली नीति है। नई शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब इस पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकें जल्द से जल्द तैयार हों। देखा जाए तो नई शिक्षा नीति के दर्शन एवं आत्मा में आजादी के बाद बनीं अनेक राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की निरंतरता दिखाई पड़ती है। इसमें राधाकृष्णन कमेटी एवं डीएस कोठारी कमेटी तथा शिक्षा क्षेत्र में हुए अन्य विमर्शों की छवियां भी दिखाई पड़ती हैं। इसमें अपनी जमीन, अपनी मातृभाषा, अपनी अस्मिता एवं राष्ट्रीयता की छवियां दिखाई एवं उनकी ध्वनियां भी सुनाई पड़ती हैं।

यह जानना सुखद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक निर्माण के कार्य में लगी है। ये पाठ्यपुस्तक छप कर आनें भी शुरू हो गई हैं। अभी हाल में कक्षा छह के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित एवं प्रकाशित पुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियोंड' देखने को मिली। इसका हिंदी संस्करण भी शायद कुछ दिनों में आ जाए। यह पाठ्यपुस्तक बहुत रचनात्मक ढंग से छात्रों में जिज्ञेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं कृतांत क्षमता विकसित करने वाली है। सामाजिक ज्ञान को अपने आसपास के उदाहरणों से सरल भाषा में छात्रों में प्रवाहित करने का बहुत सुंदर प्रयास करती दिखती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की चेतना जगाने की यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इस पाठ्यपुस्तक में अनेक प्रेरणादायी उद्धरणों एवं रचनात्मक अभ्यासों को अत्यंत तारतम्यता से प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऐसे-ऐसे चित्र दिए गए हैं जो किशोर मन को गहराई से छूते हैं। इस प्रकार से छात्रों में सामाजिक विज्ञान से जुड़े ज्ञान को प्रवाहित करने की कोशिश की गई है। साथ ही छात्रों को महत्वपूर्ण तथ्यों और विश्लेषणों को और आकर्षक ढंग से बार-बार ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है।

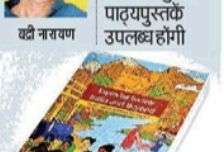

एनसीईआरटी द्वारा तैयार कक्षा छह की पुस्तक। फाइल

भारतीय समाज की विविधता में एकता का भाव इस पाठ्यपुस्तक की एक विशेषता है। इसमें देश की इस विविधता को बनाए रखने पर खासा जोर दिया गया है। इस पाठ्यपुस्तक में शुरू से अंत तक सभी अध्यायों में संवाद के जरिये ज्ञान प्रवाहित करने की रचनात्मक कोशिशें दिखाई पड़ती हैं। भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा को भी अत्यंत निरपेक्ष एवं ज्ञानपरक ढंग से इस पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ते हुए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में 'एक में अनेक' रचने का भाव दिखाई पड़ता है। यह जानना रोचक है कि इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत भारतीय संविधान के मुख्य तत्वों से होती है। यह पाठ्यपुस्तक छात्रों में भारतीय संविधान के मूल आत्मा को प्रवाहित करने का सफल प्रयास करती दिखती है। अत्यंत सरल ढंग से इस पाठ्यपुस्तक में दे पृष्ठों में संविधान में बताए गए मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तुत किया गया है। 'गवर्नेंस एवं डेमोक्रेसी' नामक पाठ में जमीन से जुड़ी अनेक केस स्टडी, प्रेरक व्यक्तित्वों एवं घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन उदाहरणों से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार भारत में पंचायती राज की व्यवस्था ने हाशिये पर बसे अनेक समूहों में भी नेतृत्व विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे आजादी के बाद अनेक आदिवासी एवं सीमांत समूहों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, ट्रांसजेंडर एवं सामाजिक परिवर्तन में लगे तमाम प्रेरक व्यक्तित्वों का एक बड़ा नेतृत्वकारी वर्ग विकसित हुआ है।

इस पाठ्यपुस्तक में परिवार एवं समुदाय पर भी एक अत्यंत उपयोगी पाठ दिया गया है, जिसमें बहुत ही सरलता एवं ग्राह्यपरकता के साथ भारतीय परिवार व्यवस्था को सहजतापूर्वक समझाया गया है। उम्मीद है कि इससे छात्रों में अपने परिवार एवं आसपास के समुदायों के साथ आत्मीय एवं ज्ञानात्मक संबंध विकसित हो पाएगा। इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में विद्यार्थियों के नाम एक छोटा पत्र लिखा गया है, जिसमें इस पाठ्यपुस्तक को कैसे पढ़ें, इसे कैसे समझें, इसके बारे में काफी सरल ढंग से बताया गया है।

जाहिर है, यह एक नवोन्मेषी प्रयास है, जिससे छात्रों को इस पाठ्यपुस्तक से निर्मित होने वाले ज्ञान की संरचना एवं उसका ढंग आसानी से समझ में आ सकता है। यह एक प्रकार से एक 'मास्टर की' की तरह है जिससे यह पुस्तक छात्रों एवं शिक्षकों के लिए खुलती जाती है। इसके अंत में एक व्यूआर कोड भी दिया गया है, जिससे छात्र सामाजिक विज्ञान से जुड़े अत्यंत रोचक ज्ञानपरक वीडियो, पहेली, खेल एवं कहानी देख पाएंगे। इन सबके कारण यह पाठ्यपुस्तक 'नए समय की पाठ्यपुस्तक' के रूप में हमारे सामने आती है। यूं तो एनसीईआरटी हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अपने बेहतर पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए हमेशा प्रशंसित होती रही है, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पाठ्यपुस्तक निर्माण का उसका यह प्रयास बेहद सराहनीय है। हमारे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए यह एक नया अनुभव बनकर सामने आया है। उम्मीद है, इसका सबको लाभ मिलेगा।

(लेखक जीबी पंत समाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भक्ति और सुख

परमपुरुष का गुणगान करना कीर्तन है। संस्कृत में 'कीर्तन' का मतलब है जोर से उच्चारण करना जिससे ध्वनि दूसरों के कानों तक पहुंचे। वैसे परमपुरुष को कीर्तन की प्रतीक्षा नहीं रहती, फिर भी मनुष्य कीर्तन क्यों करता है? वास्तव में इसके पीछे का प्रक्रिया यह है कि मनुष्य स्थूल यानी भौतिक से सूक्ष्म यानी आध्यात्मिक जगत की ओर जाना चाहता है। पहले भी मनुष्य को गाना और नाचना पसंद था। हालांकि यह बहुत स्थूल था। धीरे-धीरे लोगों ने गानों और नृत्य को परिष्कृत किया। भगवान शिव ने विभिन्न छंदों, राग-रागिनियों और तांडव नृत्य का आविष्कार किया। इसी तरह स्थूल से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ने की इस प्रगति को 'नेटनविज्ञान' कहा जाता है। नेटनविज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने सुंदरता और आनंद की अनुभूति की। अंततः यह अवस्था 'मोहनविज्ञान' में बदल जाती है। इसमें व्यक्ति खुद मौहित हो जाता है व स्वयं को भूल जाता है। कीर्तन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां व्यक्ति परमपुरुष को आनंद देने की कोशिश में स्वयं को भूल जाता है।

कीर्तन न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता हासिल करने का भी स्रोत है। इससे व्यक्ति को आत्मिक संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। इसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, क्योंकि कीर्तन के समय उच्चारित होने वाली ध्वनियों और गीतों की लय हमारी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर करती हैं। ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न होने वाली तरंगें हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और इस प्रकार एकाग्रता बढ़ाती हैं। कीर्तन के दौरान जो भावना उत्पन्न होती है, वह हमें परमपुरुष के निकट ले जाती है और हमें शांति का अनुभव कराती है। कीर्तन के माध्यम से हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह हमें आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

धैर्य के साथ लक्ष्य साधें युवा

डा. मोनिका शर्मा

असल में कर्मशील रहने वाले लोग कामयाबी तो पाते ही हैं, उतार-चढ़ाव को झेलने की शक्ति भी जुटा लेते हैं

आस्था का भाव धैर्य की सौगात देता है। धीरता का गुण जीवन के हर लक्ष्य सधना आसान बनाता है। अपने लक्ष्यों को पाने के मार्ग पर बिना रुके-थके आगे बढ़ते रहने का यह व्यावहारिक से भाव है। यह इंसान के मनोविज्ञान को बल देने वाली बात है। हाल ही में पेरिस ओलिंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भारत की डबल मेडल विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने जीत के बाद गीता की चर्चा की। मनु भाकर ने कहा कि 'मैंने बहुत बार गीता पढ़ी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस वही करो जो तुम्हें करना है।' ध्यातव्य है कि मनु भाकर के हिस्से बहुत सी मुश्किलें आईं। टोक्यो ओलिंपिक में पिस्टल में खराबी आने से वह पदक पाने से चूक गईं थीं। नतीजतन, लंबे समय तक अवसाद के दौर से गुजरीं। इन परिस्थितियों में मनु ने गीता पढ़कर कर्मशील रहने की सीख ली। मन को सही दिशा देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफलता पाई। पेरिस में पदक जीतने के बाद मनु ने कहा कि 'मेरे दिमाग में गीता के श्लोक चल रहे थे। मैंने कर्म पर फोकस किया, फल की चिंता नहीं की। मेरे दिमाग में चल रहा था कि वह करो जो आप कर सकते हो और मैंने वही किया।'

जीवन के पीड़ादायी दौर में अवसाद, आत्महत्या और आपराधिक गतिविधियें के घेरे में आने वाली युवापीढ़ी के लिए यह विचारणीय बात है। असल में कर्मशील रहने वाले लोग कामयाबी तो पाते ही हैं, उतार-चढ़ावों को झेलने की शक्ति भी जुटा लेते हैं। देश की युवा खिलाड़ी की प्रतिबद्धता और सकारात्मक सोच, दोनों ही युवाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। युवाओं को समझाते है कि मन की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। इस बल को पाने के लिए मन-जीवन का एक सकारात्मक आधार चुनना चाहिए। यह आपका परिवार, आध्यात्म, योग या अशावादी सोच, कुछ भी हो सकता है। दरअसल, अंतर्मन की शक्ति को साधने के लिए अपने भीतर विश्वास की मजबूत नींव बनना बेहद जरूरी है।

दरअसल, असफलता के दौर में बहुत से युवा जीवन से ही हार मान लेते हैं। अवसाद के घेरे में आ जाते हैं। यही वजह है कि सधी जीवनशैली और सार्थक प्रयास कामयाबी ही नहीं, नाकामयाबी के समय भी आवश्यक हैं। गीता में अनुशासन और स्व-नियंत्रण के महत्व को बहुत सहज ढंग से समझाया गया है। इतना ही नहीं, जीवन के कई मोर्चों पर संयम, संतुलन और प्रबंधन की शिक्षा भी शामिल है। घटकाव भरे इस दौर में बाकई युवाओं को संयमित जीवनशैली अपनाने की जरूरत है। हर हाल में सकारात्मक बने रहने की दरकार है। संयम, समर्पण और निष्ठा से कर्मरत रहने का सोच सांसारिक सफलता की राह दिखाने वाली तो है ही, आत्मिक उन्नति से भी जुड़ा है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

हिंदू एकता का शंखनाद

जहां भीड़तंत्र हावी हो जाता है, वहां लोकतंत्र के लिए स्थान नहीं बचता। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के नाम पर हुई व्यापक हिंसा में वहां सैकड़ों हिंदुओं को हिंसा का शिकार होना पड़ा है। हिंदुओं के खिलाफ की गई यातनाओं से यह साबित हो गया है कि शेख हसीना शासन के दौरान बांग्लादेश के भारत से संबंध प्रगाढ़ होना इस्लामिक कट्टरपंथियों को नहीं पच रहा था। बांग्लादेश के आंदोलन में हिंदुओं को चोट पहुंचाना दुखद है। इस विवाद से भारत-बांग्लादेश के धागा व्यापार पर भी भारी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बेशक इसलामिक कट्टरपंथ के विरोध एवं हिंदुओं के समर्थन में अपनी आंखें, कान और मुंह बंद कर लिए हैं, लेकिन देश-विदेश में हिंदू एकता का शंखनाद सिर चढ़ कर बोल रहा है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

अनिश्चितता से भरा बांग्लादेश

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। सेना उसके साथ है। इसके बावजूद न हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा रुक रही है, न शांति स्थापित हो रही है। यहां तक कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का घेराव कर, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है। इससे तो यही दिख रहा है कि अंतरिम सरकार अराजक आंदोलनकारियों पर आक्रमक सख्ती नहीं बरत रही है। शेख हसीना पर निरंकुश शासक का आरोप लगता रहा है। लेकिन जहां जमात ए इस्लामी जैसे संगठन सक्रिय हों, जो बांग्लादेश की अपेक्षा पाकिस्तान के प्रति अधादर हों। इस आंदोलन में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ने अपने-अपने स्वार्थों के लिए आग में घी डाला। अमेरिका बांग्लादेश के एक द्वीप में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, जो शेख हसीना को मंजूर नहीं था। चीन शेख हसीना के भारत से घनिष्ठ संबंध से चिढ़ता था, उसने पाक के जरिये आंदोलन को हवा दी। पाकिस्तान के मन में तो पुरानी रंजिश है ही, अब उसे अवसर मिल गया। कुल मिलाकर आरक्षण तो मात्र एक बहाना था, असल मकसद शेख हसीना को अपदस्थ करना था। भारत के लिए बांग्लादेश के हालात परेशान करने वाले हैं। एक तो हिंदुओं पर अत्याचार के कारण। दूसरा आशंका यही लग रही है कि नेपाल, मालदीव, म्यांमार की तरह बांग्लादेश भी चीन से अधिक नजदीकी रखेगा। यह सच सिद्ध हुआ तो दोनों के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

सीपी बंसल, दिल्ली

भयंकर एवं त्रासद बांग्लादेश

'अनिश्चितता से घिरा बांग्लादेश' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने भारतीय चिंताओं को तो उजागर किया ही है, साथ ही यह भी बताया कि बांग्लादेश के लिए भी इसमें कई संदेश निहित हैं। आज के सर्वधीम विश्व में बांग्लादेश जैसी घटनाएं आश्चर्यजनक और त्रासद हैं, जो झकझोर कर रख देती हैं। अपने ही देश के एक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लक्ष्य कर उन्हें जान से मारना, उन पर अत्याचार करना, उनकी संपत्ति को तहस-नहस करना भला किस आंदोलन का मकसद हो सकता है। यह कैसा आंदोलन है, जो अपने ही देश में रह रहे एक समुदाय विशेष पर अत्याचारों को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत का बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका से लेकर उसकी तरक्की में भी बहुत योगदान रहा है। जिन देशों के चंदे और शह पर बांग्लादेश में यह सत्ता परिवर्तन हुआ है वे अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने में लगे हुए हैं। इस बात को बांग्लादेश जब तक समझेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इस समय सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा की है जिसके प्रति कार्यवाहक प्रमुख मुहम्मद यूनुस भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लगता है उन्हें अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नगरिकों सहित भारतीय चिंताओं का भी भान है। वह नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत विभूति हैं और विश्व में उनकी प्रतिष्ठा है। हमें आशा करनी चाहिए कि वह बांग्लादेश में अराजक तत्वों को काबू करने में तत्पर होंगे।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रबंध संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *सब जोन में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

15 प्रतिशत के आसपास थी हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में वर्ष 1971 में, जो धीरे-धीरे कम होते हुए अब लगभग आठ प्रतिशत ही रह गई है।

अमिय भूषण
भारतीय संस्कृति के अध्येता

आजकल

बांग्लादेश में सनातन संस्कृति की रक्षा

बीते सप्ताह बांग्लादेश में तख्तापलट के पश्चात मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। इस बीच वहां हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, जिनका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदू इन दिनों सड़कों पर है। चटगांव से लेकर राजधानी ढाका तक प्रदर्शनों का दौर जारी है। वहां की अंतरिम सरकार के सामने अपने जान-माल और हितों की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी मांग रखी है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और सनातन संस्कृति की रक्षा आज एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए हरसंभव उपाय किए जाने चाहिए

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हिंदू समुदाय के लोग। पाइल

वर्तमान का बांग्लादेश अतीत के भारत भूमि का वह भूभाग रहा है, जहां कई आध्यात्मिक विभूतियों ने जन्म लिया है। यह धरित्र शक्ति और आध्यात्मिक सामाजिक चेतना की भाव भूमि रही है। हिंदू संस्कृति का समुच्चय समेटे इस भूमि में कई प्रसिद्ध देवालय एवं तीर्थ हैं। वहीं आध्यात्मिक विभूति एवं सामाजिक मनीषियों की भी इस भूमि ने शृंखला दी है। शक्ति की इस उपासना भूमि पर ढाकेश्वरी और जेशोरेश्वरी जैसे कई प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ हैं। यही नहीं, ढाका का रमणा काली मंदिर अविभाजित भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध काली मंदिर रहा है। बात देवालय एवं तीर्थों की छोड़ भी दें तो यह अपौनिवेशिक दौर के कई क्रांतिकारी स्रोतों की जन्म एवं कर्मभूमि है।

बांग्लादेशी हिंदू इन दिनों अपने देश की सड़कों पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने अपने जान-माल और हितों की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी एक आठ सूत्री मांग रखी है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की इन मांगों पर बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार किस तरीके से काम करती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बांग्लादेश में भय का वातावरण कायम है। बात भले सत्ता परिवर्तन की हो, किंतु एक बार पुनः धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान के बीच पुरजोर संग्राम है।

इस संघर्ष का एक बड़ा कारण इसके पाकिस्तानी अतीत से भी जुड़ा है। तब पहचान के संकट और जातीय उत्पीड़न ने ही बांग्लादेश नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। जिसमें सर्वाधिक आहुति इस भूभाग पर निवास करने वाले हिंदू समुदाय ने ही दी थी। इस शांतिप्रिय सुशिक्षित और संपन्न तबके ने अतीत के जख्मों को भुलाकर ऐसा किया था। बात बांग्लादेश के हिंदू जनता की करें तो वह इनके लिए किसी कीड़े-मकोड़े से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को देख मध्ययुगीन बर्बर मुस्लिम आक्रांताओं की याद आती है। आखिर इसके क्या कारण हैं, इसकी विवेचन से पहले कुछ हालिया घटनाओं को समझन होगा।

वस्तुतः बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर छात्र पिछले कुछ समय से आंदोलित थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गुस्से की आड़ में हिंदुओं के समूलनाश का षड्यंत्र जारी है। जमाती आतंकी छात्रों के दबाव में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश को भी इस्तीफा देना पड़ा है। बांग्लादेश के कार्यवाहक मुखिया मुहम्मद यूनुस का पहला बयान है कि बांग्लादेश एक परिवार है और इसे एकजुट करना है। इसके बावजूद यहां सार्वजनिक संस्थालयों से कला धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है। देश के सभी 65 जिलों में हिंदुओं के घर और मंदिर आततायियों के निशाने पर हैं। मूर्तियां, कलाकृति और ठाकुरबाड़ी आदि तोड़े और जलाए जा रहे हैं। इस हिंसा के दौरान हिंदू पुलिसकर्मी से लेकर चिकित्सक भी निशाने पर हैं। सोचव है कि इनमें से कुछ शेख हसीना के अवामी दल के समर्थक एवं मतदाता भी हो सकते हैं, किंतु क्या इसके आधार पर या फिर इस आक्रोश की आड़ में समुदाय विशेष के प्रति ऐसे जघन्य अपराध की इजाजत दी जा सकती है?

अब तक आई हिंसा की खबरों के अनुसार 52 जिलों में दो सौ से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। सैकड़ों हिंदू घर एवं प्रतिष्ठान तथा तीन दर्जन से कहीं अधिक मंदिरों को निशाना बनाया गया है। ऐसे कई सारे वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर चल रहे हैं जिनमें राह चलते हिंदू युवतियों के साथ घोर आपत्तिजनक और बेहद अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। कम उम्र की लड़कियां और बच्चे वहां शिकार बन रहे हैं। इनका अपहरण और दुष्कर्म भी हिंदू निर्मूलन की दिशा में एक और इस्लामिक बढ़त है। इसके नते धरती के इस भूभाग पर हिंदू आबादी का लगातार कम होना जारी है। इस समुदाय ने यहां कला साहित्य, शिल्प एवं स्थापत्य को सहेजा सजोया है। इन्होंने उद्यम तथा ज्ञान विज्ञान जैसे विधाओं को भी बढ़ाया है, किंतु अब अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। भारत विभाजन के समय इस भूभाग पर 30 प्रतिशत से कहीं अधिक हिंदू आबादी थी। वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान यह संख्या करीब 15 प्रतिशत के आसपास थी, जो धीरे-धीरे कम होते हुए आठ प्रतिशत के आस्पास ही रह गई है।

हिंदुओं के प्रति दोयम भाव : इनके कारणों की विवेचना करें तो इसका एकमेव कारण सभ्यताओं के संघर्ष में सुसंस्कृत समाज का हारना है। क्योंकि विरोधी हर दौर में मूल्य और विचारों से जकड़े लोगों के उलट बर्बरता और छल कपट का पर्याप्त प्रयोग करते हैं। ऐसा ही कुछ अतीत बांग्लादेश का भी है। यहां का हिंदू समाज नजरुल इस्लाम और रवींद्रनाथ के गीत गाता गुनगुनाता रहा। उसके लिए यह भूमि आमार सोनार तो हिंदू मुस्लिम एक परिवारजन थे। किंतु बंगबंधु शेख मुजीबुर से लेकर मुहम्मद यूनुस तक सभी हुक्मरानों के व्यक्तित्व की भलीभांति समीक्षा की जाए तो प्रत्येक में इस्लामिक गाजी ही नजर आएगा।

वहीं पश्चिमी देशों की प्रिय सुशिक्षित नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर यूनुस पद संभालने के बाद से इस हिंसा को रोकने की जगह भारत पर टेपपूर्ण वक्तव्य देने में व्यस्त हैं। वैसे इन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा का निवेदन किया है। ये छात्र जमात नामक संस्था से संबद्ध हैं जिसका एकमेव उद्देश्य लोकतांत्रिक देश को इस्लामिक गणराज्य बनाना है। वैसे जमात के प्रमुख अपनी उद्यस्ता छिपाने के लिए ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा कर रहे हैं, परंतु दूसरी ओर देश के सुदूरवर्ती गांवों में इनके लोगों हिंदुओं पर हमले जारी हैं। इन सबके बीच भारत सरकार और भारत के नागरिकों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि बांग्लादेश में सनातन संस्कृति के प्रति हो रहे कुठाराघात को कैसे रोका जाए?

खरी-खरी

लीकेज का पानी

रेखा शाह आरबी

जब घर की छत टपकती थी, तो जगह जगह बर्तन रख दिए जाते हैं। घर वाले नजरे गड़ाए लीकेज वाली जगह पर देखते रहते हैं कि पानी कहां से आ रहा और किधर तक जा रहा है। इधर-उधर न फैले और आखिर कहां-कहां से लीकेज हो रहा है, इस ओर भी ध्यान रहता है। वैसे तो हर लीकेज खराब है, चाहे वह पैसे का हो, पेपर का हो, पानी का हो या किसी विधान से हो। परंतु चिंताजनक यह है कि लीकेज को रोकने वाले कम लोग हैं और बहते मलाई की बटोरने वाले ज्यादा हैं।

खैर जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर पीपटलाल ने घर बनाया। घर उनकी अकेले की कमाई से बना था। इसलिए वह अपने घर को लेकर बड़े फिक्रमंद थे। अचानक से घर की छत लीकेज होने लगी तो पीपटलाल घबरा गए। लीकेज से गिरते हुए पानी को रोकने के लिए घर के सभी बर्तनों को काम पर लगाया गया। पीपटलाल ने सभी जतन किए, परंतु लीकेज थम नहीं रहा था। चूंकि पीपटलाल आम आदमी थे, इसलिए उनके उपाय भी आम थे। लेकिन जब संसद जैसा भवन लीकेज कर रहा हो, तो इस या तपेले या प्लास्टिक की बाल्टी से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। उसमें अधिक स्टोर नहीं किया जा सकता था। उसके लीकेज को संभालने के लिए कुछ भारी भरकम चीज होनी चाहिए। आम आदमी तो काफी हल्का-फुल्का होता है। एक भी विपत्ति आती है तो अपने को संभाल नहीं पाता है। या तो लुढ़क जाता है या ढिबलिया हो जाता है।

सबसे अच्छा तो यह रहे कि लीकेज की जगह पर नेताओं को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि इनके स्टोरेज की क्षमता अधिक है। ये अपने अंदर अनेक पुलों और योजनाओं को आत्मसात कर लेते हैं। उसके बाद भी डकार नहीं लेते हैं। यह अपने अंदर कितना भी मैटीरियल स्टोर कर लेते हैं। वैसे भी इनका ज्यादा कोई काम तो रहता नहीं है। अपने निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली, दिल्ली से अपने क्षेत्र, तो कम से कम लीकेज की समस्या दूर करने में तो काम आएं। सांसद महोदय की स्टोरेज क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता है। लीकेज वाले मामले से वैसे आप उनकी क्षमताओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं।

जब घर की छत टपकती थी, तो जगह जगह बर्तन रख दिए जाते हैं। घर वाले नजरे गड़ाए लीकेज वाली जगह पर देखते रहते हैं कि पानी कहां से आ रहा और किधर तक जा रहा है। इधर-उधर न फैले और आखिर कहां-कहां से लीकेज हो रहा है, इस ओर भी ध्यान रहता है। वैसे तो हर लीकेज खराब है, चाहे वह पैसे का हो, पेपर का हो, पानी का हो या किसी विधान से हो। परंतु चिंताजनक यह है कि लीकेज को रोकने वाले कम लोग हैं और बहते मलाई की बटोरने वाले ज्यादा हैं।

खैर जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर पीपटलाल ने घर बनाया। घर उनकी अकेले की कमाई से बना था। इसलिए वह अपने घर को लेकर बड़े फिक्रमंद थे। अचानक से घर की छत लीकेज होने लगी तो पीपटलाल घबरा गए। लीकेज से गिरते हुए पानी को रोकने के लिए घर के सभी बर्तनों को काम पर लगाया गया। पीपटलाल ने सभी जतन किए, परंतु लीकेज थम नहीं रहा था। चूंकि पीपटलाल आम आदमी थे, इसलिए उनके उपाय भी आम थे। लेकिन जब संसद जैसा भवन लीकेज कर रहा हो, तो इस या तपेले या प्लास्टिक की बाल्टी से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। उसमें अधिक स्टोर नहीं किया जा सकता था। उसके लीकेज को संभालने के लिए कुछ भारी भरकम चीज होनी चाहिए। आम आदमी तो काफी हल्का-फुल्का होता है। एक भी विपत्ति आती है तो अपने को संभाल नहीं पाता है। या तो लुढ़क जाता है या ढिबलिया हो जाता है।

सबसे अच्छा तो यह रहे कि लीकेज की जगह पर नेताओं को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि इनके स्टोरेज की क्षमता अधिक है। ये अपने अंदर अनेक पुलों और योजनाओं को आत्मसात कर लेते हैं। उसके बाद भी डकार नहीं लेते हैं। यह अपने अंदर कितना भी मैटीरियल स्टोर कर लेते हैं। वैसे भी इनका ज्यादा कोई काम तो रहता नहीं है। अपने निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली, दिल्ली से अपने क्षेत्र, तो कम से कम लीकेज की समस्या दूर करने में तो काम आएं। सांसद महोदय की स्टोरेज क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता है। लीकेज वाले मामले से वैसे आप उनकी क्षमताओं को समझने में सक्षम हो सकते हैं।

पलायन कर शरणार्थी बनने पर विवश न हों हिंदू

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

बांग्लादेश में संक्रमण के इस दौर में पिटते हुए नहीं, बल्कि हुंकार भरते हुए हिंदू दिखाई दे रहे हैं। हिंदुओं का यह रुख न केवल उनके लिए, बल्कि उनके राष्ट्र का नागरिक बने रहने का अभिमान और शरणार्थी या घुसपैठिए की लाचारी से मुक्त बने रहने का स्वाभिमान भी है। उनकी इस भावना को सम्मान देते हुए मुहम्मद यूनुस को कहना पड़ा है कि हिंदू देश के नागरिक हैं, अतएव उनके प्रति हिंसा तत्काल बंद होनी चाहिए। यूनुस ने कहा, 'हम ऐसी सरकार का गठन करेंगे, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा है, तो यह तय करना होगा कि कहीं भी किसी पर कोई हमला नहीं किया जाए।'

दरअसल बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हालात बद से बदतर होते दिखाई दिए हैं। पुलिस बलों ने भी स्वयं को आंदोलनकारी छात्रों से मुकाबले के लिए सक्षम नहीं पाया, लिहाजा 650 से अधिक थानों में ताालाबंदी कर दी थी। इस कारण अराजक तत्वों को खुली छूट मिल गई और वे बांग्लादेश में रहने वाली लगभग एक करोड़ 30 लाख की हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों में आक्रामक होते दिखाई दिए। लिहाजा हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना पड़ा। अपनी संगठन क्षमता दिखाने की दृष्टि से बांग्लादेश में हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय राजधानी ढाका के शहबाग में एकत्रित हुए और आगजनी, लूटपाट एवं हमलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। इस बीच देखने में आया है कि संयुक्त राष्ट्र और मुहम्मद यूनुस तो हिंदुओं की सुरक्षा की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस और विपक्षी दलों के मुंह इस घटना पर पूरी तरह से नहीं खुल रहे हैं। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष का खुलकर नहीं बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हमारे देश में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए चिंता जताई है, परंतु नेता प्रतिपक्ष को भी इस मामले पर मुखरता से बोलना चाहिए, जिसका अभाव ही दिख रहा है। याद रहे कांग्रेस व विपक्ष की इस बोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा मिला, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वहां से पांच लाख से भी ज्यादा हिंदुओं और सिखों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा।

इन सबके बीच बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज की आवाज को मुखर ढंग से उठाया नहीं जा सका है। बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन भारत में होता रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है, राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाना। परंपरागत रूप से हिंदू वोटर बांग्लादेश में सतारूढ़ आवामी लीग के समर्थक रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बताकर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा तो करती रही हैं, लेकिन हमले की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश अपने कार्यकाल में कभी नहीं लगा पाईं। हिंदू बांग्लादेश में इसलिए कमजोर हुए, क्योंकि पलायन करके भारत का रुख करते गए। यह पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां की सरकार को देश का नागरिक होने के अधिकार को जताया। यदि हिंदू इसी दृढ़ता से पेश आते रहे तो उन्हें पलायन करके किसी अन्य देश का शरणार्थी बने रहने की जरूरत शायद नहीं रह जाएगी।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले एक निश्चित पद्धति के अनुसार होते रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं पर हमले की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिसके बाद हमलों का दौर शुरू हो जाता है। उधर सरकार केवल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। यह बात अब वहां के अल्पसंख्यक समझ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हाशिए पर होने के कारण वे कुछ कर नहीं पाते थे। लिहाजा अब वे स्वयं को मजबूत बनाने के प्रयास में जुट चुके हैं।

पोस्ट

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले भारत के छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि उनके 'डीप स्टेट' साथियों को पिछली बार की तरह वे लाभ की उम्मीद है, लेकिन याद रहे कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। विक्रांत@vikrantkumar

हिंडनबर्ग प्रकरण ने कुछ साबित किया हो या नहीं, मगर एक बात जरूर रेखांकित की है कि भारत को बर्बाद करने के लिए उस पर हमले का जोखिम लेने की क्या जरूरत है? हिंडनबर्ग जैसी को खरीद लीजिए और फिर बड़ी फुर्सत के साथ उद्योग जगत से लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी सुविधा से घुन-घुनकर आरोप लगाते रहिए। लोग केकड़े की तरह खुद ही मर मिटेंगे। शिव कांत@shivkant

शेख हसीना को अपदस्थ कर उनके बांग्लादेश से पलायन में अहम भूमिका निभाने वाली सेना ने बांग्लादेशी राजनीति पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि शेख हसीना के निर्देश पर देश में लाकडाउन लगाने से मना करने वाली सेना ने तख्तापलट के बाद नागरिकों पर गोलीबारी से गुरेज नहीं किया। ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या केंद्र सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने से इन्कार कर सही किया?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज तक सवाल
क्या आप मानते हैं कि ओलिंपिक स्तर पर दमदार प्रदर्शन के लिए भारत को नए खेल कार्यक्रम की जरूरत है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

हिंदू के संहार पर चुप हैं सेक्यूलर लोग,
पर गाजे के नाम पर चिल्लाने का रोग।
चिल्लाने का रोग कहां है आज औवैसी,
निकले ना आवाज आज गाजे के जैसी!
जले बांग्लादेश आग चुप क्यों हैं कंगु,
राहुल को भी याद नहीं है क्यों हिंदू!!
- ओमप्रकाश तिवारी

हरिशंकर मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक

उत्तर प्रदेश डायरी

तैयार हो रही एक और घमासान की जमीन

भारतीय जनता पार्टी के लिए यह निराशा से उबरने का बड़ा अवसर है तो सपा-कांग्रेस के लिए यह साबित करने की चुनौती कि लोकसभा चुनाव की सफलता उसके लिए महज संयोग नहीं थी और उसका जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए धमासान तगड़ा होगा और अखाड़ा बनेंगे वे 10 विधानसभा क्षेत्र जहां उपचुनाव होना है। यही वजह है कि मुकाबले की तैयारियां दोनों तरफ से जोरदार हैं। ये 10 विधानसभा क्षेत्र वे हैं, जहां विधायक रहे नौ सदस्य अब संसद हो गए हैं। इनमें से चार सपा, तीन भाजपा और दो एनडीए के सहयोगी दलों के सदस्य हैं। दसवीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के कारण रिक्त हुई है।

भाजपा ने अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तो इसका कारण साफ है कि कई सीटें ऐसे हैं जहां सपा का बोलबाला रहा है और उन पर जीत हासिल करके ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार खड़ा किया जा सकता है। दूसरी ओर सपा अपने जनाधार वाली सीटों को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती, इसलिए वह योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही है, हालांकि उसका हथियार वही पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) है जिसके बूते उसने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हासिल कर ली हैं। कांग्रेस उसके साथ खड़ी दिखाई देगी, लेकिन यह देखने की बात होगी कि उपचुनाव में अखिलेश उसे कितना हिस्सा देते हैं। आमतौर पर उपचुनावों के प्रति उदासीन रहनेवाली बसपा भी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने के लिए तैयार है।

नवनिर्वाचित सांसदों के लिए भी यह चुनौती होगी कि वे स्वयं की रिक्त सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर साबित करें कि उनका जनाधार अभी बरकरार है। भाजपा इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि हर सीट के लिए अलग-अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी दो-दो सीटों की कमान संभाल रहे हैं। योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी ली है और वहां का दौरा भी शुरू कर दिया है। मिल्कीपुर पर भाजपा का खास फोकस इसलिए भी है, क्योंकि यहां से विधायक चुने गए सपा के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद में भाजपा को हराया है। अवधेश का क्षेत्र में प्रभाव भी है। रहा बात कटेहरी क्षेत्र की तो यहां से विधायक चुने गए लालजी वर्मा भी अब सपा से सांसद हैं और क्षेत्र में उनका भी खासा असर है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट एवं ब्रजेश पाठक को कानपुर की सीसामऊ और मैनुरी की करहल सीट का दायित्व दिया गया है। फूलपुर सीट से केशव का कद आंका जाएगा, क्योंकि यहां से वह पूर्व में सांसद रह चुके हैं तो मझवां में भाजपा को निषाद पार्टी से समन्वय बनकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहां निषाद मत चुनाव प्रभावित करते रहे हैं। ब्रजेश पाठक के लिए अलबत्ता बड़ी चुनौती है, क्योंकि करहल सीट सपा का अभेद्य दुर्ग मानी जाती है और पिछले चुनाव में यहां से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं लड़े थे। उनके सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई है और सपा किसी भी कीमत पर इसे गंवाना नहीं चाहेगी। इसीलिए यहां से परिवार के तेज प्रताप यादव को लड़ाने की तैयारी चल रही है।

इसके अलावा गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें मीरापुर में पिछली बार रालोद जीता था जो अब भाजपा के साथ है और इसका असर परिणाम पर देखने को मिल सकता है। सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी है, इसलिए यहां भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाजपा के लिए यह उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं ही संभाल रखी है। उपचुनाव की तैयारियों के बहाने जातीय समीकरणों को तो दुरुस्त किया ही जा सकता है, निष्क्रिय और नाराज कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ फिर से जोड़ना संभव हो सकेगा। इसे उद्देश्य से उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के नेताओं को भी लगा दिया गया है। इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष व महामंत्री शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष भी तैयारियों को समीक्षा कर चुके हैं। कोई दो राय नहीं कि उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए धरातल तैयार करेंगे और ऐसा जीत हासिल करके ही किया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बैठकों व कार्यक्रमों में एक साथ दिखने लगे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा की दस सीटों पर चल रही उपचुनाव की तैयारी। पाइल

छत्तीसगढ़ डायरी

गहमागहमी के बीच कुछ सहमे हुए कदम

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

बस्तर में चित्रकोट जलप्रपात और इंद्रावती नदी उफान पर है और इधर रायपुर में प्रशासनिक एवं राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती जा रही है। राज्यपाल बदल गए हैं। मंत्रियों के दो रिक्त पदों पर निर्णय नहीं हो सका है। स्वतंत्रता दिवस समारोह निकट है और भाजपा नेतृत्व हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। इधर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार नौवें महीने में प्रवेश करने जा रही है। जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज हुई है। इन सबके बीच प्रदेशवासियों का मन-मस्तिष्क कुछ उधेड़बुन में है। सब सरकार ने मतदाताओं से किए गए वादे तो पूरे कर दिए, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के दावों पर काम कुछ सहमा-सहमा सा है। कारण स्पष्ट नहीं हो रहा।

महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है। इसी तरह किसानों से किए वादे के अनुसार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और एकमुश्त भुगतान का वादा भी पूरा किया गया। विकास कार्यों में ऐसी ही स्फूर्ति की उम्मीद है। इस तरह जिन मुख्य वादों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वह लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरे कर दिए गए। अब मसला दावों का है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विपक्ष के जिस नेता पर चुनावी सभाओं में भ्रष्टाचार का सरगना होने के आरोप लगा रहा था, उससे पिछले आठ महीने में एक बार भी पूछताछ तक नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस आलाकमान के लिए एटीएम बना देने के लिए भाजपा द्वारा आरोपित बताया जाता रहा व्यक्ति हाल के दिनों में उलटा प्रदेश सरकार पर हमलावर है। शराब, कोयला परिवहन, सीजीपीएससी, पीडीएस राशन से लेकर गौठान तक के घोटालों के लिए मंचों से नामित व्यक्ति गौर्वश के सड़क पर होने के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। यह मंथन का विषय भी है।

प्रदेश सरकार के सामने चुनौती है कि एक समय सीमा में भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाए, क्योंकि आरोपितों को देरी का फायदा मिलने की भी बातें सामने आ रही हैं। पीडीएस घोटाले के आरोपित वरिष्ठ आइएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की जमानत में गड़बड़ी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के प्रमाण तक सौंप दिए हैं कि आरोपितों ने जमानत देने वाले जज तक से संपर्क कायम कर लिया था। इसीलिए जनता सहमी-सहमी है कि कहीं लंबी न्याय प्रक्रिया भ्रष्टाचारियों को बचाव का रास्ता नहीं दे दे। जांच एजेंसियों के काम में तेजी लाने के लिए अंततः सरकार को ही पहल करनी होगी।

सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित नियुक्ति घोटाले के अन्य आरोपितों के घरों पर छापे और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्ता में आने के बाद विष्णु देव साय सरकार ने सबसे पहले सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआइ जांच की ही घोषणा की थी। अब आवश्यक हो गया है कि अन्य मामलों में भी सीबीआइ, ईडी, ईओडब्लू सहित सभी एजेंसियां कार्रवाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं। कांग्रेस और नक्सलियों के बीच तालमेल के आरोप लगाते रही भाजपा को एक बार और मुद्दा मिल गया है। नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने के आरोप मोहला-मानपुर-अंबागढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार पांच आरोपितों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल का सलाहकार विवेक सिंह भी शामिल है। राजनंदगांव रेंज के आइजी ने दावा किया है कि आरोपितों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की लेवी वसूली कर नक्सलियों तक पहुंचाने का काम किया। अगर यह सही है तो बस्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग को और बल मिल जाता है जो क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं की नक्सलियों से सांठगांठ के आरोप लगाते रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेताओं के झीरम नक्सल हमले में मारे जाने का जख्म अभी भी रह-रहकर जीवंत हो उठता है। मई 2013 के सुकमा जिले के झीरम कांड में 32 लोगों की मौत के आरोपितों में कांग्रेस नेताओं का नाम होने के दावे भी किए जाते रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता सशंकित और भ्रमित हो रहे हैं। सरकार की तरफ से सत्य सामने लाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं।

इन सबके बीच प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुट गई है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं। विष्णु देव साय इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को "जनदर्शन" कार्यक्रम में उन्होंने कांकेर जिला अस्पताल में 1200 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम कर चुकी संतोषी दुर्गा की नारी शक्ति का प्रतीक बताते हुए तिरंगा भेंट कर सहराहे कार्यों के लिए सम्मानित किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि नवंबर में प्रस्तावित स्थानीय निकाय चुनाव की गहमा गहमी और बढ़ने से पहले सरकार की तरफ से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ठोस कदम के परिणाम भी सामने आने लगेंगे।

1200 पोस्टमार्टम करने वाली संतोषी दुर्गा को तिरंगा भेंट करते विष्णु देव साय। सोशल मीडिया से साभार

चिंतन

हिंडनबर्ग को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं

भारत में एकबार फिर से हिंडनबर्ग का बम फूटा है। इस बार निशाने पर सेबी प्रमुख हैं। पहली बार जब इस अमेरिकी निवेश फर्म ने अडाणी समूह को अपने कई आरोपों से लपेटे में लिया था, तब भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। अडाणी समूह के शेयर को रातोरात भारी नुकसान हुआ, निवेशकों के कई करोड़ रुपये डूब गए। उस वक्त शॉर्ट सेलिंग का खेल खेला गया था। भारत में अडाणी समूह विपक्ष के राजनीतिक निशाने पर रहा है, इसलिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो विपक्ष के राजनीतिक आरोपों को बल मिला। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें हिंडनबर्ग के आरोप बेदम साबित हो गए। उस वक्त सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया और पक्षपातपूर्ण शॉर्ट सेलिंग के मकसद से जारी रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा। इस नोटिस का तो हिंडनबर्ग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधबी पुरी बुच व उनके पति पर पर्दे के पीछे निवेश का आरोप मढ़ दिया है। हिंडनबर्ग ने शनिवार रात को जारी एक रिपोर्ट में संदेह जताया है कि अडाणी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख और उनके पति धवल बुच की अडाणी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। आरोप के जवाब में सेबी की प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी शोध एवं निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और चेयरपर्सन की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग के इन आरोपों के जवाब में बुच दंपति ने रविवार शाम को जारी एक विस्तृत बयान में कहा कि आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट के एक फंड में उनका निवेश सिंगापुर स्थित निजी नागरिक के रूप में किया गया था। माधबी के सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होने से दो साल पहले यह निवेश किया गया था। इसके साथ ही दंपति ने कहा कि 2019 से ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार धवल निजी इक्विटी फर्म के रियल एस्टेट पक्ष से नहीं जुड़े हैं। वर्ष 2017 में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में माधबी की नियुक्ति के तुरंत बाद उनकी दो परामर्श कंपनियां निष्क्रिय हो गई थीं। चूंकि, भारत में कई तरह के नियामकीय उल्लंघनों के लिए हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने के बजाय उसने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी चेयरपर्सन की छवि भंजन का विकल्प चुना है। संपदा प्रबंधन कंपनी 360 वन ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में किए गए दावों पर सफाई दी है कि उसके पूर्ववर्ती आईपीई-प्लस फंड-1 ने अडाणी समूह के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया था। कंपनी 360 वन (पूर्व में आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट) ने एक बयान में कहा कि सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का इस निवेश फंड में कुल प्रवाह का 1.5 प्रतिशत से भी कम निवेश था और किसी भी निवेशक की निवेश निर्णयों में कोई संलिप्तता नहीं थी। बुच ने कहा कि फंड ने किसी भी समय किसी भी अडाणी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया। भारतीय कंपनी व नियामकों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित रही है, यह साबित हो चुका है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडाणी ग्रुप ने भी खंडन किया है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। इस बार भी सेबी प्रमुख पर लगे आरोपों पर विपक्ष की राजनीति तेज हो गई है, जो निराशाजनक है। विपक्ष को देखना चाहिए कि एक अमेरिकी फर्म की मंशा क्या है? भारत क्यों निशाने पर है?

मौद्रिक समीक्षा
सतीश सिंह

महंगाई व विकास के बीच संतुलन

मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो दर में बदलाव नहीं करके इसे 6.5 प्रतिशत के स्तर पर यथावत रखा है। इसके पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की गई थी। भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के बावजूद चिंताजनक स्तर पर है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है। मंहगाई को लेकर केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है,ताकि आम आदमी को परेशानी भी नहीं हो और विकास की रफ्तार भी तेज बनी रहे।

महंगाई और विकास के बीच संतुलन साधने के लिए ताजा मौद्रिक समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो दर में बदलाव नहीं करके इसे 6.5 प्रतिशत के स्तर पर यथावत रखा है। इसके पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की गई थी। रिजर्व बैंक मुख्य तौर पर रेपो दर में बढ़ोतरी करके महंगाई से लड़ने की कोशिश करती है। जब रेपो दर अधिक होता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है, जिसके कारण बैंक भी ग्राहकों को महंगी दर पर कर्ज देते हैं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है और लोगों की जेब में पैसे नहीं होने की वजह से वस्तुओं की मांग में कमी आती है और वस्तुओं व उत्पादों की कीमत अधिक होने के कारण इनकी बिक्री में कमी आती है, जिससे महंगाई में गिरावट दर्ज की जाती है।इसी तरह अर्थव्यवस्था में नरमी रहने पर विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाने की कोशिश की जाती है और इसके लिए भी रेपो दर में कटौती की जाती है, ताकि बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर कर्ज मिले और सस्ती दर पर कर्ज मिलने के बाद बैंक भी ग्राहकों को सस्ती दर पर कर्ज दे। मौजूदा समय में महंगाई दर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। केयर एज रेटिंग के अनुसार कर्ज दर के नरम नहीं होने के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में ऋण वृद्धि दर 16 प्रतिशत के आसपास रही है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 14 से 14.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही सकारात्मक है। हालांकि, इसे अपवाद वाली स्थिति कहा जा सकता है। बहरहाल,कर्ज देने की रफ्तार में तेजी बनी रहने के कारण आर्थिक गतिविधियों और विकास दर दोनों में तेजी आ रही है। इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने विकास अनुमान को 7.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।

वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 6.1 प्रतिशत रही थी। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से 1.2 प्रतिशत अधिक है यानी रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7 प्रतिशत लगाया था। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही थी। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार विनिर्माण और खनन के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन से आलोच्य अवधि में विकास दर तेज रही। विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में माइनस 2.2 प्रतिशत रही थी। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 1.9 प्रतिशत रही थी. उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

खुदरा महंगाई अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमत उफान पर रहने का अनुमान है। वैसे, सर्दी में इसमें कुछ नरमी आ सकती है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष

2025 में मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, लेकिन यह स्तर विकास के लिए निर्णायक निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जून महीने में खुदरा महंगाई मई महीने के मुकाबले 0.33 प्रतिशत बढ़कर 5.08 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई, जबकि मई महीने में यह 4.75 प्रतिशत रही थी, जो 12 महीने का निचला स्तर था। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई में कुछ कमी आई थी, लेकिन वह मई महीने से थोड़ी अधिक 4.83 प्रतिशत के स्तर पर थी। जून 2023 में खुदरा महंगाई 4.81 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई 2023 में यह 4.44 प्रतिशत रही थी। महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6 प्रतिशत है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसलिए महंगाई के स्तर के अनुरूप निवेशकों को निवेश करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रतिफल कम मिलेगा। महंगाई का बढ़ना और घटना उत्पाद की माँग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा उत्पाद खरीदेंगे और ज्यादा उत्पाद खरीदने से माँग बढ़ेगी और माँग के मुताबिक आपूर्ति नहीं होने पर उत्पादों की कीमत बढ़ेगी।इस तरह, बाजार महंगाई के दुष्चक्र में फंस जायेगा। बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या उत्पाद की कमी महंगाई का कारण बनता है। वहीं,अगर माँग कम होगी और आपूर्ति ज्यादा होगी तो महंगाई कम होगी।

ग्राहक खुदरा बाजार से सामान खरीदते हैं और बाजार में मौजूद उत्पादों की कीमत में हुए बदलाव को मापने का काम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) करता है। उत्पाद और सेवाओं के लिए जो औसत मूल्य चुकाया जाता है,सीपीआई उसी को मापता है।कच्चे तेल, उत्पादों की कीमतों, निर्माण की लागत के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जो खुदरा महंगाई दर को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में लगभग 300 उत्पाद ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर खुदरा महंगाई दर तय होती है।इसतरह,किसी की क्रय शक्ति को निर्धारित करने में मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तु एवं सेवा दोनों की कीमतों में इजाफा होता है, जिससे ग्राहक की खरीददारी क्षमता कम हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम होती है। फिर,उनकी बिक्री कम हो जाती है, उनके उत्पादन में कमी आती है, कंपनी को घाटा होता है,कामगारों की छंटनी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है आदि। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं और विकास की गति बाधित होती है। विगत कुछ महीनों से उधारी ब्याज दर के उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद भी ऋण वितरण में तेजी आ रही है और विकास दर की रफ्तार भी तेज बनी हुई है। वैसे, ऐसी स्थिति अपवाद वाली है।

एचएसबीसी इंडिया का पीएमआई आंकड़ा जुलाई 2024 में 58.1 रहा, जो जून महीने में 58.3 पॉइंट रहा था और मई महीने में 57.5 पॉइंट रहा, वहीं अप्रैल महीने में यह 58.8 पॉइंट रहा था। यह आंकड़ा आर्थिक गतिविधियों में तेजी को दर्शाता है और 50 पॉइंट से अधिक इस आंकड़े के रहने का अर्थ है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है। भारत में मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई सहनशीलता सीमा के अंदर रहने के बावजूद चिंताजनक स्तर पर है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है। मंहगाई को लेकर केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा संवेदनशील है और यह महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है,ताकि आम आदमी को परेशानी भी नहीं हो और विकास की रफ्तार भी तेज बनी रहे।

(लेखक अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैं, ये उनके अपने विचार हैं। लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।)

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस
डॉ. अशोक कुमार वर्मा

युवाओं को चाहिए नई दिशा

संसार के 195 देश हैं और भारत इनमें जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। इसके साथ ही भारत संसार का सबसे युवा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता था लेकिन आज भारत विश्व का सर्वोच्च जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यूएनएफपीए द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग के व्यक्तियों की है जबकि 65 वर्ष से ऊपर की आयु के मात्र 7 प्रतिशत लोग हैं। संसार में आयु समूह की कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है तथापि भारत की राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को युवा माना जाता है लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तकनीकी विज्ञान, इंटरनेट और संचार साधनों के साथ साथ मोबाइल कंप्यूटर आदि संसाधनों की पहुँच के फलस्वरूप 10 से 11 वर्ष का बच्चा भी मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व हो चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। यद्यपि भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथापि 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 12 अगस्त 2000 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। तब से लेकर हर वर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे के कारणों पर चिंतन करना आवश्यक है। युवा किसी भी देश के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि वह ही देश का भविष्य है। जिस देश का युवा जागरूक होगा वह देश उतनी ही शीघ्रता से विकास की ओर बढ़ेगा। इसीलिए सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने और समाज में उनकी भूमिका और योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। किसी भी देश के विकास में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकसित और विकासशील दोनों देशों में, युवाओं को मानसिक और सामाजिक जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, युवाओं को इन चुनौतियों के बारे में जागरूक करने, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनकी क्षमता का सम्मान करने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।

युवाओं को ऊर्जा, शक्ति और सोच को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाना माता-पिता, समाज और राष्ट्र का दायित्व है। 10 से 18 वर्ष की आयु युवाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। वे अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। वे अपने शिक्षकों, मित्रों, चलचित्रों से बहुत अधिक प्रभावित होकर उनसे सकारात्मक और नकारात्मक सीख लेते हैं। सत्य तो यह है कि ये कच्चे घड़े के समान होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बर्तन आदि बनाता है और जो आकृति वह चाहता है वैसी आकृति बना देता है उसी प्रकार समाज और आसपास के लोग जैसे होते हैं वैसे ही युवा बन जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग वाली युक्ति यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। माँ बच्चे के लिए सबसे प्रथम गुरु है। छत्रपति शिवाजी का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि बाल्यावस्था में ही उनकी माता जी ने उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी। परिणामस्वरूप छत्रपति शिवाजी महान शासक जी नहीं बने अपितु राष्ट्र के महानायक भी बने।

आज युवा पीढ़ी को नई सोच के साथ साथ सकारात्मक दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है। भारत का युवा प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उसकी विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा में ही देश प्रेम, नैतिक मूल्य, पर्यावरण के प्रति सजगता, राष्ट्र के प्रति दायित्व, संस्कार, भारत की संस्कृति और संस्कार के अध्याय जोड़े जाएं ताकि उसका जीवन नैतिकता से पूर्ण हो। महापुरुषों के चरित्र उनकी शिक्षा के अध्याय में जोड़ने की आवश्यकता है। अल्पायु में खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। ऐसे चरित्र उनकी शिक्षा का अध्याय होने चाहिए। क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी थी। इतना ही नहीं शिक्षा के साथ साथ जीविका उपार्जन के लिए कार्यशाला की नियमित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि युवा शक्ति विदेशों की ओर प्रस्थान न करें।

(लेखक पुलिस अधिकारी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन को स्थिर रखना ही है जीवन का सूत्र

संकलित
दर्शन

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असद्दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार सुखानुभव लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छापूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्र में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रतिक्रिया से हर दम चिंता में डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो, जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी न कर सके और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला न हो सके। रावण से लेकर कंस आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो अपने जीवन में अपनी ऐसी ही मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके।

आखिर कर्म ही महान है

संकलित
प्रेरणा

एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहां गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछाः कहां चले गए थे? गांव के सभी लोग तुमें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया, उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूं कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत में मजबूत है लोकतंत्र

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी भी यहां के लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास है। अगर यहां लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास नहीं होता तो लोग लंबी-लंबी कतारों में लगकर अपने वोमदेश का प्रयोग कर सरकारें न चुनते और न ही अपनी मांगों के लिए धरने-प्रदर्शन कर पाते। हाल ही में अमरीकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कितने लोग अपने यहां के लोकतंत्र से खुश या संतुष्ट हैं। इसमें हमारा देश पंहिया का दूसरा और विश्व का तीसरा देश है। यहां लगभग 77 फीसदी नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश या संतुष्ट हैं। हमारे देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाने वाले देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका आदि के लोग अपने लोकतंत्र से उतने संतुष्ट नहीं हैं। यह रपट उन लोगों को भी आईना दिखाती है, जो अपने ही देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। *- किरण कुरे, बलौदा बाजार*

ट्रेंड

नटवर का समृद्ध योगदान

नटवर सिंह के निधन से दुखी हूं। उन्होंने एटमी और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वह अपनी बुद्धिमत्ता के साथ-साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

निधन से दुखी हूं

पूर्व विदेश मंत्री, पद्म भूषण से सम्मानित कुंवर नटवर सिंह जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। -अखिलेश यादव, पूर्व सीएम यूपी

अर्थव्यवस्था में समस्याएं

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बैंकों से लोगों का भरोसा बहाल करने की है। अर्थव्यवस्था के यहाँ तरह की समस्याएं हैं। -सालेहुद्दीन अहमद वित्त व योजना सलाहकार, बांग्लादेश

लोकार्नो को धन्यवाद

इस बेहद तुंदर, सांस्कृतिक, कलात्मक शहर लोकार्नो में बाहे फैलाकर लेरा स्वागत करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। शाहरुख खान को फिल्म्फेयर के 'बेस्ट अल फैशियल अवार्ड-लोकार्नो टूरिज्म' का 'फैशियल लेपर्ड' से सम्मानित किया गया। -शाहरुख खान, अभिनेता

करंट अफेयर

तुर्किये ने इंस्टाग्राम पर लगाया प्रतिबंध हटाया

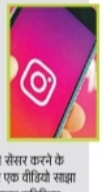

तुर्किये ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच शनिवार को बहाल कर दी। देश के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने दो अगस्त को बिना कोई विशेष कारण बताए इंस्टाग्राम तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी थी। बाद में सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि प्रतिबंध इसलिए लगाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया मंच तुर्किये के कानूनों का पालन करने में विफल रहा है। तुर्किये के परिवहन एवं बुनियादी ढांचा मंत्री अब्दुलक़दिर उरालोग्लू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'इंस्टाग्राम के अधिकारियों के साथ बातचीत में हमें आश्वासन दिया गया कि हमारा अनुरोध स्वीकार किया जाएगा, खासतौर पर आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अनुरोध। हमसे वादा किया गया कि हम उपयोगकर्ताओं को सेंसर करने के उपायों पर मिलकर काम करेंगे।' उरालोग्लू ने 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि इंस्टाग्राम 'तुर्किये के कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और जिन मामलों में कानून का उल्लंघन किया गया है, उनमें त्वरित एवं प्रभावी हस्तक्षेप करेगा।' मंत्री ने कहा कि 'आतंकवादी' संगठनों से जुड़े सभी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ऑफ बीट

खाज एक प्रकार का त्वचा संक्रमण है

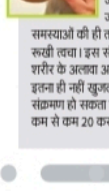

खाज एक प्रकार का त्वचा संक्रमण है, जो सरकोप्टेस स्कैबी (एक प्रकार के सूक्ष्म कीटाणु) के कारण होता है। यह हमारी त्वचा के नीचे पनपता है धीरे-धीरे फैलने लगता है। आमतौर पर इसके लक्षणों में खुजली भरे दाने, त्वचा पर सूजन या छिर खरोंच शामिल हैं। आपको त्वचा फटती भी नजर आ सकती हैं, जो दिखने में मोटी, छोटी या फिर बेरंग लकीरों जैसी प्रतीत होती है। खाज सामान्य रूप से आपके शरीर पर ऐसी जगह होती है, जहां त्वचा आपस में जुड़ती है जैसे उंगलियों के बीच, काख (आर्मपिट) या फिर गुप्तांग वाली जगह। रात में या फिर गर्म पानी से नहाने के बाद खाज ज्यादा तेज होने लगती है। खाज अन्य प्रकार की त्वचा समस्याओं की ही तरह दिखाई देती है जैसे एक्जिमा, सोरायसिस या फिर रूखी त्वचा। इस संक्रामक त्वचा रोग को फैलाने वाला कीट इंसानों के शरीर के अलावा अन्य चीजों पर मुश्किल से 48 घंटों तक जीवित रहता है। इतना ही नहीं खुजली करने से आपको दूसरा जीवाणु (बैक्टीरियल) संक्रमण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनियाभर में कम से कम 20 करोड़ लोगों को कभी न कभी खाज होती है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 12 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

हताश न होना सफलता का मूल है, और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है, और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है।
-वाल्मीकि

वायनाड में आश्वासन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को आश्वासन दिया कि केंद्र वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री वायनाड में जिला कलक्ट्रेट में जमीनी हालात की समीक्षा करने और भूस्खलन पीड़ितों की पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इससे पूर्व वायनाड जाते समय उन्होंने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला, मुंडक्कई और पुंचिरीमट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने एक राहत शिविर का भी दौरा किया और भूस्खलन से विस्थापित हुए कुछ लोगों से बातचीत की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। भूस्खलन की इस आपदा में 226 लोगों की मौत

हो चुकी है, और 130 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते अति मौसमी घटनाओं के कारण आपदाएं आने का सिलसिला बढ़ गया है। देश के पहाड़ी राज्यों में तो इन घटनाओं से जान-माल का खासा नुकसान होता है, और आये साल होने वाली इन घटनाओं के मद्देनजर इन घटनाओं को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग विशेषकर विपक्षी दलों की तरफ से उठती है। वायनाड में भूस्खलन इस आपदा के लिए भी यह मांग जोर-शोर से उठी, लेकिन केंद्र ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार किया है। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार के तत्कालीन गृह राज्यमंत्री मुल्लापल्ली रामंचद्रन द्वारा 2013 में संसद में दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए बल दिया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में 'राष्ट्रीय आपदा' जैसी कोई अवधारणा नहीं है। एक प्रश्न के जवाब में रामचंद्रन ने कहा था कि केंद्र सरकार कई स्थितियों के आधार पर तय करती है कि आपदा की प्रकृति क्या है, जिसमें इसकी तीव्रता, राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने में राज्य सरकार की क्षमता और राहत प्रदान करने के लिए योजना के भीतर उपलब्ध विकल्प आदि को ध्यान में रखा जाता है। प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में तत्काल राहत और सहायता प्रदान करना प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि 'राष्ट्रीय आपदा' के लिए तो कोई निर्धारित मानदंड नहीं है, अलबत्ता, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। बहरहाल, वायनाड भूस्खलन गंभीर किस्म की आपदा करार दी जा सकती है, और इसलिए बेहद जरूरी है कि तमाम संभव उपाय करके प्रभावितों और पीड़ितों को संकट के दंश से उबारा जाए।

सिद्धांतों की अनदेखी

सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सत्रह माह तक जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। अदालत ने अधीनस्थ अदालतों की आलोचना करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई हुए बगैर ही लंबे समय तक जेल में रखे जाने से वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए। सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ यह जमानत मिली है जिसमें पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ अदालत में जमा कराने

और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने, गवाहों को प्रभावित न करने के प्रयास शामिल हैं। पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया की समाज में गहरी पैठ बताई और कहा कि अपीलकर्ता के देश से भागने और मुकदमे का सामना करने के लिए उपलब्ध न होने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने इसे ईमानदारी और सच्चाई की जीत बताई। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नई आबकारी नीति लागू कर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसमें तीन पूर्व सरकारी अफसरों समेत नौ कारोबारी और दो कंपनियां भी दोषी मानी गईं। चूंकि सिसोदिया के पास उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट भी था इसलिए कथित तौर पर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। इस विवाद की शुरुआत से ही आप का दावा है कि भाजपा दिल्ली सरकार की ईमानदार छवि को बिगाड़ने के लिए जान-बूझकर षड़यंत्र कर रही है। जैसा कि सबसे बड़ी अदालत ने कहा जेल अपवाद है, जमानत के नियम हैं, परंतु दोषी साबित होने से पहले ही सजा नहीं प्रारंभ की जा सकती। बार-बार जमानत की अपील खारिज होती रही तथा सवा साल से ज्यादा समय तक सिसोदिया को जेल की सलाखों के भीतर रखना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में जघन्य अपराधियों और सजायाफ्ता आरोपियों को भी जनता की नुमाइंदगी का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में चुने हुए नेताओं के साथ वैमनस्यपूर्ण बर्ताव को सही नहीं ठहरा सकते। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भले हो मगर संविधान का सम्मान रखते हुए जनता के समक्ष उदाहरण पेश करना भी आवश्यक है। अदालती कार्रवाई चालू है, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। धन शोधन के आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान मौजूद है। वास्तव में सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई जरूरी है।

परिधि/ राजीव मंडल

चेतावनी को चुनौती समझें

विकास कार्यों में घनघोर लापरवाही से आजिज आकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पंजाब सरकार को चेतावनी देना अकारण और अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों और ठेकेदारों पर हिंसा और धमकी देने के बाद गडकरी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर यह चेतावनी दी कि अगर मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पंजाब में करीब 14,288 करोड़ रुपए की लागत वाली आठ प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को रद्द कर देगा। अगर राज्य के विकास को लेकर पंजाब सरकार का रवैया वाकई में लचर है तो वह निःसंदेह तकलीफदेह प्रकरण है।

विकास के किसी भी काज में अगर कोई व्यवधान डालता है तो स्पष्ट रूप से वह अक्षम्य है। और सरकार को ऐसे अपराधियों पर सख्ती से नकेल डालने की जरूरत है। अगर प्रशासन का इकबाल खत्म हो जाएगा तो विकास के काम औंधे मुंह गिर जाएंगे। बिहार और झारखंड के वर्षों तक पिछड़ा रहने के पीछे अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल और सरकार की काहिली बड़ी वजह है। नक्सली इलाकों को जब-जब विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश की गई तब-तब अपराधी तत्वों ने उन्हें तंग किया, न केवल तंग किया बल्कि महंगी उपकरण बर्बाद कर दिए और मारपीट कर उन्हें भगा दिया। आज वे दोनों सूबा विकास के पायदान पर कहां हैं, जगजाहिर है। पंजाब को इन राज्यों की बर्बादी से सबक लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस मसले पर सक्रिय होने के साथ ही सख्त बर्ताव दिखाना होगा। आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपनी ऊर्जा खपाने से बेहतर होगा कि वह राज्य में कानून-व्यवस्था का धागा मजबूत करें और विकास के पथ पर सरपट दौड़ें। वैसे भी वह कोई दुष्कर काम नहीं है। हां, इच्छाशक्ति मजबूत रखने से इस मामूली सी बाधा पर पार पाया जा सकता है। दक्षिण भारत के राज्य समेत महाराष्ट्र और गुजरात ने अपने-अपने यहां कानून का राज स्थापित कर प्रगति की है। पंजाब एक समय में बेहद विकसित सूबा था। हालांकि 80 के दशक में आतंकवाद के कारण वह जरूर पिछड़ गया। गडकरी की चेतावनी को भगवंत मान-सम्मान दें और इसे नसीहत के साथ-साथ चुनौती की तरह लें। सब बातों का लब्बो-लुआब तो यही है कि कानून का राज आएगा तो विकास भी सरपट भागेगा।

संदेश की गंभीरता समझें

बांग्लादेश

विनीत नारायण

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं परंतु इन सबमें अहम सवाल भारत और बांग्लादेश के संबंधों का है। पड़ोसी और मित्र होने के चलते जिस तरह भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अपदस्थ नेता शेख हसीना को दिल्ली में शरण दी है वह आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है क्योंकि आम बांग्लादेशियों की नजर में शेख हसीना और भारत एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। ऐसे में अगले कुछ महीने दोनों देशों के रिश्तों के लिए तनाव भरे भी हो सकते हैं। बांग्लादेश में बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत के साथ किस तरह पेश आती है, यह अभी कहा नहीं जा सकता। यह हमारी चिंता का विषय रहेगा।

कई देशों में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत के अनुसार यह ऐसा संकट है जो वाजिब संदेह से परे नहीं है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहीं महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के त्वरित क्रम में, अचानक इस्तीफा, निष्कासन और प्रस्थान अप्रत्याशित था। उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रशासन ने बांग्लादेश को महत्त्वपूर्ण स्थायित्व प्रदान किया। इसके कारण उसकी आर्थिक प्रगति भी प्रभावशाली रही पर साथ ही शेख हसीना के शासन में बढ़े भारी भ्रष्टाचार और उनके अहंकार के साथ-साथ उन पर चुनावों में गड़बड़ी करवाने के आरोपों ने उनकी विरासत को कलंकित किया। अपने ही दल के लोगों को स्वतंत्रता सेनानी बता कर सरकारी नौकरियों में लगातार तीस फीसद आरक्षण देना युवाओं में उनके भारी विरोध का मुद्दा बना।

हालांकि जुलाई के तीसरे सप्ताह में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सुलटा दिया था। फिर भी यह विवाद का बड़ा मुद्दा बना रहा। इसी के चलते 300 से अधिक छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मौत के साथ स्थिति बिगड़ गई। वो महत्त्वपूर्ण मोड़ था जब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह घटनाक्रम श्रीलंका और मिस्र में देखे

गए संकटों की प्रतिध्वनि है। इस बीच, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया की नजरबंदी रद्द कर दी गई है जो फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के करीब मानी जाती हैं। हमारे लिए यह चिंता का कारण है।

उधर, बांग्लादेश की सेना के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं है क्योंकि सेना प्रमुख ने जनता विशेषकर छात्रों से इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के मामले में कार्रवाई और जांच का आश्वासन देते हुए सहयोग मांगा है। ऐसा है तो क्या उठा और अनियंत्रित भीड़ द्वारा शेख हसीना के कार्यालय, आवास और संसद में की गई तोड़फोड़ को नजरअंदाज किया जाएगा? गौरतलब है कि बांग्लादेश के लोगों खासकर युवाओं को लंबे समय तक चलने वाला सैन्य शासन पसंद नहीं है। यदि एक समय के बाद सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण नहीं किया गया तो सेना को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के कुछ जानकर ऐसा भी मानते हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण ही मुद्दा होता तो शेख हसीना जनवरी, 2024 में भारी बहुमत से चुनाव कैसे जीतीं? ऐसा क्या हुआ कि मात्र छह महीनों में ही उन्हें देश छोड़ कर जाने पर मजबूर होना पड़ा? उनका कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अलग होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी जासूस एजेंसी आईएसआई हमेशा से बांग्लादेश में सक्रिय रही है जिसने इस तख्तापलट की पटकथा लिखी है क्योंकि शेख हसीना ने पिछले 15 वर्षों से भारत के साथ अच्छे संबंध रखे और वे भारतीय हितों को पोषित करने वाली मानी जाती थीं जिससे पाकिस्तान बेचैन था। ऐसे पड़ोसी मित्र का सत्ता से अचानक हटना भारत के लिए चिंता का सबब क्या बनेगा? यह अभी कहना मुश्किल है। इस बीच, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया की नजरबंदी रद्द कर दी गई है जो फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के करीब मानी जाती हैं। हमारे लिए यह चिंता का कारण है।

उधर, बांग्लादेश की सेना के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं है क्योंकि सेना प्रमुख ने जनता विशेषकर छात्रों से इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के मामले में कार्रवाई और जांच का आश्वासन देते हुए सहयोग मांगा है। ऐसा है तो क्या उठा और अनियंत्रित भीड़ द्वारा शेख हसीना के कार्यालय, आवास और संसद में की गई तोड़फोड़ को नजरअंदाज किया जाएगा? गौरतलब है कि बांग्लादेश के लोगों खासकर युवाओं को लंबे समय तक चलने वाला सैन्य शासन पसंद नहीं है। यदि एक समय के बाद सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण नहीं किया गया तो सेना को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के कुछ जानकर ऐसा भी मानते हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण ही मुद्दा होता तो शेख हसीना जनवरी, 2024 में भारी बहुमत से चुनाव कैसे जीतीं? ऐसा क्या हुआ कि मात्र छह महीनों में ही उन्हें देश छोड़ कर जाने पर मजबूर होना पड़ा? उनका कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अलग होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी जासूस एजेंसी आईएसआई हमेशा से बांग्लादेश में सक्रिय रही है जिसने इस तख्तापलट की पटकथा लिखी है क्योंकि शेख हसीना ने पिछले 15 वर्षों से भारत के साथ अच्छे संबंध रखे और वे भारतीय हितों को पोषित करने वाली मानी जाती थीं जिससे पाकिस्तान बेचैन था। ऐसे पड़ोसी मित्र का सत्ता से अचानक हटना भारत के लिए चिंता का सबब अवश्य है। प्रश्न है कि भारत जैसे मजबूत देश और भारत का एक तेज-तर्रार खुफिया तंत्र होने के बावजूद ढाका में होने वाले राजनैतिक घटनाक्रम की भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या इसे भी पुलवामा की तरह 'इंटेलिजेंस फेलियर' माना जाए? उल्लेखनीय है कि 1975 में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बांग्लादेश में तख्तापलट की भनक लगी तो तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक सप्ताह पहले ही हेलीकॉप्टर भेज कर शेख मुजीबुर रहमान को भारत में शरण लेने की सलाह दी थी, परंतु वे नहीं माने। परिणामस्वरूप उन्हें और उनके बेटों और परिवार के 17 सदस्यों को ढाका में उनके घर में ही मार दिया गया। यदि उसी तरह हमारी खुफिया एजेंसियां ढाका में होने वाले ताजा घटनाक्रम की खबर समय रहते दे देतीं तो शायद प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश को संकट से बचा भी सकते थे।

दूसरी ओर, यदि हमारे पास घटनाक्रम की जानकारी थी तो हमने बांग्लादेश के समर्थन में समय रहते कठोर कदम क्यों नहीं उठाए? विदेशी मामलों के ये जानकार यह भी कहते हैं कि भारत ने 2014 तक अपनी कूटनीति के चलते दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को अपने पांव पसारने नहीं दिए। नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत सहित सात देशों के समूह ने भारत की पहल पर ही साक्र का गठन किया जिसमें पाकिस्तान के अलावा भारत के सभी से अच्छे संबंध रहे, परंतु किन्हीं कारणों से हमारी विदेश नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि 2015 के बाद से साक्र देशों की एक भी बैठक नहीं हुई। साक्र के बिखरते ही चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते पहले पाकिस्तान और फिर भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए परंतु यह सब होते हुए हम चुपचाप बैठे देखते रहे।

नतीजतन, आज भारत चारों ओर से चीन के प्रभाव वाले पड़ोसियों से घिर गया है। अब छोटे से देश भूटान को छोड़कर कोई हमारा मित्र नहीं है। बांग्लादेश के साथ हमारा लाखों करोड़ का व्यापार चल रहा है। दोनों देशों के बीच काफी लंबी सीमा भी लगती है जो हमारी बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हमारे लिए यह होगा कि बांग्लादेश में जो भी सरकार चुनी जाए वह भारत के हित की ही बात करे बल्कि जहां हमारी दो सीमाएं पहले से ही नाजुक स्थिति में हैं, कहीं हम चारों ओर से दुश्मनों से घिर न जाएं। अब यह उत्सुकता से देखना होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बाद जो भी सरकार बने वह भारत के साथ कैसे संबंध रखती है। इसलिए ढाका में हुए घटनाक्रम को दिल्ली को गंभीरता से लेना होगा।

कई देशों में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत के अनुसार यह ऐसा संकट है जो वाजिब संदेह से परे नहीं है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्तारूढ़ रहीं महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का बांग्लादेश में हो रहीं घटनाओं के त्वरित क्रम में, अचानक इस्तीफा, निष्कासन और प्रस्थान अप्रत्याशित था। उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रशासन ने बांग्लादेश को महत्त्वपूर्ण स्थायित्व मिला था

जिस किसी को नेहरू-इंदिरा युग की ज्यादा जानकारी की दरकार होती तो नटवर सिंह संदर्भ व्यक्ति थे जिनकी याददाश्त गजब की थी...मुझे व्यक्तिगत रूप से ऑन-ऑफ रिकार्ड बातचीत में इससे काफी फायदा हुआ। राजनयिक, लेखक, राजनेता, सही मायने में उनके व्यक्तित्व के विविध आयाम थे। और हां, वह साठ के दशक के क्रिकेट स्कोरों को चुटकियों में याद दिला देते थे। ॐ शांति!

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार@sardesairajdeep

जीवित रहे संस्कृति का संरक्षण

आर्थिक प्रगति

प्रह्लाद सबनानी

किसी भी देश में सत्ता का व्यवहार उस देश के समाज की इच्छा के अनुरूप ही होने के प्रयास होते रहे हैं। जब-जब सत्ता द्वारा समाज की इच्छा के विपरीत निर्णय लिए गए हैं अथवा समाज के विचारों का आदर सत्ता द्वारा नहीं किया गया है तब-तब उस देश में सत्ता परिवर्तन होता दिखाई दिया है। लोकतंत्र में तो सत्ता की स्थापना समाज द्वारा ही की जाती रही है। साथ ही, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए देश में शांति बनाए रखना सबसे पहली आवश्यकता मानी जाती है। समाज में विभिन्न मत पंथ मानने वाले नागरिक आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे तो शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकेगी।

भारत पिछले लगभग 2000 वर्षों के खंडकाल में से अधिकतम समय (लगभग 250 वर्षों के खंडकाल को छोड़कर) पूरे विश्व में आर्थिक ताकत के रूप में अपना स्थान बनाने में सफल रहा और इसे 'सोने की चिड़िया' कहा जाता रहा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भी भारत की आर्थिक प्रगति पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा था परंतु 1750 ईस्वी में अंग्रेजों (ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में) के भारत में आने के बाद से भारत की आर्थिक प्रगति को जैसे ग्रहण ही लग गया था। आक्रांताओं एवं अंग्रेजों ने न केवल भारत को जमकर लूटा, बल्कि भारत की संस्कृति पर भी गहरी चोट की थी और भारत के नागरिक जैसे अपनी जड़ों से कटकर रहने लगे थे। आक्रांताओं एवं अंग्रेजों के पूर्व भी भारत पर आक्रमण हुए थे, शक, हूण, कुषाण आदि ने भी भारत पर आक्रमण किया था परंतु लगभग 250/300 वर्षों तक भारत पर शासन करने के उपरांत उन्होंने अपने आपको भारतीय सनातन संस्कृति में ही समाहित कर लिया था। इसके ठीक विपरीत आक्रांताओं एवं अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत की लूटखसोट करने के साथ ही अपने धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी था। आक्रांताओं ने जोरजबरदस्ती एवं मारकाट मचाकर भारत के मूल नागरिकों का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाया तो अंग्रेजों ने लालच का सहारा लेकर एवं दबाव बनाकर भारतीय नागरिकों को ईसाई बनाया। कुछ

विदेशी ताकतों द्वारा भारत में आज पुनः इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि हिन्दू समाज को किस प्रकार आपस में लड़ाकर छिन्न-भिन्न किया जाए। ऐसा विमर्श खड़ा करने का प्रयास हो रहा है कि देश में हिन्दू हैं ही नहीं, बल्कि सिख हैं, दलित हैं, राजपूत हैं, जैन हैं आदि-आदि। जातियों के आधार पर जन गणना की मांग की जा रही है ताकि समस्त सुविधाओं को हिन्दू समाज की विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जा सके जिससे अंततः देश में विभिन्न जातियों के बीच झगड़े पैदा हों और इस प्रकार भारत को पुनः गुलाम बनाए जाने में आसानी हो सके। विदेशी ताकतों द्वारा आज भारत के एकात्म समाज को टूटा-फूटा समाज बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार पुनः भारत ऐसे खंडकाल में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में भारत की तूती पूरे विश्व में बोलती दिखाई देगी। ऐसे में कुछ देशों द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के सामने बाधाएं खड़ी किए जाने के प्रयास हो रहे हैं। देश में निबासरत 80 प्रतिशत आबादी हिन्दू सनातन संस्कृति की अनुयायी है एवं हिन्दू समाज में व्याप्त समस्त जातियों, मत, पंथों को मानने वाले नागरिकों में त्याग, तपस्या, देशप्रेम का भाव, स्व-समर्पण का भाव कूट-कूट कर भरा है। कहा भी जाता है कि हिन्दू जीवन दर्शन ही पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में मददगार बन सकता है। भारतीय जीवन प्रणाली अपने आप में सर्व समावेशक है। हिन्दू सनातन धर्म का अनुपालन करने वाले नागरिक पशु, पक्षी, वनस्पति, पहाड़, नदियों आदि में भी ईश तत्त्व का वास मानते हैं, और उनकी पूजा भी करते हैं।

हिन्दू संस्कारों में पला-बढ़ा नागरिक सहिष्णु होता है। इसी के चलते कहा जा रहा है कि कई देशों में बढ़ रही हिंसा को नियंत्रित करने में हिन्दू सनातन संस्कृति के अनुयायी ही सहायक हो सकते हैं। और फिर, हिन्दू जीवन दर्शन का अंतिम ध्येय तो मोक्ष को प्राप्त करना है। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी हिंदू सनातन संस्कृति के अनुयायी कोई भी काम आत्मविचार, मनन एवं चिंतन करने के उपरांत ही करता है। इस प्रकार, इससे किसी भी जीव को दुखाने वाला कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। कई देशों के बीच कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं, अपने नागरिकों को खो रहे हैं। यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध एवं हमास- इस्राइल युद्ध इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बांग्लादेश में अशांति व्याप्त हो गई है। इसी प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे शांतिप्रिय देश भी आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए शांति स्थापित करने एवं आर्थिक विकास को गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से आज हिन्दू सनातन संस्कृति के संस्कारों को आज पूरे विश्व में फैलाने की महती आवश्यकता है।

विनम्रता

श्रीराम शर्मा आचार्य

विनम्रता आपके आंतरिक प्रेम की शक्ति से आती है। दूसरों को सहयोग और सहायता का भाव ही आपको विनम्र बनाता है। कहना गलत है कि यदि आप विनम्र बनेंगे तो दूसरे आपका अनुचित लाभ उठाएंगे जबकि यथार्थ स्वरूप में विनम्रता आपमें गजब का गौरव पैदा करती है। आप में सोचने-समझने की क्षमता का विकास करती है। विनम्र व्यक्तित्व का एक प्रचंड आभा मंडल होता है। धूर्तों के मनोबल उस आभा से निस्तेज हो स्वयं परास्त हो जाते हैं। उल्टे जो विनम्र नहीं होते वे आसानी से धूर्तों के प्रभाव में आ जाते है क्योंकि धूर्त को तो अहंकारी का मात्र चापलूसी से अहं सहलाना भर होता है। बस, चापलूसी से अहंकार प्रभावित हो जाता है। किंतु जहां विनम्रता होती है वहां तो व्यक्ति को सत्य की अथाह शक्ति प्राप्त होती है। सत्य की शक्ति, मनोबल प्रदान करती है। विनम्रता के प्रति पूर्ण समर्पणयुक्त आस्था जरूरी है। मात्र दिखावे की ओढ़ी हुई विनम्रता अक्सर असफल ही होती है। सोचा जाता है- 'पहले विनम्रता से निवेदन करूंगा यदि काम न हुआ तो भृकुटि टेढ़ी करूंगा' यह चतुरता विनम्रता के प्रति अनास्था है, छिपा हुआ अहं भी है। कार्य पूर्व ही अविश्वास व अहं का मिश्रण असफलता ही न्योता है। सम्यक विनम्र व्यक्ति, विनम्रता को झुकने के भावार्थ में नहीं लेता। सच्चाई उसका पथ प्रदर्शन करती है। निश्छलता उसे दृढ़ व्यक्तित्व प्रदान करती है। अहंकार सदैव आपसे दूसरों की आलोचना करवाता है। आपको आलोचना-प्रतिआलोचना के एक प्रतिशोध जाल में फंसाता है। अहंकार आपकी बुद्धि को कुंठित कर देता है। आपके जिम्मेदार व्यक्तित्व को संदेहयुक्त बना देता है। अहंकारी दूसरों की मुश्किलों के लिए उन्हें ही जिम्मेवार कहता है और उनकी गलतियों पर हंसता है जबकि अपनी मुश्किलों के लिए सदैव दूसरों को जवाबदार ठहराता है और लोगों से द्वेष रखता है। विनम्रता हृदय को विशाल, स्वच्छ और ईमानदार बनाती है। आपको सहज संबंध स्थापित करने के योग्य बनाती है। न केवल दूसरों का दिल जीतने में कामयाब होती है अपितु आपको अपना ही दिल जीतने के योग्य बना देती है जो आपके आत्म-गौरव और आत्म-लय में ऊर्जा का अनवरत संचार करती है। आपकी भावनाओं के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। व्याकुलता और कठिनाइयां भी स्वतः दूर होती चली जाती है।

रीडर्स मेल

आरक्षण का मुद्दा है बेहद पेचीदा

बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे ने तबाही मचाई है। इसको सभी राज्य सरकारों को जरूर समझना होगा और इससे सबक लेना होगा। आरक्षण बेहद पेचीदा और संवेदनशील मुद्दा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण संबंधी निर्णय के संदर्भ में भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया है कि मुद्दे का सम्मानजनक समाधान निकाला जाना चाहिए। सांसदों ने अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में क्रीमीलेयर का विरोध किया है जिस पर कैबिनेट मीटिंग में भी सहमति बनी है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आरक्षण में क्रीमीलेयर नहीं होगा, बल्कि संविधान में दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के तहत जारी व्यवस्था लागू रहेगी। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णय के बाद कांग्रेस ने भी चुप्पी तोड़ते हुए क्रीमीलेयर पर सवाल उठाया है, लेकिन जो वास्तविक तनाव का मुद्दा है उसे पर न बीजेपी, न कांग्रेस चर्चा कर रही है। वह मुद्दा है आरक्षण में वर्गीकरण का। इस मुद्दे पर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लगातार केंद्र सरकार से संवीधन की मांग की है और न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग करके इसको बड़ी बहस का मुद्दा बना दिया है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संसद में हंगामा गलत

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष हंगामा खड़ा करता है। यह लोकतंत्र की मजाक है। लोक सभा और राज्य सभा में विपक्षी दल प्रश्नकाल के दौरान हो-हल्ला कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करते हैं। न भूलें कि यह देश लोकतंत्र की जननी है। देश की गौरवशाली परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही में कोई विवाद और बेतुकी बयानबाजी से दूर रहा जाना चाहिए। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्य सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं कही, जबकि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले हो रहे हैं। विपक्ष तुष्टिकरण पर आज भी अडिग है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम सरकार को बधाई देते हुए हिन्दुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, लेकिन कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अल्पसंख्यक के लिए कोई टिप्पणी नहीं की गई। हिन्दुओं की सुरक्षा पर चुप्पी साधना भेदभावपूर्ण नीति की पक्षधारिता है।

कांतिलाल मांडोत, सूरत

युवाओं का दमखम

भारत ने युवाओं के दम पर पेरिस ओलंपिक में एक सिल्वर और चार ब्रॉन्ज, कुल पांच पदक जीत कर परचम लहराया है। विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारे युवाओं ने परचम न लहराया हो। इसीलिए नेपथ्य के परिदृश्य में आवाज सदैव बुलंद होती है कि युवा देश के युवा नागरिकों आगे बढ़ो, दुनिया को मुट्ठी में कर लो, भविष्य हमेशा तुम्हारा है, और रहेगा। किसी राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए वर्षों की मेहनत, अथक प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ संयम एवं उच्च मनोबल की आवश्यकता होती है, तब जा

स्वस्थ वातावरण एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। -टेड कुलोंगोस्की

हिंडनबर्ग का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है। इस बार निशाना हैं सेबी प्रमुख। आरोप है कि वह पहले भी अदाणी की साख को धक्का पहुंचाने वाली रिपोर्ट इसलिए लाया, क्योंकि वह शेयरों में गिरावट पर दांव लगा रहा था। सेबी को चाहिए कि वह विधिवत जांच के जरिये चीजों को सामने लाकर रिपोर्ट का कायदे से खंडन करे।

हिंडनबर्ग का जिन्न

पिछले साल अदाणी समूह पर निशाना साध कर देश की राजनीति और शेयर बाजार में भूचाल लाने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अब शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख को निशाना बनाने से हिंडनबर्ग-अदाणी की कहानी में एक नया मोड़ आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी की वर्तमान प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितताओं के कथित आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि उनकी अदाणी समूह से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदाणी समूह पर खाते में हेराफेरी और कंपनी में गड़बड़ी करने तथा शेयरों की कीमत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही अदाणी समूह की कंपनियों के मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट आई थी और विपक्ष को भी इससे सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिला था कि सरकार के संरक्षण में अदाणी समूह फल-फूल रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग, जो एक एलानिया शॉर्ट सेलर है, भी आरोपों से बच नहीं सका था, जिसके बारे में कहा गया कि अदाणी की साख को धक्का पहुंचाने वाली रिपोर्ट वह इसलिए लाया था, क्योंकि स्टॉक में जोरदार गिरावट पर दांव लगा रहा था। सेबी ने भी हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा था। हिंडनबर्ग पर आरोप लगा कि शॉर्ट सेलर होने के नाते उसने अदाणी के शेयरों में गिरावट पर दांव लगाकर काफी कमाया था। उस वक्त, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने तो इस मामले में किसी भी तरह की अनियमितता के सुबूत तो नहीं ही पाए थे, शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने या इस मामले को सीबीआई को सौंपने की जरूरत भी नहीं समझी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग कोई मीडिया समूह नहीं और न ही सार्वजनिक हित के उद्देश्य से गठित कोई निकाय। बल्मबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि हिंडनबर्ग ने वर्ष 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है, और रिपोर्ट जारी होने के अगले ही दिन उन कंपनियों के शेयर औसतन 15 फीसदी तक टूट गए। जाहिर है, हिंडनबर्ग ने सेबी को निशाना बनाते हुए उस कहानी के दोहराने की आशंका बढ़ा दी है, जो पिछले साल की शुरुआत में अडानी के खिलाफ आई उसकी रिपोर्ट के बाद बाजार में दिखी थी। शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने इस बार बजाय एक कंपनी के सीधे सेबी पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे में सभी तथ्यों को सामने लाते हुए विवाद का हमेशा के लिए पटाक्षेप किया जाना चाहिए।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है

शेख हसीना की आर्थिक नीतियों की बदौलत बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में एक स्थायित्व तो आया ही था, इससे घरेलू आत्मविश्वास भी बढ़ा था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में सिर्फ कपड़ा उद्योग पर निर्भरता से उपजी चुनौतियों से बांग्लादेश कैसे निपटेगा, यह देखने वाली बात होगी।

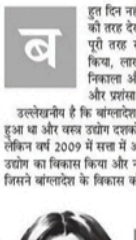

अनुप्रीता दास
द न्यूयॉर्क टाइम्स

बहुत दिन नहीं हुए, जब बांग्लादेश की आर्थिक चमत्कार की तरह देखा गया। मात्र कपड़ा और परिधान उद्योग पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर इसने अपना विकास किया, लाखों लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रसिद्धि और प्रशंसा दिलाई।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में आर्थिक सुधार 1970 के दशक में शुरू हुआ था और वस्त्र उद्योग दशकों से देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहा है। लेकिन वर्ष 2009 में सत्ता में आने वाली शेख हसीना ने सही मायनों में इस उद्योग का विकास किया और नए वैश्विक बाजार में इसका विस्तार किया, जिसने बांग्लादेश के विकास को काफी आगे बढ़ाया। सस्ते कपड़े वैश्विक परिधान के खुदरा विक्रेताओं, खासकर जारा एवं एच एंड एम जैसे फास्ट-फैशन ब्रांड्स के लिए काफी आकर्षक थे। साथ ही सस्ते परिधानों की बढ़ती मांग ने लाखों लोगों, खासकर महिलाओं के लिए आजीविका का सृजन किया और उनके जीवन स्तर को बदल दिया।

शेख हसीना ने बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च किया और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आश्वस्त किया कि वे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए बांग्लादेश पर भरोसा कर सकती हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में बांग्लादेश संबंधी सलाहकार थॉमस कौन ने कहा, 'प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना बांग्लादेश में स्थिरता का एक ऐसा स्तर लेकर आईं, जो विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक था। उन्होंने कहा कि अगर श्रमिकों की हड़ताल, बिजली कटौती या अन्य कारक इसे अविश्वसनीय बनाते, तो परिधान खरीदार बांग्लादेश को ऑर्डर नहीं देते। हसीना ने घरेलू आत्मविश्वास भी बढ़ाया। कौन कहते हैं कि जब उन्होंने सशस्त्र बल और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लिया, तब भी लोगों और उनकी सरकार के बीच लगभग एक तरह का समझौता था। उन्हें यह भरोसा था कि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ही आर्थिक वृद्धि और विकास लाएगी।

हसीना के नेतृत्व में एक दशक से भी अधिक समय तक अर्थव्यवस्था

बहुत तेज गति से बढ़ी, कुछ वर्षों में तो यह सात प्रतिशत से भी अधिक हो गई। परिधान निर्यात से देश को 80 प्रतिशत से अधिक आय हुई। लेकिन परिधान उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता हसीना के लिए विनाशकारी साबित हुई। कोरोना महामारी के कारण वस्त्र और परिधान की वैश्विक मांग घट गई। साथ ही, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और यूक्रेन पर रूस के युद्ध ने आयातित खाद्य और ईंधन की कीमतों में तेजी से वृद्धि की। अर्थव्यवस्था में कम विविधता के चलते बांग्लादेश बिलों का भुगतान करने के लिए अन्य उद्योगों से पर्याप्त राजस्व हासिल करने में असमर्थ था। इसके अलावा, महंगाई बढ़ने पर उसे नियंत्रित करने में हसीना सरकार विफल रही। अपनी कमजोर मुद्रा को सहारा देने की कोशिश में बांग्लादेश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च कर दिया, जो इतना कम हो गया कि 2022 में उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना पड़ा।

महामारी के बाद जब परिधान निर्यात में उछाल आया, तो बांग्लादेश अपनी अल्पकालिक समस्याओं में फंस चुका था। लचर नौकरशाही और नागरिकों की कर चुकाने की अनिच्छा के कारण बांग्लादेश बहुत कम कर राजस्व इकट्ठा कर पाता है। बांग्लादेश की विकास दर अब भी ऊंची है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मूल्क में असमान विकास हुआ है और आय असमानता बहुत ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बांग्लादेश के कार्यकारी निदेशक इफ्तिखार जमान ने कहा कि लोगों को यह एहसास हुआ कि कागज पर विकास की कहानी वास्तविकता से मेल नहीं खाती, जिससे सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा। हसीना के लिए शायद सबसे बड़ी दीर्घकालिक समस्या यह थी कि उनकी सरकार परिधान व्यवसाय पर निर्भरता के कारण नई नौकरियां पैदा करने में असमर्थ रही। देश की बड़ी कामकाजी आबादी के लिए पर्याप्त नई या बेहतर वेतन वाली नौकरियां नहीं हैं। पिछले महीने उस संचित हताशा को एक रास्ता मिल गया, जब सरकारी नौकरियों के लिए कोटा व्यवस्था को खत्म करने की मांग शुरू हुई। आंदोलन की आड़ में देश के कट्टरपंथी और विपक्षी दल भी जोर लगा रहे थे, हसीना ने प्रदर्शन को दबाने के लिए सशस्त्र बलों को भेजा, तो लोगों का गुस्सा और उबल पड़ा।

हसीना की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को उछाल दिया और एक आम बांग्लादेशी को आत्मविश्वास दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर शेख हसीना को व्यापक जन-असंतोष का सामना करना पड़ा है, तो यह जरूर विश्लेषण का विषय है। खासकर युवाओं का असंतोष देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बताया गया। कुछ अर्थशास्त्री इसके पीछे खराब नीतिगत निर्णयों को वजह बता रहे हैं। हसीना के इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी छात्रों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रोफाइनेंस के अग्रणी मुहम्मद यूनुस को लाया है। लेकिन उनके लिए भी राह आसान साबित नहीं होने वाली। यूनुस को सबसे पहले बांग्लादेश को शांति व्यवस्था बहाल करनी होगी और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होगा। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले रोकने होंगे। लंबे समय तक बांग्लादेश को व्यापक आर्थिक तनावों को झेलना होगा, जिसने प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य किया था।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अंतरिम सरकार कब तक सत्ता में रहेगी और इसका व्यापक जनादेश कितना होगा। लेकिन कनाडा स्थित वाल्स्ली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के फेलो साद हम्मादी ने कहा कि सरकार और यूनुस से 'लोगों को न्याय दिलाने, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने, कानून का शासन और एक पारदर्शी व जवाबदेह सरकार स्थापित करने जैसी कई आकांक्षाएं हैं।' उन्होंने ईमेल के जरिये बताया कि 'अंतरिम सरकार के लिए ये चुनौतियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए नेताओं का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिये हो। पूरे प्रशासन में संस्थागत सुधारों की जरूरत होगी।' अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेते हुए 84 वर्षीय यूनुस ने शांति की अपील की और राष्ट्र से व्यवस्था बहाल करने के साथ हिंसा से दूर रहने की अपील की। एक अर्थशास्त्री होने के नाते उनसे बाजार के अनुकूल सुधार की उम्मीद की जा रही है।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

फ्योदोर दोस्तोवस्की

आप प्रेम में आगे बढ़ेंगे, तो ईश्वर की वास्तविकता और आत्मा की अमरता के बारे में अधिक आश्वस्त होंगे। यदि आप खुद से या दूसरे से प्रेम करते हैं, तब कोई संदेह आपकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

प्रेम के अनमोल खजाने से दुनिया खरीद सकते हैं

मानव जाति का अस्तित्व सिर्फ जीवित रहने में नहीं है, बल्कि जीने के लिए कुछ खोजने में है। मुझे जीवन की लालसा है और मैं तर्क के बावजूद जीता रहता हूं। हालांकि मैं ब्रह्मांड के कर्म में विश्वास नहीं करता, फिर भी मुझे वसंत में खिलने वाली छोटी पत्तियां बहुत पसंद हैं। मुझे नीला आकाश पसंद है। मुझे कुछ लोग पसंद हैं, जिन्हें मैं कभी-कभी बिना किसी कारण प्यार कर लेता हूं। यह सब बुद्धि या तर्क की बात नहीं है, यह सब अपने से प्यार करना है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के अलावा और कुछ नहीं। जीवन खोज की सतत और शाश्वत प्रक्रिया है, स्वयं खोज नहीं है। इसलिए जीवन को उसके अर्थ से भी अधिक प्यार करना चाहिए।

मनुष्य एक रहस्य है। इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। अगर आप इसे सुलझाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, तो यह मत कहिए कि आपने समय बर्बाद कर डाला। मैं उस रहस्य का अध्ययन कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक इन्सान बनना चाहता हूं। मैं मानव जाति से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जितना मैं मानव जाति से प्यार करता हूं, उतना ही मैं विशेष रूप से मनुष्य से प्यार करता हूं। इन्सान बनने की पहली शर्त है कि खुद से झूठ कभी मत बोलो। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है और खुद के झूठ को सुनता है, वह इस हद तक पहुंच जाता है कि वह अपने भीतर या आसपास के सत्य को पहचान तक नहीं पाता। ऐसे में, वह जीवन के रहस्य को कैसे समझ पाएगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सारा सम्मान खो देता है। और फिर सम्मान न होने पर वह प्यार करना भी बंद कर देता है। अक्सर लोग स्वर्ग-नरक के बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि जीवन स्वर्ग है, और हम सब इसी स्वर्ग में हैं, लेकिन इसे देखने से इन्कार करते हैं। नरक तो प्रेम न कर पाने की पीड़ा है। इसलिए प्रेम के महत्व को पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे-जैसे आप प्रेम में आगे बढ़ेंगे, ईश्वर की वास्तविकता और आत्मा की अमरता के बारे में अधिक आश्वस्त होते जाएंगे। यदि आप खुद से या दूसरे से प्रेम करते हैं, और उस प्रेम में पूर्ण आत्म-विस्मृति प्राप्त कर लेते हैं, तो आप बिना किसी संदेह के विश्वास करने लगेंगे। तब कोई भी संदेह आपकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

प्रेम एक शिक्षक है, लेकिन प्रेम को प्राप्त करना उतना आसान भी नहीं है। किसी से प्यार करने का मतलब है, उसे वैसे देखना जैसा उसे ईश्वर ने बनाया है। प्यार एक ऐसा अनमोल खजाना है, जिससे आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। इसलिए यह बहुत महंगा भी है और हर कोई इसे पा ले, यह भी आसान नहीं। इसलिए जिससे भी प्रेम करें, किसी पल या सीमित समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यदि आप ऐसा करने का संकल्प करते हैं, तो हमेशा के लिए पूरी दुनिया को वश में करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

सूरज बनने का प्रयास करें

सूत्र

प्रेमपूर्ण विनम्रता किसी को भी जीतने का अद्भुत हथियार है। सम्मान भी प्रेम के साथ ही जुड़ा है। यदि आप दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है खुद का सम्मान करना। अगर दुनिया पर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो पहले खुद पर विजय पाएं। सूरज बनने का प्रयास करें, ताकि सब आपकी ओर देखें।

दूसरा पहलू

चीन ने दावा किया है कि मानव इतिहास में पहली बार उसे चांद पर जो मिट्टी मिली है, उसमें अलग तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं।

शुरू हो गई चांद पर खेती की तैयारी

चीन जहां चांद पर खेती करने की योजना बना रहा है, वहीं अमेरिका ने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का तरीका खोज लिया है। नासा का आर्टेमिस-3 चंद्रमा पर पौधों की खेती का पता लगाएगा। पिछले दिनों चीन चांद से मिट्टी के नमूने लेकर आया है। उसका कहना है कि मिट्टी के नमूने में पानी होने का संकेत मिला है। भारत यह बात वर्षों से कह रहा है। भारत के चंद्रयान-1 ने 15 साल पहले ही संकेत दिए थे कि चांद की मिट्टी में पानी है। चीन अब वहां फल उगाने से लेकर खेती करने तक के सपने बुन रहा है। यह मिट्टी चांद के उस हिस्से में है, जिधर अंधेरा रहता है। गौरतलब है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 उतारने वाला पहला देश है।

निरंकार सिंह

चीन ने दावा किया है कि मानव इतिहास में पहली बार उसे चांद पर जो मिट्टी मिली है, उसमें अलग तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। इस दौड़ में अमेरिका, रूस, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चीन, भारत और जापान जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन चंद्रमा के जिस हिस्से पर पानी की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर होड़ केवल भारत और चीन के बीच है। भारत ने चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में अपना रोवर भेजा था, जिसने एक हफ्ते तक चांद की मिट्टी से कई नमूने हासिल किए, जिससे वहां पानी की मौजूदगी का पता चला था।

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसे जीवाणुओं को वहां भेजा है, जो महत्वपूर्ण पौध पोषक तत्व फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं। इसके परीक्षण के लिए दो साल बाद नासा आर्टेमिस-3 को चांद पर भेजेगा। एक विशेष पेलोड चंद्र वातावरण में पौधों की खेती की अवधारणा का पता लगाएगा। अमेरिकी नेशनल एयरोनॉटिक्स ऐंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्टेमिस-3 के दौरान चंद्रमा की सतह पर तैनात करने के लिए कुछ उपकरणों को चुना है, जिनमें से एक कृषि वनस्पतियों पर चंद्र प्रभाव है। यह अंतरिक्ष की फसलों पर चंद्र सतह के पर्यावरण प्रभावों की जांच करेगा।

वर्ष 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 12 थिम्बल आकार के कंटेनरों में अरेबिडोप्सिस थालियाना नामक एक फूलदार खरपतवार उगाया, जिनमें से प्रत्येक में आधी सदी से भी अधिक समय पहले नासा मिशनों के दौरान एकत्र की गई वास्तविक चंद्रमा मिट्टी का एक ग्राम था।

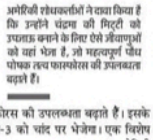

भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 ने 15 साल पहले ही संकेत दिए थे कि चांद की मिट्टी में पानी है। लेकिन चीन अब खेती करने के सपने बुन रहा है।

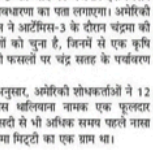

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ऐसे जीवाणुओं को वहां भेजा है, जो महत्वपूर्ण पौध पोषक तत्व फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं।

आंकड़े

सड़क नेटवर्क

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क यातायात नेटवर्क है। भारत ने इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है।

आंकड़े लाख किलोमीटर में। | स्रोत : CIA

एकादशी व्रत के प्रभाव से अयोध्यावासी यमपुरी नहीं जाते थे। रुकमांग का व्रत तुड़वाने के लिए ब्रह्मा जी ने माया से मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री बना दी।

रुकमांग ने नहीं तोड़ा एकादशी व्रत

अयोध्या के राजा रुकमांग एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि बच्चों, आतिवृद्धों और गर्भवतियों को छोड़कर सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। व्रत के प्रभाव से अयोध्यावासी यमपुरी नहीं जाते थे। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा 'इस तरह तो हमारा यमलोक सूना हो जाएगा। ब्रह्मा ने राजा का व्रत तुड़वाने के लिए अपनी माया से मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री बना दी।

अंतर्यात्रा
संकलित

इधर, राजा रुकमांग अपने बेटे धर्मांगद को राज्य सौंप कर हिमालय की ओर चले गए। इसी बीच जंगल में मोहिनी ने राजा से भेंट की। राजा मोहिनी पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने शर्त रखी, 'मैं आपसे तभी विवाह करूंगी, जब आप मेरी हर बात मानेंगे।' राजा ने वचन दे दिया और मोहिनी से विवाह कर लिया। रुकमांग ने जब एकादशी का व्रत किया, तो मोहिनी ने कहा कि महाराज आपको मेरी बात माननी होगी। उन्होंने कहा क्या बात है? मोहिनी बोली, 'आप एकादशी का व्रत करना छोड़ दें।' राजा बोले, 'कोई और बात मनवा लो, एकादशी व्रत छोड़ने के लिए बाध्य न करो।' मोहिनी बोली, ठीक है, तो अपने इकलौते बेटे धर्मांगद का सिर काटकर मुझे दे दीजिए। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन धर्मांगद ने कहा, 'पिता जी, आपके धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।' रुकमांग जैसे ही बेटे का सिर काटने को तैयार हुए, तो भगवान प्रकट हो गए और उनके पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 04 जून, 1957

अमेरिका बगदाद संधि की सैनिक समिति में शामिल

अमरीका बगदाद संधि की सैनिक समिति में शामिल
अमेरिका ने ईरानी को बैठक में शामिल करवाने के लिए, 'न बाज' पीने वचनों की तैयारी

बगदाद संधि समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने कहा कि संधि का उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। बैठक में अमेरिका ने भी हिस्सा लिया।

सिर्फ जीडीपी ही काफी नहीं

सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) का विचार जीडीपी के साथ मिलकर आर्थिक प्रदर्शन का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।

वीर सिंह — पर्यावरण

विश्व के लगभग सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मानकों से आंकते हैं। भूटान सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस) को अपना सबसे बड़ा आधार मानता है। लेकिन 19 जुलाई को उत्तराखंड ने अपनी अर्थव्यवस्था के आकलन के लिए जिस मानक की घोषणा की, वह अद्वितीय है। सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) को अपनी अर्थव्यवस्था का मानक मानने वाला यह हिमालयी राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है, जो दुनिया भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। हालांकि ऐसी आर्थिक विकास की नीति कोस्टा रिका तथा कुछ अन्य देशों में आंशिक रूप से प्रभावी है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से प्रयासरत पर्यावरणविद् डॉ अनिल जोशी और उत्तराखंड प्रशासन की यह पहल स्वागत योग्य है, परंतु इस पर इतनी चर्चा नहीं हो रही, जितनी होनी चाहिए।

जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक रूप से स्वीकृत

माप है, परंतु आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी पर्यावरणीय लागतों और लाभों को ध्यान में रखते हुए यह आर्थिकी के वास्तविक आकलन की एक कमजोर कड़ी है। जबकि सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) की अवधारणा मानव सहित सभी जीवों के कल्याण और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के योगदान को मापने के सार्थक दृष्टिकोण के रूप में उभरी है।

महात्मा गांधी ने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, न कि लालच की पूर्ति करने वाली, आर्थिकी का दर्शन दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने 'पारिस्थितिकी ही स्थायी आर्थिकी है' का सिद्धांत दिया था।

सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) एक अभिनव मानदंड है, जिसे प्रकृति द्वारा प्रदान की गई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मापने और महत्व देने के लिए तैयार किया गया है। जीईपी का लक्ष्य इन विविध योगदानों को एकल मौद्रिक मूल्य में समाहित करना है, जो आर्थिक और सामाजिक कल्याण के समर्थन में प्राकृतिक पूंजी के वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। जीईपी मूल्यांकन पर्यावरणीय कारकों को शामिल करके आर्थिक प्रदर्शन का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। प्रकृति के नियमों के साथ पूर्ण राजनीतिक निष्ठा से जीईपी को अपनाने से सतत राष्ट्रीय विकास प्रभावों को प्रोत्साहन मिल सकता है। यह बदलाव अधिक संतुलित और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों को जन्म दे सकता है, जो आर्थिक विकास का तालमेल पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ बनाए रखती है।

वैसे जीईपी की अवधारणा भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने के अनुरूप भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इसकी गणना में कई चरण और पद्धतियां समाहित हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की जटिलता और विविधता को दर्शाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख दृष्टिकोण हैं : बाजार-आधारित मूल्यांकन, प्रतिस्थापन लागत विधि, आकस्मिक मूल्यांकन और लाभ अंतरण। जीईपी का उद्देश्य एक ही है-पारिस्थितिकी-केंद्रित सतत सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विकास। उत्तराखंड में जो जीईपी लागू किया जाना है, उसमें पर्यावरण के चार घटकों (जल, वायु, वन और मिट्टी) संबंधी सूचकांक शामिल हैं। आर्थिक विकास की नीतियों, योजनाओं और प्रक्रियाओं में पर्यावरण के इन घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित रखना किसी भी प्रशासन का नैतिक दायित्व है और इसे मूर्त रूप देने में उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण-नैतिकता के प्रदर्शन का साहस दिखाया है।

जीईपी को कार्रवाई योग्य नीतियों और निर्णयों में बदलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है। सरकारों और संगठनों को अपनी योजना प्रक्रियाओं में जीईपी को एकीकृत करने और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक प्रोत्साहन में तालमेल बनाना चाहिए। उत्तराखंड में एक जीईपी सेल की स्थापना की बात कही गई है, जो जीईपी के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। जीईपी को नीति आयोग के साथ जोड़ने और इसे पूरे देश के लिए लागू करने की आवश्यकता है। जीईपी आर्थिक प्रगति और स्थिरता पर पुनर्विचार करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान किए गए असंख्य लाभों को महत्व देकर जीईपी आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच अंतर को पाटता है। इसमें नीतियों को नया आकार देने, टिकाऊ प्रथाओं का मार्गदर्शन करने और मनुष्यों और प्रकृति के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। जीईपी को अपनाना न केवल एक आर्थिक अनिवार्यता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए ग्रह की सुरक्षा का एक नैतिक दायित्व भी है।

edit@amarujala.com

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

हमारे छह पदक

पेरिस ओलंपिक 2024 के मीठे-खट्टे अनुभवों को भारत एक सबक की तरह हमेशा याद रखेगा। छह पदकों (एक रजत, पांच कांस्य) के साथ ओलंपिक 2024 में भारत के सफर का समापन हो गया। यह याद आना स्वाभाविक है कि पिछले टोक्यो ओलंपिक में हमने सात पदकों (एक स्वर्ण, दो रजत, चार कांस्य) के साथ इससे बेहतर प्रदर्शन किया था। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि अगर पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता का मामला न होता, तो भारत अपने प्रदर्शन को दोहराने में सफल हो जाता। यह भी याद किया जाएगा कि विनेश फोगाट के मामले ने देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस देश में राजनीति और खेल संघों को अलग-अलग न किया जा सके, वहां ऐसे विवाद स्वाभाविक हैं। यह 100 ग्राम से उपजी सियासत भी सुबूत है कि हम खेलों व खिलाड़ियों के प्रति पूरी तरह पेशेवर या समर्पित नहीं हैं। विनेश प्रकरण के अनेक परत हैं, जिन पर हमें गौर करना होगा। फिर भी प्रशंसा करनी चाहिए कि हमने ओलंपिक की खेल अदालत में विनेश की शिकायत को पुरजोर ढंग से उठाया है और मुमकिन है कि 13 अगस्त को एक और रजत पदक हमारी झोली में आ जाए।

सबसे बड़ी खुशी राष्ट्रीय खेल हॉकी को लेकर है कि हमने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। इससे निस्संदेह भावी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, हम लगातार अपने खेल को सुधारते और पदक जीतते चले जाएंगे। इस ओलंपिक को नीरज चोपड़ा के रजत पदक और उनके साथी पाकिस्तानी अरशद नदीम के स्वर्ण पदक के लिए भी याद किया जाएगा। नीरज और नदीम की मां के उद्गार भी याद आएंगे। लंबे समय बाद पाकिस्तान की झोली में एक पदक, वह भी स्वर्ण आया है और पाकिस्तानियों को चर्चा के लिए एक सकारात्मक विषय मिला है। नदीम वहां प्रेरणास्रोत बनें, तो इसमें दक्षिण एशिया का हित है। यह ओलंपिक निशानेबाज मनु भाकर के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने एक कांस्य पदक व्यक्तिगत शूटिंग में और दूसरा सरबजोत के साथ मिश्रित टीम में जीता है। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले और पहलवान अमन सहरावत ने भी कांस्य जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह ओलंपिक हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश की शानदार विदाई के लिए भी याद किया जाएगा। ये खिलाड़ी अब प्रेरणा-स्रोत बनकर भारतीय खेल इतिहास में दर्ज हो गए हैं।

अब यहां से खेल प्रबंधकों और निर्णायकों के लिए काम शुरू हो जाता है। क्या सोचा गया था और क्या हुआ है? आगे क्या सुधार करना है?

अब यहां से खेल प्रबंधकों-निर्णायकों के लिए काम शुरू हो जाता है। क्या सोचा गया था और क्या हुआ है? आगे क्या सुधार करना है? किससे क्या सीखना है? खेल निर्णायकों को युद्ध स्तर पर काम करना होगा, तभी उनकी सार्थकता है, वरना पदक तालिका तो अभी कहीं उत्साह से दिखाने लायक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पदक अमेरिका ने जीते हैं, पर चीनी खिलाड़ियों ने रणनीति के तहत स्वर्ण पर निशाना साधा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली इत्यादि के पदक गिनने के बजाय हमारा जोर अपने प्रदर्शन को सुधारने पर होना चाहिए। हमें सोचना होगा कि हमारा ध्यान किधर ज्यादा है? मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में क्यों हमारी अवनति हुई है? खैर, यह पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सत्कार का समय है। हम जब खिलाड़ियों के साथ मजबूती से खड़े होने लगेंगे, तो खेलों में सुधार की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हॉकी के पुनरोत्थान और ओडिशा सरकार के सहयोग से भी सीखना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 12 अगस्त, 1949

आर्थिक एकीकरण

पिछले दो वर्षों में देश के नक्शे तक में भारी परिवर्तन हो गये हैं। विदेशी शासकों ने इस देश के दो हिस्सों के बीच एक अस्वाभाविक दीवार खींच रखी थी। हमारे देश का एक हिस्सा ब्रिटिश भारत कहलाता था और दूसरा भारतीय भारत, जो राजाओं द्वारा शासित होता था। ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत की शासन-प्रणाली में कोई समानता न थी। भारतीय भारत लगभग पौने छः सौ भागों में विभाजित था और हरेक भाग अपनी खिचड़ी अलग पकाता था। देशी राज्य भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से देश के अविभाज्य अंग थे, किन्तु उनके पृथक् राजनीतिक अस्तित्व ने उनको देश की सामान्य जीवन-धारा से जुदा कर दिया था। देश की स्वतंत्रता और उसका भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन साथ-साथ आये। एक ही राष्ट्र के दो टुकड़े हो गये। इससे उसकी शक्ति क्षीण हुई। जिन लोगों के सिर पर राष्ट्र-निर्माण का गुरुतर दायित्व था, उन्होंने महसूस किया कि विभाजन के बाद देश का जो हिस्सा बच रहा है, उसी को एक मजबूत इकाई के रूप में संगठित कर दिया जाये, ताकि सदियों पश्चात् जो दुर्लभ स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा की जा सके और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सके। उन्होंने सबसे पहले देश को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का काम हाथ में लिया। अंग्रेज जाते-जाते राजाओं को स्वच्छन्द कर गये थे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें भारतीय संघ के पाश में आबद्ध किया।

राजाओं ने भारतीय संघ का अंग बनना स्वीकार किया और रक्षा, यातायात और वैदेशिक संबंध- ये तीन आवश्यक विषय केन्द्रीय सरकार के हवाले कर दिये। छोटे-बड़े सैकड़ों राज्यों के पृथक् अस्तित्व की समस्या को इस तरह हल किया गया कि कुछ को पड़ोसी प्रान्तों में मिला दिया गया, कुछ को आपस में संघबद्ध कर दिया गया और कुछ बड़ी रियासतें स्वतंत्र रूप में कायम रहने दी गईं। देश के राजनीतिक एकीकरण की यह प्रक्रिया दो वर्ष के समय में प्रायः पूरी हो चुकी है। रियासतों का राजनीतिक एकीकरण पहली बड़ी मंजिल थी। उसके बाद हमको शेष भारत के साथ रियासतों के आर्थिक एकीकरण की दूसरी मंजिल तय करनी होगी। इसके बिना रियासतों को प्रान्तों की सतह पर नहीं लाया जा सकेगा।

राष्ट्रवाद की एक बुनियाद बने ओलंपिक

यहां सीन करें

रॉन्जॉय सेन | राजनीतिक विश्लेषक

खेल और राष्ट्रवाद के बीच संबंध पुराना है। चीन सहित अनेक देशों ने पदक तालिका में स्थिति सुधारकर अपनी पहचान बनाई है, भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है।

हर चार साल में भारत निशानेबाजी की बारीकियों और पिस्तौल, राइफल, ट्रैप व स्कीट के बीच के अंतर से परिचित होता है। ऐसा निशानेबाजी के प्रति उसके प्यार के कारण नहीं होता, बल्कि निशानेबाजों पर टिकी उम्मीदों की वजह से होता है कि वे एक दुर्लभ चीज लाएंगे, जो है ओलंपिक पदक। यह कहना गलत नहीं होगा कि हाशिये पर पड़े खेलों को ओलंपिक पदकों से काफी ऊर्जा मिलती है। यह स्थिति कई देशों की है, उस चीन की भी, जिसने खिलाड़ियों की सफलता को अपने राष्ट्रवाद का स्तंभ बनाया और पूरी दुनिया में जगह बनाई। पुराने दौर में रूस ने भी यही किया था।

खेल और राष्ट्रवाद के बीच का संबंध काफी पुराना है। यह ओलंपिक संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन के मत के बिल्कुल विपरीत है, जिनका मानना था कि प्रतिस्पर्द्धा करें, फिर चाहे आपको उसमें जीत मिले या न मिले। जॉर्ज ऑरवेल ने शायद अतिशयोक्ति की थी, जब उन्होंने शीत युद्ध के संदर्भ में खेल को 'वार माइनस द शूटिंग' कहा था, फिलहाल भावार्थ है- बिना गोलीबारी वाली वैश्विक जंग। हालांकि, एरिक हॉब्सबॉम यह उचित ही लिखते हैं कि ग्यारह नामित खिलाड़ियों की टीम लाखों लोगों के किसी समुदाय, समाज, देश से कहीं अधिक वास्तविक लगती है। टीम को हम प्रतिनिधि रूप में देखते हैं।

कुछ शुरुआती ओलंपिक खेलों में ऐसे प्रतिभागी भी थे, जो जरूरी नहीं कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन जल्द ही देश का प्रतिनिधित्व करना नियम बन गया। जाने-माने खेल इतिहासकार एलन बैरनर ने लिखा है, खेल किसी भी अन्य सामाजिक गतिविधियों की तुलना में कहीं अधिक ध्वजा लहराने और राष्ट्रगान बजाने की सुविधा प्रदान करता है। यह ओलंपिक खेलों के लिए विशेष रूप से सच है। मुकुल केसवन के शब्दों में कहें, तो ओलंपिक ने खेल और राष्ट्र की निरंतर पहचान का बीड़ा उठा रखा है।

यह बात रविवार को खत्म हुए ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल के फाइनल में भी साफ-साफ दिखी, जब ताइवान की जोड़ी चीन के खिलाफ मुकाबिल थी। इसमें ताइवानी खिलाड़ी अपने ध्वज नहीं, बल्कि चीनी ताइपे के झंडे तले मुकाबला कर रहे थे। दर्शकों में जो कोई भी ताइवान का झंडा लहराता दिखता, उसे या तो बाहर निकाल दिया जाता या फिर उसका झंडा जब्त कर लिया जाता था। मुकाबले में चीनी ताइपे की जोड़ी भारी पड़ी और इस जीत को कई ताइवानियों ने विश्व समुदाय में ताइवान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा। ताइवानी राष्ट्रपति ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा कि इस जीत ने मुल्क को एकजुट कर दिया है।

राष्ट्रवादी नजरिये से जीत को परिभाषित करने का यह कोई एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि ओलंपिक खेल ऐसे अनेक उदाहरणों से भरे पड़े हैं। साल 1980 के मॉस्को व साल 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों के दौरान शीत युद्ध के दौर में बहिष्कार जैसी कार्रवाइयां तस्दीक करती हैं कि खेलों के इर्द-गिर्द बहरहाल, भारत सहित ज्यादातर देशों की पदक-तालिका में अपनी स्थिति मजबूत बनाने की नीयत काफी हद तक राष्ट्रवादी प्रवृत्ति और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बनने की महत्वाकांक्षा से जुड़ी है। पुराने जमाने में सोवियत संघ और सोवियत गुट के कुछ सदस्यों ने व्यवस्थित रूप से ऐसा ही किया था। आज के समय में चीन ने भी यही रास्ता दिखाया है। भारत के विपरीत, जिसने आजादी से पहले हॉकी में सोना जीता था, चीन ने अपना पहला सोना 1984 के खेलों में जीता, जब वह ओलंपिक में फिर से शामिल हुआ था। तब से यह देश तेजी से आगे बढ़ा है और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ही 48 सोना जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अमेरिका से आगे निकल गया था। चीन बाद के ओलंपिक खेलों में भी शीर्ष स्थान के लिए अमेरिका के साथ होड़ लगाता दिखा है। माओत्से तुंग हमेशा खेल और राष्ट्रवाद के बीच गहरा रिश्ता बताते रहे। 2001 में बीजिंग को 2008 के खेलों की मेजबानी के लिए चुने जाने के बाद से ही चीन ने पदकों का पीछा करना शुरू कर दिया था। चीन की सरकार ने 'प्रोजेक्ट-119' के तहत अपने बच्चों को चैंपियन बनाने के लिए 3,000 से भी अधिक अकादमियों में अरबों डॉलर निवेश किए। इसका नाम प्रोजेक्ट-119 इसलिए रखा गया था, क्योंकि उस समय जल क्रीड़ा और एथलेटिक्स में 119 पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया था। दो चीनी इतिहासकारों ने बताया है कि स्वर्ण पदक को लेकर चीन की भूख ने चीनी एथलीटों पर भारी सियासी बोझ डाल दिया, जिनका मिशन था, चीन की छवि को सुधारना और राष्ट्र के पुनरोद्धार के लिए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना।

भारत ने आजादी के शुरुआती वर्षों में खेलों को लेकर अलग नीति अपनाई थी। 1951 के दिल्ली एशियाई खेलों में जवाहरलाल नेहरू के संबोधन में भले ही डे कुबर्टिन के आदर्शों की ध्वनि निकल रही थी, जब उन्होंने कहा था कि खेल प्रतियोगिताएं मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्विता विकसित करने के लिए अच्छी हैं और प्रत्येक खिलाड़ी को इसमें अपनी भूमिका शालीनता से निभानी चाहिए, लेकिन तब से अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। हाल के वर्षों में तो भारत सरकार और उद्योग जगत, दोनों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के प्रदर्शन को सुधारने के लिए काफी पैसे लगाए हैं। हालांकि, भारत की खेल नीति के कुछ अन्य पहलू भी हैं। बेशक, इसका खेल के बुनियादी ढांचे के विकास और खेल व स्वास्थ्य सुविधाओं तक बच्चों की बेहतर पहुंच पर बहुत असर नहीं पड़ा हो, लेकिन इसने हमारे खेल प्रदर्शन को काफी अधिक सुधारा है, भले ही हमें पदक के मामले में अभी पीछे रहना पड़ रहा है।

पिछले एक दशक में भारत में भी खेल राष्ट्रीय गौरव, वैश्विक रुतबे का विषय बना है। भारत ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के प्रयासों में लगा है। यही कारण है कि इस साल ओलंपिक में टोक्यो से भी बेहतर प्रदर्शन की इच्छा जताई गई थी। इसने किसी खिलाड़ी की सफलता में आत्म-गौरव और उनकी हार पर सामूहिक निराशा पैदा की, फिर चाहे वह विनेश फोगाट का ही मामला क्यों न हो। वास्तव में, विनेश फोगाट की अयोग्यता को राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखने जैसी प्रतिक्रिया भारत में खेलों के प्रति बढ़ते प्रेम के साथ ही राष्ट्रवाद व ओलंपिक के संबंधों का ही एक रूपक है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दुनिया में हुए युवा आंदोलनों को याद करने की जरूरत

यहां सीन करें

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जब 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब कई देशों में हुए एक और युवा आंदोलन को याद करना जरूरी है, जिसके घटनाक्रम अब भी हमारी स्मृतियों में ताजा हैं। चंद महीनों बाद उस आंदोलन के 15 साल पूरे हो जाएंगे, जिसे हम 'अरब स्प्रिंग' के नाम से जानते हैं। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ यह आंदोलन जब एक के बाद एक पश्चिम एशिया के तमाम देशों में फैलने लगा, तो पूरी दुनिया की खैर-खबर रखने वाले तकरीबन सभी आलिम-फाजिल दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर थे। लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया, बहरीन जैसे देशों में नौजवान सड़कों पर आ चुके थे। वे तानाशाही की तमाम पाबंदियां हटाने और मानवाधिकार देने की मांग कर रहे थे। यह हवा इतनी तेज थी कि मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान और यहां तक कि सऊदी अरब में भी इसके झोंके महसूस किए गए। आंदोलन का भूगोल भले ही सीमित रहा हो, लेकिन इसने दुनिया के तानाशाहों और लोकतांत्रिक ताकतों को यह संदेश दे दिया था कि इस नए दौर में पुराने तौर-तरीकों से नौजवान पीढ़ी को ज्यादा समय तक भरमाए नहीं रखा जा सकता।

नए दौर का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है कि इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के आगमन के बाद का यह पहला बड़ा आंदोलन था, जो एक साथ कई देशों में फैला। तकनीक ने देश की सीमाओं से परे लोगों को आपस में जुड़ने का मौका दे दिया था। इनसे लोगों को लामबंद किया गया, धरना स्थलों तक खींच लाया गया और जो नहीं पहुंच सके, वे लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड से भागीदार बनते रहे। इस सबका असर भी दिखा। कई देशों के शासनाध्यक्षों को गद्दी छोड़नी पड़ी। कई राजाओं ने अपनी गद्दी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। तमाम जगहों पर सरकारें भंग की गईं और नए सिरे से चुनाव कराए गए।

मगर इन सबके बाद क्या खत्तीन क्रांति की बात करने वाले इन देशों के नौजवानों ने वह हासिल कर लिया, जिसके लिए वे सड़कों पर निकले थे? इसका जवाब पाने के लिए हमें अमेरिकी थिंक टैंक 'कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन' के एक अध्ययन को देखना होगा। यह अध्ययन बताता है कि इन सबमें ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश है, जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। बाकी सभी देशों में तानाशाही जैसी थी, कम या ज्यादा वैसी ही बनी रही। अपवाद सिर्फ मिस्र और सीरिया को कह सकते हैं, जहां सत्ता पहले से ज्यादा सख्त हो गई। तमाम देशों में लोगों के अधिकार कम कर दिए गए और उनके जीवन-स्तर में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि ट्यूनीशिया में भी, जहां लोकतंत्र काफी हद तक स्थापित हो चुका था। युवा आंदोलनों के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वे बेरोजगारी की कुंठा से उपजते हैं। इलाज भी यही बताया जाता है कि नौजवानों को काम में लगाकर घर-गृहस्थी में उलझा दो, तो वे सड़कों पर नहीं निकलेंगे। यह धारणा कितनी सही है और कितनी नहीं, इस विस्तार में जाए बिना अगर हम 'अरब क्रांति' के दौरान आंदोलित देशों को देखें, तो आंदोलन के बाद भी वहां की सरकारों ने इस इलाज को अपनाने की या तो कोशिश नहीं की या फिर इसमें सफलता हासिल नहीं की। ज्यादातर देशों में बेरोजगारी दर कम या ज्यादा वैसी ही बनी रही, जैसी वह पहले थी।

डर इसी बात का है कि बांग्लादेश के नौजवान जितना हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं, कहीं वे उससे ज्यादा गंवा न बैठें।

हम अरब देशों की इस क्रांति को तब याद कर रहे हैं, जब हमारे पड़ोस बांग्लादेश में युवा उबाल का एक अन्य रूप हमने अभी देखा है। चंद हफ्तों के युवा आंदोलन ने 15 साल से जमी-जमाई उस सरकार को उखाड़ फेंका, जो आई तो लोकतंत्र के दरवाजे से थी, लेकिन पूरे देश को तानाशाही की गहरी गुफाओं में ले गई। इस आंदोलन का स्वागत किया जाना चाहिए, पर अरब स्प्रिंग के सबक यहां हमें आशंकित करते हैं। डर है कि ये नौजवान जितना हासिल करने के लिए घर से निकले हैं, कहीं उससे ज्यादा वे खो न दें। इस डर का कारण भी है। सत्ता में बदलाव के बाद यहां जिस तरह से हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक तत्वों को खेलने का मौका मिला है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वह भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं बनाता। क्या पश्चिम एशिया के नौजवानों की तरह ही बांग्लादेश के नौजवानों को भी एक अंधेरे के बदले दूसरा अंधेरा मिलेगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

स्वतंत्रता का मंदिर

न्यूयॉर्क में प्रवेश करते ही आपका स्वागत करती है एक महाकाय स्वतंत्रता की देवी 'द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।' चबूतरे सहित लगभग 305 फीट ऊंची, एक हाथ में मशाल और दूसरे में किताब लिए यह तांबे की प्रतिमा लगभग डेढ़ सौ सालों से समुंदर के बीच खड़ी है। फ्रांसीसी शिल्पकार फ्रेडरिक बार्थोल्दी ने इसे बनाया था। यह न केवल अमेरिका और फ्रांस की मुक्ति की आकांक्षा का प्रतीक है, बल्कि मनुष्य के जन्मजात अधिकार की घोषणा करती है और वह अधिकार है स्वतंत्रता का। विचारणीय बात यह है कि ग्रीक और रोमन 'माइथोलॉजी' में स्वतंत्रता का भगवान एक स्त्री है। इसीलिए अमेरिका ने भी स्वतंत्रता का उद्घोष करने की खातिर एक देवी स्त्री को चुना, जबकि विरोधाभास यह है कि मानवीय स्त्री को न यूरोप और न अमेरिका में कोई स्वतंत्रता है। आज तक अमेरिका में एक भी स्त्री राष्ट्रपति नहीं बन पाई।

भारत में स्वतंत्रता की न कोई देवी है और न देव। चारों तरफ इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन स्वतंत्रता का कोई मंदिर नहीं, क्योंकि देवता हो, तो ही मंदिर बनता है। वजह शायद यह होगी कि इस देश में स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ गुलामी से विद्रोह करना नहीं है, यहां स्वतंत्रता को हमेशा आत्मिक मुक्ति के रूप में देखा गया है। वस्तुतः पूरी आत्मिक खोज ही स्वतंत्रता को पाने के लिए है। मनीषी कहते हैं कि मनुष्य अपने गहरे में स्वतंत्र ही है। वह केवल मानता है कि बंधा हुआ है। जैसे ही वह अपने अंतरतम के निकट पहुंचता है, उसे अपनी ज्योति का अनुभव होता है। वह दिव्य हो जाता है। यह एक नितांत व्यक्तिगत विकास और अनुभूति है।

इसीलिए विद्रोह भारतीय मानसिकता का हिस्सा ही नहीं है। यहां के लोग हमेशा एक तरह के स्वीकार भाव में जीते रहे। इसीलिए यह चमत्कार हुआ कि सदियों तक भारत पर लगातार राजनीतिक आक्रमण होते रहे, लेकिन वे आक्रांता भारतीय अस्मिता को जीत न सके।

ओशो कहते हैं कि भारतीय मानस स्वैणतत्व से बना है। स्त्रैण का अर्थ है ग्रहण, शील, सात्विक, शांतिप्रिय, सहज समर्पण करने वाला, रचनात्मक, स्वीकार भाव से युक्त। स्वतंत्रता के भी यही सारे गुण हैं। जो स्वतंत्र है, वह आक्रामक नहीं होता, वह किसी को जीतने की लालसा नहीं रखता। वह इतना तृप्त हो जाता है कि उसे दिखाने की आकांक्षा भी नहीं रहती कि मैं स्वतंत्र हूं। फूल कब घोषणा करता है कि मैं खिल गया! जिसने स्व का तंत्र, स्व का छंद पा लिया, उसे दूसरे को काबू में करने का ख्याल भी नहीं उठता। स्त्री-ऊर्जा प्रकृति के साथ घुल-मिलकर जीती है, क्योंकि वह स्वयं प्रकृति ही है। समूची प्रकृति ही स्वतंत्रता का मंदिर है, अलग से बनाने की जरूरत कहां?

जो सचमुच स्वतंत्र है, वह आक्रामक नहीं होता, वह किसी को जीतने की लालसा नहीं रखता। वह इतना तृप्त हो जाता है कि उसे दिखाने की आकांक्षा भी नहीं रहती कि मैं स्वतंत्र हूं।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

इन्हें क्रांतिकारी नहीं, अराजकतावादी कहिए

बेरोजगार आंदोलनकारी बिना किसी कारण शेख हसीना को दोषी साबित करने पर तुले हुए हैं। चूंकि इन युवाओं ने ही बांग्लादेश में सत्ता गिराई है, इसलिए इन्हें बस अपने को सही साबित करना है। शेख हसीना कट्टरपंथ से निपट रही थीं, जमात व आतंकी गुटों के आगे नहीं झुक रही थीं, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रही थीं और यह सब वहां के कई कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा था। बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, जीडीपी ऊंचाइयां छू रही थी, विशेषज्ञों का अनुमान था कि बांग्लादेश जल्द ही काफी मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, लेकिन आतंकियों को जीडीपी से क्या लेना-देना? उनके लिए तो जीडीपी का अर्थ अलग है। उनकी जीडीपी, यानी जन्नत डेवलपमेंट प्रोग्राम।

देश और सत्ता चलाने के लिए सख्ती और बल, दोनों आपको बराबर मात्रा में चाहिए होता है। शासक अगर हर किसी की सुनने लग जाए और सबके हिसाब से देश चलाने लग जाए, तो फिर उसे कभी गधे पर बैठना पड़ेगा, तो कभी गधे को अपनी पीठ पर लादकर चलना पड़ेगा। लोग तो जाने क्या-क्या कहेंगे, पचास पार्टियां और उनके सैकड़ों सिद्धांत, करोड़ों जनता और उनकी अनगिनत महत्वाकांक्षाएं, जाति-मजहब सबको अपने हिसाब से कुछ न कुछ चाहिए। देश इन सबसे पूछकर नहीं चलाया जाता है। जो एक बड़ी आबादी और देश के भविष्य के लिए अच्छा होता है, शासक को वैसा निर्णय लेना होता है। शेख हसीना वही कर रही थीं। वह चाहतीं, तो कट्टरपंथियों की बातें मान लेतीं, आरक्षण वाली मांग मान लेतीं, लेकिन वह जानती थीं कि भविष्य में क्या सही रहेगा, इसलिए वह अपनी बातों पर अड़ी रहीं। एक अच्छे शासक की यही तो पहचान होती है।

बाकी, जो यह कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और सम्मान के योग्य होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। क्रांति करने वाली जनता बस भीड़ होती है, जिनमें ज्यादातर लफंगे, लुच्चे, नशेड़ी और कामचोर लोग होते हैं। जो ढंग की जनता होती है, वह अपने काम-धंधे में फंसी होती है, देश की जीडीपी बढ़ा रही होती है, टैक्स दे रही होती है और जनहितकारी कार्यों में अपनी भागीदारी निभा रही होती है। शेख हसीना बहुत ही मजबूत औरत हैं और उन्होंने जो भी किया, बहुत अच्छा किया। शासन ऐसे ही किया जाता है। उनके शासन में कमी नहीं थी। जो आज उन पर हंस रहे हैं, वे दरअसल दुनिया की हर अराजकता से खुश होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। ये दुनिया में कहीं भी शांति स्थापित नहीं होने देते, क्योंकि अराजकता से ही इनको ऊर्जा मिलती है।

सिद्धार्थ ताबिश, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
तख्तापलट या क्रांति

इस छात्र क्रांति को हल्के में नहीं ले सकते

देश छोड़कर भाग आईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर हथौड़ा चलता देखकर लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखने वाला कोई भी व्यक्ति आहत हुआ होगा! लेकिन बंगबंधु की विरासत जमींदोज हुई है, तो इसमें उनकी पुत्री का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है? शेख हसीना के राज में बांग्लादेश एकदलीय शासन में बदल गया था। खबर 2021 की है। ढाका की एक अदालत में जब कार्टूनिस्ट अहमद कबीर किशोर को पेश किया गया, तो उनके भाई उनकी स्थिति देखकर सदमे में आ गए, क्योंकि कबीर काफी कमजोर और ठोस-सहमे दिख रहे थे। हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया था। उनका कथित अपराध यह था कि कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कुछ कार्टून सोशल मीडिया पर डाले थे। अदालत ने उनको जमानत देने से छह बार इनकार किया। जमानत मिलने तक किशोर 'द डिजिटल सिक्योरिटी ऐक्ट' (डीएसए) के तहत दस महीने जेल में बिता चुके थे।

यह कहानी सिर्फ किशोर की नहीं है। बांग्लादेश में संपादकों और सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद अक्तूबर 2018 में डीएसए लागू किया गया। आलोचकों का कहना है कि असहमति की आवाज और सरकार की आलोचना को दबाने के लिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया पर नजर रखने वाली ब्रिटेन स्थित संस्था आर्टिकल-19 के मुताबिक, साल 2020 में बांग्लादेश में डीएसए लागू होने के तहत 312 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें 70 पत्रकार शामिल थे।

सवाल यह भी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरोकार कही जाने वाली शेख हसीना के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां लोकतंत्र कितना महफूज रह गया था? अमेरिका, इंग्लैंड समेत तमाम पश्चिमी देशों ने 2024 के चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए थे। मानवाधिकारों का उल्लंघन और प्रेस की आजादी खत्म करने के लिए हसीना सरकार की तीखी आलोचना की थी। यह सब जब हो रहा था, तब बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति और जीडीपी का डंका बजाया जा रहा था। वह डंका इतना तेज बज रहा था कि भीषण गरीबी, चौड़ी होती असमानता की खाई, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही आवाजें दब गईं। शेख हसीना के खिलाफ सुलग रही चिनगारी जब छात्र-युवा आंदोलन के रूप में भड़की, तब उसमें कट्टरपंथी ताकतों की घुसपैठ रोक पाना मुश्किल हो गया! सिर्फ इसी आधार पर बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसका दूरगामी असर पड़ेगा।

हेमंत कुमार, टिप्पणीकार

आवास योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत आगामी पांच वर्षों में तीन करोड़ घरों का निर्माण होगा, जिनमें दो करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में तथा एक करोड़ आवास शहरी क्षेत्र में होंगे. इस निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इस चरण में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च किये जायेंगे. शहरी गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों के आवास पर कुल निवेश 10 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, जिसमें सरकार 2.3 ट्रिलियन रुपये का अनुदान देगी. ग्रामीण आवासों पर केंद्र और राज्य सरकारें 3,06,137 करोड़ रुपये खर्च करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय के प्रांरभ में ही ग्रामीण भारत के हर परिवार के लिए आवास उपलब्ध कराने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया था. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत अप्रैल, 2016 में की गयी थी, जिसके तहत मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था. शहरी क्षेत्र में आवास मुहैया कराने की योजना जून, 2015 में प्रारंभ की गयी थी. अनुदान और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ निर्माण को बढ़ावा देने पर आधारित इस योजना से अब तक करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न और मध्य वर्ग के वैसे सभी परिवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है. शहरी क्षेत्र में तो किराये पर पक्का मकान लेने के लिए भी योग्य आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं. हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो मकान बना पाने की स्थिति में नहीं है. हालांकि पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवास मुहैया कराने या सस्ती दरों पर कर्ज की व्यवस्था कराने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं, पर प्रधानमंत्री आवास योजना अपने लक्ष्य एवं उपलब्धि में अग्रणी है. घर का सपना पूरा होना महज एक सपने का साकार होना ही नहीं है, यह परिवार के लिए एक उपलब्धि और उत्साह का आधार होता है, जो उसे उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रेरित करता है. बीते वर्षों में आवास के अलावा अनाज, रसोई गैस, बिजली, चिकित्सा आदि के लिए भी अनेक कल्याण योजनाएं शुरू की गयी हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, निशुल्क राशन, बिजली में छूट, उज्ज्वला योजना आदि. ऐसी योजनाओं ने गरीब और निम्न आय वर्गीय परिवारों की मुख्य चिंताओं का काफी हद तक समाधान किया है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं. आवास योजना के विस्तार से बड़ी संख्या में घर बनने से सीमेंट, लोहा आदि अनेक उद्योगों को भी लाभ होगा तथा रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च किये जायेंगे.

बांग्लादेश में संकट के पीछे कई ताकतें

प्रो शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित
कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली
santishreepandit@gmail.com

कुछ रिपोर्टों में यह संकेत दिया जा रहा है कि चीन, अमेरिका या पाकिस्तान जैसे सरकारी कारकों की भूमिका हो सकती है. इसके साथ-साथ इस्लामिक आतंकी समूहों और अपने तरह के 'लोकतंत्र' को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे दूसरे तत्वों की भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है. ऐसी रिपोर्टों को इस्लाम विरोधी या अनुदार कह कर खारिज करना उसी तरह खतरनाक हो सकता है, जैसे बिल्ली को देख कर कबूतर इस उम्मीद में आंख बंद कर लेता है कि खतरा अपने-आप टल जायेगा.

बांग्लादेश का हालिया संकट बाहरी हस्तक्षेप तथा चुनाव जीतने एवं लोकतांत्रिक बदलाव लाने में असफल रहे उसके आंतरिक सहयोगियों की भूमिका को इंगित करता है. अवामी लीग सरकार के नाटकीय पतन तथा शेख हसीना के देश छोड़ने से इस क्षेत्र में उथल-पुथल के लगातार जोखिम तथा बाहरी दखल और अंतुरनी गड़बड़ी के खतरे का भी पता चलता है. क्या सड़क पर भीड़ और छात्रों के प्रदर्शन बिना बाहरी समर्थन के हो रहे हैं? अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे ताकतवर दानदाता स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व को पसंद नहीं करते. उनकी तानाशाहों से खूब बनती है और वे अपने हितों को साधने के लिए धार्मिक अतिवाद, यहां तक कि आतंकियों को भी समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं. बांग्लादेश उर्दू थोपने के विरोध में बंगाली होने के अपने धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर पाकिस्तान से अलग हुआ था. बांग्लादेश स्वाधीनता संग्राम के नेता और देश के पहले राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की पाकिस्तान-समर्थक इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हत्या के बाद वहां यह बहस केंद्र में आ गयी कि बांग्लादेश पहले बंगाली है या इस्लामिक.

अमेरिकी पत्रकार और अकादमिक गैरी जे बास की किताब 'द ब्लड टेलीग्राम: निक्सन, किसिंजर, एंड ए फॉरगॉटन जेनोसाइड' (2013) बताता है कि बांग्लादेश अमेरिकी वाणिज्य राजदूत आर्चर ब्लड द्वारा 1971 में भेजे गये एक टेलीग्राम पर आधारित है. उसमें बांग्लादेश जनसंहार पर अमेरिकी विदेश विभाग के रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए लिखा गया था कि अमेरिकी सरकार लोकतंत्र के हनन और भयंकर दमन की निंदा करने में विफल रही, जिसे कई लोग नैतिक दिवालियापन मानेंगे. यह तार आज भी प्रासंगिक है. अंतरराष्ट्रीय दानी एनजीओ की भूमिका पर संदेह स्वाभाविक है. जिस गठजोड़- पाकिस्तान का आइएसआइ, अमेरिका और चीन- पर 1971 के जनसंहार का दोष था, इस बार उसी पर शक हो रहा है. पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च, 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक दमन के साथ हिंदू और बंगाली विरोधी बांग्लादेश जनसंहार की शुरुआत की थी. अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लोग हिंसा को देखकर अचंभित रह गये थे और उन्होंने अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप करने का निवेदन किया. आर्चर ब्लड ने बाद में अपनी सरकार की प्रतिक्रिया को 'भयावह चुप्पी' की संज्ञा दी थी. उसके बाद ही रोष जताते हुए वह तार भेजा गया था. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे चीन से कूटनीतिक संबंध बहाल करने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने की कोशिश कर रहे थे.

विभिन्न मुद्दों, जो कई देशों में भी हैं, पर आंतरिक झंझट बांग्लादेश में शीघ्र ही बहुत ही उग्र और हिंसक हो गया, इसे देखते हुए बाहरी- सरकारी और गैर-सरकारी दोनों- हस्तक्षेप को लेकर चिंता स्वाभाविक है. अधिकतर विश्लेषण में सामान्य तर्क ही दिये जा रहे हैं और अक्सर विदेशी मिलीभगत की संभावना को परे रख दिया जा रहा है. लेकिन, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उचित ही कहा है, किसी भी आयाम को मानना या नहीं मानना अभी जल्दबाजी होगी. कुछ रिपोर्टों में यह संकेत दिया जा रहा है कि चीन, अमेरिका या पाकिस्तान जैसे सरकारी कारकों की भूमिका हो सकती है. इसके साथ-साथ इस्लामिक आतंकी समूहों और अपने तरह के 'लोकतंत्र' को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे दूसरे तत्वों की भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है. ऐसी रिपोर्टों को इस्लाम विरोधी या अनुदार कहकर खारिज करना उसी तरह खतरनाक हो सकता है, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर इस उम्मीद में आंख बंद कर लेता है कि खतरा अपने-आप टल जायेगा. कुछ खबरों में पिनाकी भट्टाचार्य द्वारा हाल के महीनों में भारत विरोधी भावनाएं भड़कने के बारे में बताया गया है. इस व्यक्ति पर तबलीगी जमात का प्रभाव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'पड़ोसी प्रथम' की पहल अच्छा पड़ोस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसका प्रारंभ तब हुआ था, जब दक्षिण एशियाई के नेताओं को 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था. क्षेत्रीय संबंध केवल भारत के प्रयासों पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि पड़ोसी देशों के घरेलू कारक भी अहम भूमिका निभाते हैं. 'इंडिया आउट' का एक चिंताजनक प्रचार चल पड़ा है, जिसे भारत के विरोधी संसाधन देते हैं.

बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक अब उस कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे हैं कि कथित 'शांतिपूर्ण संक्रमण' या 'जनता की जीत' का मामला बहुत जटिल है. पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लाये गये नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैश्विक आलोचना हालिया घटनाओं को देखते हुए अदूरदर्शी साबित हुई है. अब ये आलोचक चुप हैं क्योंकि ऐसी नीतिगत पहलों की दूरदर्शिता स्पष्ट दिख रही है. बांग्लादेश के मसले के पीछे हिंदू विरोध है या भारत को कमजोर करने की सोची-समझी रणनीति, इसे रेखांकित कर पाना कठिन है, पर यह तो स्पष्ट है भारत का आर्थिक, राजनीतिक और भू-राजनीतिक विकास इस क्षेत्र के साथ ठोस संबंधों पर निर्भर करेगा. भारत के सामने अजीब स्थिति है- क्या उसे अपने पड़ोसियों के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करना चाहिए ताकि बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा न हो या फिर उसे दूर रहना चाहिए और उन देशों को अपने मसले स्वयं सुलझाने देना चाहिए? इन दोनों विकल्पों में खतरे भी बहुत हैं. भारत जुड़ाव को 'बिग ब्रदर' के हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे भारत विरोधी भावनाएं बढ़ सकती हैं. दूसरी तरफ, किनारे खड़े रहने से प्रभाव कम हो सकता है, भारत के लिए भी जोखिम बढ़ सकता है और अलग-थलग पड़ने का खतरा भी है.

कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बांग्लादेश के बारे में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था. दिसंबर, 2023 में रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा था कि अगर शेख हसीना चुनाव के बाद सत्ता में आती हैं, तो अमेरिका उनकी सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. उनके कहने का अर्थ यह था कि कुछ साल पहले अरब देशों में हुए प्रदर्शनों की तरह बांग्लादेश में भी स्थिति पैदा की जा सकती है. तब छात्रों का ही इस्तेमाल किया गया था.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

अंतरिक्ष अनुसंधान के अग्रदूत विक्रम साराभाई

जयंती विशेष

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

स्वाभाविक ही विक्रम 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह' कहलाये. वे 1963 में 21 नवंबर को केरल में तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा में देश का पहला रॉकेट लांच कर 'रॉकेट पिता' भी बन चुके थे. दुनिया के महान भौतिक विज्ञानियों में शुमार विक्रम खगोलशास्त्री और उद्योगपति भी थे. वे जीवनभर प्रयासरत रहे कि विज्ञान के विभिन्न प्रयोग आम आदमी के काम आएं, उनका मानना था कि ऐसा नहीं हुआ, तो वैज्ञानिक प्रयोगों की कोई सार्थकता नहीं रहेगी. साल 1975 में भारत ने एक रूसी कॉस्मोड्रोम से 'आर्यभट्ट' उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दुनिया को चकित कर डाला. यह विक्रम की परियोजना की सफलता थी.

देश 24 जनवरी, 1966 को एक विमान दुर्घटना में अपने परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को गंवा कर ठगा-सा रह गया था. उनके रहते हमारा परमाणु कार्यक्रम दुनिया की कई शक्तियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था, जिसके चलते उक्त दुर्घटना को लेकर वह संदेह भी जताया गया. तब यह सवाल गंभीर था कि उनकी जगह किसे दी जाए, जो उक्त कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके. अंततः यह तलाश

विक्रम साराभाई
जन्म- 12 अगस्त, 1919
निधन- 30 दिसंबर, 1971

विक्रम साराभाई पर ही खत्म हुई और मई, 1966 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला. साल 1919 में 12 अगस्त को अहमदाबाद के स्वतंत्रता आन्दोलन को समर्पित एक प्रगतिशील विचारों वाले उद्योगपति परिवार में जन्मे विक्रम अपने पिता अंबालाल व माता सरला देवी की आठ संतानों में से एक थे. उनके माता-पिता वहां 'स्ट्रीट' नामक निजी स्कूल चलाते थे और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा इसी स्कूल से प्राप्त की. गुरुदेव रवीन्द्रनाथ, जे कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरु, सी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, सी एफ एंड्रूज व सी वी रमन जैसी शख्सियतें जब भी अहमदाबाद आतीं, उनके माता-पिता की अतिथि बनती थीं. एक बार तो महात्मा गांधी भी उनके घर में रुके थे. बालक विक्रम का सौभाग्य कि उस पर इन महान व्यक्तित्वों के सान्निध्य का गहरा असर हुआ.

द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत में वे कैम्ब्रिज से अध्ययन कर वापस आये तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु में सर सीवी रमन के शोध छात्र बनकर वैज्ञानिक गतिविधियों को समर्पित हो गये. साल 1945 में वे फिर कैम्ब्रिज गये और 1947 में लौटकर अहमदाबाद में प्रयोग व अनुसंधान का अपना सपना पूरा करने में लग गये. इससे पहले 1942 में शास्त्रीय नर्तकी मृणालिनी से विवाह कर उन्होंने दांपत्य जीवन में प्रवेश कर लिया था. उनकी दो संतानें हैं- मल्लिका व कार्तिकेय. मल्लिका ने कुचीपुड़ी व भरतनाट्यम की नृत्यांगना, मंचों की अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ख्याति अर्जित की है, तो कार्तिकेय दुनिया के अग्रणी पर्यावरण शिक्षकों में से एक हैं.

उनका 30 दिसंबर, 1971 की रात तिरुअनंतपुरम से मुंबई जाने का कार्यक्रम था. वे अपने उन दिनों के सहयोगी एपीजे अब्दुल कलाम से बात कर सोये ही थे कि उन्हें हृदयाघात हुआ और नींद में ही उनका निधन हो गया. उस वक्त वे महज 52 वर्ष के थे. अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को तिरुअनंतपुरम से अहमदाबाद ले जाया गया. उन्होंने समय के साथ अपने योगदानों को लेकर भरपूर प्रशंसाएं व मान्यताएं हासिल कीं. उन्होंने 1947 में अहमदाबाद में जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की थी, वह आगे चलकर भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के उद्गम स्थल के रूप में विख्यात हुई. साल 1962 में उन्होंने शांतिस्वरूप भटनागर पदक प्राप्त किया, तो 1966 में पद्मभूषण. मरणोपरांत उन्हें 1972 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. अगले साल 1973 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने फैसला किया कि सेरेनिटी सागर में एक चंद्र क्रेटर 'बेसेल ए' को साराभाई क्रेटर के रूप में जाना जायेगा. भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के लैंडर (जिसको 20 सितंबर, 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना था) का नाम भी विक्रम रखा गया.

अहमदाबाद में उनके द्वारा स्थापित एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र से भी अब उनका नाम जोड़ दिया गया है. हैदराबाद के थीएम विड्डला विज्ञान केंद्र में स्थित अंतरिक्ष संग्रालय भी उनको ही समर्पित है. साल 2019 में उनकी जन्म शताब्दी पर इसरो ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार भी शुरू करने की घोषणा की. यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान, अनुप्रयोग और अनुसंधान की रिपोर्टिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर इयू के शुल्क का मामला डब्ल्यूटीओ में

चीन की इलेक्ट्रिक कारें अपनी सस्ती कीमतों के कारण यूरोप के कार बाजार पर काले साये की तरह मंडरा रही हैं. चीनी ईवी से बचने के लिए यूरोप ने उन कारों पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है. कोई सुलह होते न देखकर चीन ने डब्ल्यूटीओ में अपील की है. चीन का कहना है कि यूरोपीय संघ के तात्कालिक निर्णय का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है. उसका यह निर्णय विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है. विदित हो कि इस वर्ष जुलाई में यूरोपीय संघ ने चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर लगभग 38 प्रतिशत तक अस्थायी शुल्क लगा दिया था. इससे पहले यूरोपीय आयोग ने एक जांच के बाद पाया कि चीन, यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों को अनुचित रूप से हानि पहुंचा रहा है. चीन का इलेक्ट्रिक कारों पर नया शुल्क यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों की पुष्टि के बाद नवंबर से लागू होगा. चीन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, तकनीक, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के कई मुद्दों पर विवाद रहा है. परंतु ब्रसेल्स के सामने अपनी इलेक्ट्रिक कार उद्योग को सुरक्षा देने के अतिरिक्त पर्यावरण सम्मत विकास की ओर बढ़ने और चीन से झगड़े को रोकने की चुनौती है. यूरोपीय संघ ने सोलर पैनल, पवन चक्कियां और ट्रेन बनाने वाली कंपनियों को दी जा रही सरकारी सब्सिडी की जांच शुरू की है. इस बीच चीन ने यूरोप से आयात की जाने वाली ब्रांडी और पोर्क की जांच शुरू कर दी है. चीन का यह झगड़ा केवल यूरोपीय संघ से नहीं, अमेरिका से भी चल रहा है. अमेरिका ने तो चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर 110 प्रतिशत का शुल्क लगाया है. कनाडा भी ऐसा ही कदम उठाने पर विचार कर रहा है. चीन और यूरोपीय संघ के पास नवंबर तक अपना झगड़ा सुलझाने का समय है. यदि तब तक दोनों के बीच सुलह नहीं होती है, तो अगले पांच वर्षों के लिए अस्थायी शुल्क लागू हो जायेगा.

बोधि वृक्ष

संसार सच है या केवल भ्रम

जिस संसार में हम रहते हैं, उसके तीन आधारभूत दृष्टिकोण है. पहला दृष्टिकोण भौतिकवाद का है जिसमें लोग इस संसार को वास्तविक रूप में देखते हैं. दूसरा वाद है जिसमें दुनिया पूरी तरह एक भ्रम है और तीसरा तीनों दृष्टिकोणों में सबसे बढ़िया है और वाद है कि संसार भगवान की पवित्र संपत्ति है. यह वास्तविक है परंतु प्रत्यक्षीकरण में अस्थायी है. अब यह अवधारणा कि वास्तविकता में संसार ही केवल सत्य है, यह हमारी चेतना को सोचने की अनुमति देता है. जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि संसार ही केवल वास्तविकता है, तो हमारे तथाकथित नैतिक सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं. उसके बाद हम फिर लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, आतंकार और भ्रम जैसी भावनाओं से पीड़ित हो जाते हैं. दूसरे सिद्धांत के अनुसार, संसार कुछ नहीं बल्कि एक भ्रम है. वास्तविकता में इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है. सच वास्तविक है पर पूरा संसार एक भ्रम है. जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए मृत्यु के बाद मुक्ति के बारे में सोचने के लिए यह एक अच्छी प्रेरणा है क्योंकि यदि दुनिया ही एक भ्रम है, तो यह बात मायने नहीं रखती कि हम जीते हैं या मरते हैं. बस यह मायने रखता है कि जितनी जल्दी संभव हो, हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाए, यदि यह दुनिया भ्रम है तो कोई भी पानी और हवा को गंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता. यह बात मायने नहीं रखती कि हम पीछे छोड़कर क्या जाते हैं. हमारा कर्म केवल मुक्ति पाने के लिए है. श्री चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानुजचार्य और माधवाचार्य ने श्रीमद भगवद्गीता और भगवद्गीता में वैष्णव धर्म के सिद्धांत में जो सिखाया है उसकी अलग ही व्याख्या है.

ईशा उपनिषद के अनुसार उन्होंने 'ओम पूर्णम् आदा पूर्णमिदम्' सिखाया है. परम सत्य यह है कि जो भी अस्तित्व में है उन सबका स्रोत है. कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि 'संसार भगवान की संपत्ति है.' यदि हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम स्वामी नहीं बल्कि रखवाले हैं.

- राधानाथ स्वामी

प्रबंध सूत्र

रीलबाजी में समय बेकार न करें

उम्रे-दराज मांग कर लाये थे चार दिन, दो फेसबुक पर कट गये और दो ट्विटर वार में. गौर से देखिए, दिन का कितना बड़ा हिस्सा फालतू रील देखने में निकल जाता है- रील एक के बाद एक. कई घंटे खराब करने के बाद ख्याल आता है कि यह तो कतई बेहूदा काम हो गया. समय नष्ट हो गया. पर दोबारा भी यही होता है. समय सबके पास सीमित है. उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी रीलबाजी में खत्म हो रहा है. समय खराब करने के कई तरीके हैं, मोबाइल के जरिये कई तरीके आप तक पहुंच जाते हैं, जिस प्लेटफार्म से आप रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं. उन्हें पता चल जाता है कि आपको इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है, फिर फिर यूट्यूब या कोई और प्लेटफार्म उन वीडियो की कतार आपके सामने पेश कर देता है, जिनमें आपकी रुचि हो सकती है. धीमे धीमे होता यह है कि उस टाइप के वीडियो की बाढ़ में आप डूब जाते हैं. यह सिलसिला चलता जाता है. फिर आप इसके आदी हो जाते हैं, आदत लत में बदल जाती है. लत किसी आइटम को खाने की हो सकती है, लत किसी किस्म के वीडियो को देखने की हो सकती है.

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

जरा चेक कीजिए, कितना वक्त जा रहा है इन सब में. दिन के बहुत कीमती घंटे इन सब में जा रहे हैं. परम फालतू काम, पर सबसे जरूरी काम. एक लत जैसा हाल है. आप किसी प्लेटफार्म के किसी गार्ड साहब को देखिये, वह मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहे होंगे. आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाइए, वहां के गार्ड साहब भी मोबाइल पर वीडियो देख रहे होंगे. एक आंधी आपके आसपास चल रही है. आसपास क्या, आपकी अपनी जिंदगी में भी चल रही होगी. पर हमें इसका अंदाज नहीं है. हमारे पास उन चीजों के लिए वक्त नहीं है, जो हम करना चाहते हैं. पर हमारे पास दिन में दो चार घंटे उन वीडियो को देखने के लिए है, जो हमारी ही राय में परम फालतू हैं. कोई गृहिणी सब्जी काटते हुए नाच रही है. नाचना अच्छी बात है और सब्जी काटते हुए नाचना तो बहुत बढ़ी कला है. पर ऐसे वीडियो में दो-चार घंटे लगाना विशुद्ध मूर्खता है.

मूर्खता है, पर करनी है क्योंकि इसकी लत लग चुकी है. लत का सबसे पहला लक्षण यह होता है कि लती इसे मानने से इनकार कर देता है कि उसे कोई लत है. रील, वीडियो अगर सीमा में देखे जावें, तो मनोरंजन के माध्यम हैं. पर मनोरंजन ही जीवन हो जाए, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, जिनका धंधा ही मनोरंजन है, पर ज्यादातर लोगों को तमाम काम करने होते हैं. उनके अगर कई घंटे इस तरह के वीडियो रील आदि में जायेंगे, तो समस्या ही है. और, यह समस्या लगातार बढ़ रही है. गौर से देखिए, कहीं आपको भी इसकी लत तो नहीं हो गयी है.

आपके पत्र

भंडारण ही एकमात्र उपाय

देश में महंगाई स्थायी समस्या बन गयी है. त्योहार और विशेष आयोजनों पर फलों-सब्जियों के दाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं. ऐसे में मध्यम और निम्न वर्ग की रसोई से सब्जियों का गायब होना स्वाभाविक ही है. महंगाई को काबू में करने का एक बड़ा उपाय उत्पादकों के लिए निकटतम भंडारण की सुविधा का विस्तार है. अधिक उत्पादन की स्थिति में सब्जियों को सुरक्षित रखकर जरूरत के समय बाजार में उपलब्ध करवाया जा सकता है. इससे मूल्य भी नियंत्रण में रहेगा.

अमृतलाल मारू, इंदौर

प्रभात खबर के 40 वर्ष

प्रभात खबर 14 अगस्त को अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है. यह झारखंड का नंबर वन अखबार है. अखबार की सफलता में संपादक की बेहतर सोच, स्पष्ट नजरिया, खबरों का सही चयन की भूमिका है. अच्छी भाषा शैली और चुनिंदा फीचर लेख, लेख का नियमित प्रकाशन, सनसनीखेज खबर से दूरी और पाठकों के लिए जरूरी सूचनाओं को तवज्जो भी दिया जाना है. यही कारण है कि प्रभात खबर पाठकों की पहली पसंद है और लोगों के जनमानस पर छाया हुआ है.

जीतेंद्र कुमार, रांची